खण्ड-184, अंक-5
गुरूवार, 3 श्रावण, शक संवत् 1879
(25 जुलाई, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 184 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, २५ जुलाई, १९५७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३३३)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असगर अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री बह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री

बुद्धीलाल, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद सुलेमान अहामी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री

यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री

रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य , श्री
लायकसिंह, चौधरी
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २५ जुलाई, १९५७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में अधिगृहीत मकानों का किराया

**१--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि लखनऊ शहर में कितने मकान सरकार ने अधिगृहीत (requisition) किये हैं और उसके लिए उसे कितना किराया वार्षिक देना पड़ता है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--लखनऊ में अधिगृहीत (requisition) किये गये मकानों की संख्या १३ है जिनका वार्षिक किराया २२,६२० रुपया है। उनमें से दो मकानों में सरकारी कार्यालय स्थापित हैं जिनका वार्षिक किराया ६,३०० रु० सरकार देती है। शेष ११ मकानों का किराया वे व्यक्ति देते हैं जिनको कि वे एलाट किये गये हैं।

**२--श्री गेंदासिंह--उक्त मकानों में से १० रु० से २५ रु० के भीतर, २५ रु० से ५० रु० के भीतर, ५० रु० से १०० रु० के भीतर और इससे अधिक प्रत्येक सौ की वृद्धि पर कितने-कितने मकान मासिक किराये के हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--सूचना इस प्रकार है :--

मकानों का किराया प्रतिमास			अधिगृहीत किये गये मकानों की संख्या
१० रु० से २५ रु० तक	..	..	२
२६ रु० से ५० रु० तक	..	..	२
५१ रु० से १०० रु० तक	..	..	२
१०१ रु० से २०० रु० तक	..	..	४
२०१ रु० से ३०० रु० तक	..	..	१
३०१ रु० से ४०० रु० तक	..	..	१
४०१ रु० से ५०० रु० तक	..	..	१
योग	..	..	१३

श्री गेंदासिंह--क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी मुलाजिमों में से कितने मुलाजिम ऐसे हैं जिनके पास इस वक्त मकान नहीं हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--वह तो तीसरे नम्बर का सवाल आयेगा, उसमें मैं अर्ज करूंगा। इसमें यह नहीं है कि कितने सरकारी मुलाजिमों को मकान नहीं मिले।

श्री गेंदासिंह--क्या यह बतलाने की मिनिस्टर साहब मेहरबानी करेंगे कि ये मकान जो ६,३०० रु० के सरकार के जिम्मे हैं, वे इस वक्त किस काम में हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--जैसा कि मैंने कहा कि २ मकान हैं जिनमें दफ्तर हैं सरकारी और इस वजह से उनका किराया सरकार देती है। एक में एलेक्शन आफिस है। उसका किराया २५ रुपये है और दूसरे में एकानामिक ऐन्ड स्टैटिस्टिक्स आफिस है और उसका किराया ५०० रुपये है। इस हिसाब से ६,३०० रुपये उनका किराया हो गया।

श्री गेंदासिंह---क्या कुछ सरकारी कोठियां भी ऐसी खाली हैं जिनमें ये दफ्तर ले जाये जा सकते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है ।

एक दिन में तीन से अधिक प्रश्न पूछे जाने पर आपत्ति

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। हमारे रूल २५ में यह लिखा हुआ है कि एक मेम्बर एक दिन में ३ सवाल से ज्यादा नहीं कर सकता है। लेकिन आज के एजेंडे में ६ सवाल हैं ।

श्री अध्यक्ष---अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के लिए यह नियम नहीं है, तारांकित प्रश्नों के लिए है । शार्ट नोटिस क्वेश्चन्स के लिए कोई लिमिट नहीं है ।

लखनऊ में सरकारी कर्मचारियों को मकान का कष्ट

**३---श्री गेंदासिंह---लखनऊ में वे सरकारी नौकर कितने हैं जिन्हें मकान अब तक नहीं मिल सका है ? उन्हें कितने दिनों से मकान नहीं मिला है और आगे मिल जाने का क्या प्रबन्ध है ?

श्री सैयद अली जहीर---लखनऊ में १ जनवरी, १९५७ से ३० जून, १९५७ तक ३,३०४ प्रार्थना-पत्र सरकारी कर्मचारियों ने मकानों के एलाटमेंट के लिए दिये जिनमें से ४०९ कर्मचारियों को मकान एलाट किये गये। शेष कर्मचारियों को कितने दिनों से मकान नहीं मिले, यह बताना सम्भव नहीं है। खाली मकान उपलब्ध होने पर उन्हें एलाट किये जा सकेंगे ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि ३,३०४ में से जो बाकी लोग रह गये, वह वे लोग हैं, जो कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---उनमें से थोड़े से जरूर ऐसे होंगे जो कम वेतन पाने वाले हैं। मुमकिन है कुछ ऐसे हों जो ज्यादा पाने वाले हों ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि राजधानी में रहने वालों में से सब से अधिक मकानों की कमी उन लोगों को है जो चपरासी वर्ग में से हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---यह सूचना इस वक्त तो मेरे पास नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मन्त्री जी उन कर्मचारियों के बारे में बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने ५७ से पहिले दरख्वास्त दी थी, लेकिन मकान एलाट नहीं हो सके ?

श्री सैयद अली जहीर---यह सूचना तो मेरे पास इस वक्त नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी नौकरों को मकान देने के लिए कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष---नियमों के बारे में आप नहीं पूछ सकते हैं। नियमों को आपको खुद जानना चाहिए ।

श्री गेंदासिंह---सरकार मकानों की कमी को देखते हुए कि बहुत से लोगों को मकान नहीं मिल सके, पूरा करने के लिए क्या सोच रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--इस सिलसिले में सरकार अव्वल तो यह चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं वह खुद मकान बनायें और जहां तक सरकार का ताल्लुक है जितना मुमकिन हो सकता है मकान बना रही है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि लो इन्कम ग्रूप हाउसिंग स्कीम केन्द्रीय सरकार के मश्विरे से हमन चलायी है और इसमें तीन करोड़ के करीब रुपया मुख्तलिफ शहरों में खर्च हुआ है। लोगों को रुपया कर्ज दिया गया ताकि मिडिल क्लास के लोग छोटे-छोटे मकान आठ दस हजार तक की मालियत के बना सकें। यह स्कीम अब भी चल रही है। अभी मैं दिल्ली गया था और वहां बातचीत की थी और हमें उम्मीद हो रही है कि कुछ और रुपया केन्द्रीय सरकार से मिलेगा जो कर्जे की शक्ल में लोगों को देंगे ताकि वह लोग छोटे-छोटे मकान बना लें और उनमें रहने लगें। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन असली दिक्कत यह है कि सीमेंट और लोहे की कमी की वजह से जितने मकान हमारे यहां बनने चाहिये थे, नहीं बन पाये क्योंकि लोगों को सीमेंट और लोहे के मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। बहुत से गवर्नमेंट के काम चल रहे हैं, उन में ज्यादातर सीमेंट और लोहा खर्च हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर को लोहा और सीमेंट काफी मिकदार में नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसके मुताल्लिक बातचीत की गयी है और मुझको उम्मीद है कि लोहे और सीमेंट की हालत कुछ बेहतर हो जायगी और ज्यादा मिकदार में लोगों को मिलने लगेगा।

खाद्यान्न की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी

४--श्री गेंदासिंह**--क्या यह सही है कि भारत सरकार ने जितना अन्न देने का वादा राज्य सरकार को दिया था वह पूरा नहीं हो रहा है और सस्ते गल्ले की दूकानें उचित मात्रा में नहीं खोली जा रही हैं और खुली दूकानों को भी अन्न के बिना बन्द रखना पड़ता है? यदि नहीं, तो महीने में कितने अन्न की आवश्यकता है और पिछले छः महीने से कितना अन्न भारत सरकार से मिला?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं। परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेशन (allot) किये गये गेहूं के बन्दरगाह से वितरण केन्द्रों तक पहुंचने में देर लग जाने के कारण कभी-कभी अन्न की कमी अल्प समय के लिए हो जाती है। ऐसी अवस्था में दूसरे केन्द्रों से गेहूं पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। पिछले ६ महीनों में (जनवरी से जून तक) केन्द्रीय सरकार ने १,४७,००० टन गेहूं राज्य सरकार को प्रदेशन (allot) किया।

५--श्री गेंदासिंह**--क्या राज्य सरकार ने केवल १५ हजार टन अन्न की प्रतिमाह मांग भारत सरकार से की थी? यदि हां, तो यह किस आधार पर?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं।

६--श्री गेंदासिंह**--सारा उत्तर प्रदेश गेहूं के एक ही जोन में होने के बावजूद भी मेरठ और बनारस, जालौन और गोरखपुर, बरेली और देवरिया के भाव में ५० प्रतिशत चढ़ाव उतार क्यों है?

श्री सैयद अली जहीर--मेरठ, जालौन और बरेली ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां गेहूं की पैदावार अच्छी होती है, परन्तु वाराणसी, देवरिया और गोरखपुर कमी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं जहां दूसरे क्षेत्रों से गेहूं ले जाने में दाम स्वाभाविक रूप से बढ़ जाते हैं। देवरिया और गोरखपुर छोटी लाइन पर स्थित हैं इसलिए दूसरे क्षेत्रों से यहां गेहूं व्यापारियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने में कठिनाई होती है और जो थोड़ी बहुत आयात बाहर से होती है, उस से गेहूं के दाम कभी-कभी प्रभावित नहीं होते। भाव में थोड़ा बहुत खिचाव होना अन्न की प्राप्ति को प्रभावित करने के लिए आवश्यक है।

भाव में चढ़ाव ५० प्रतिशत नहीं है। एक भाव की तालिका इस सम्बन्ध में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०९ पर)

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो केन्द्रीय खाद्य मन्त्री श्री अजित प्रसाद जैन बराबर यह कहा करते हैं कि यू० पी० की गवर्नमेंट की जितनी मांग है, वह सब हमने पूरी कर ली, तो क्या यह सही है कि जो कुछ यू० पी० की मांग थी, वह पूरी हो गयी, और वह मांग क्या थी ?

श्री सैयद अली जहीर--इसकी सूरते हाल यह है कि शुरू में जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने वायदा किया था कि जितनी हमारी मांग होगी, उसको वह पूरा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जब उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने यह तजवीज पेश की थी कि हम यू० पी० को गल्ले का जोन बना देंगे ताकि यहां से जितना गेहूं बाहर भेजा जाता है, वह न जा सके। उसके बाद उनका यह खयाल हुआ, हालांकि हम लोगों से बातचीत नहीं हुई थी कि वह जोन बना देंगे तो उसके बाद शायद यहां गेहूं का निर्ख नीचा हो जाय और काफी गेहूं हमारे सूबे को प्राप्त हो सके जिस से कमी बाकी न रहे। मगर १५ जून को जाकर वह जोन बने। उस वक्त तक हमारे यहां से गेहूं काफी बाहर जा चुका था जिसकी वजह से कीमत कम नहीं हुई। तो इस दौरान में फिर उन्होंने यह समझा कि जोन बन जायेंगे तो यहां की जरूरत पूरी हो जायगी, लेकिन इसके साथ ही यह हुआ कि थोड़ी कमी अनाज के आने में हुई। बम्बई और कलकत्ता में दोनों जगह कुछ तो स्ट्राइक हुई और कुछ यह हुआ कि बहुत से जहाज एक दम आ गये और माल उतारा नहीं जा सका जिसकी वजह से यहां गेहूं के आने में देर हुई। लेकिन फिर बाद को उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने वायदा किया कि माल बराबर उतारा जा रहा है, और हमारे सूबे को जो जरूरत होगी उस को वह पूरा करेंगे। अब बहुत काफी मिकदार में हमारे यहां बम्बई, बिजगापट्टम और कलकत्ता से और दो गेहूं के सेन्टर जो उनके कानपुर और इलाहाबाद में हैं, उन गोदामों से हम को मिल रहा है। जुलाई के महीने में तकरीबन २७ हजार टन गेहूं हम को दिया गया है। १०,५०० टन गेहूं हम को पश्चिमी गोदामों से मिल रहा है। अब हम को कोई दिक्कत नहीं है। जो कमी बीच में थोड़े दिनों के लिए हो गयी थी, वह बाकी नहीं रही। अब जितनी भी जरूरत होगी वह पूरा करेंगे।

श्री गेंदासिंह--क्या इस वक्त यह बताना मुमकिन है कि कितनी दुकानें सरकार ने खोल रखी हैं और कितनी फेंक्शन कर रही हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--पूर्वी जिलों में दो तरह की दुकानें हैं। एक तो फेयर प्राइस शाप्स और दूसरी फेमीन रिलीफ शाप्स। तो फेयर प्राइस शाप्स ४६० और फेमीन रिलीफ शाप्स ८०९ हैं और पहाड़ के इलाके में ४८४ शाप्स हैं। कुल दुकानें १,७५३ इस वक्त हमारे सूबे में काम कर रही हैं, जो अनाज तकसीम कर रही है।

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)---क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती अदालतों पर जो फेयर प्राइस शाप्स रखने की व्यवस्था की गयी थी, वह इस महीने के अन्त तक या अगस्त के पहिले सप्ताह तक खुल जायेंगी ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरी इत्तला है कि ज्यादातर जगहों में २ पंचायतों पर १ दुकान खोलने की इजाजत है। अगर वह काफी नहीं होगी, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इजाजत दे दी है कि जरूरत हो तो और भी दुकानें खोल सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--जो १,७०० से ऊपर दुकानें उन्होंने बतलायी हैं वे कब खुली हैं और क्या वे अभी तक जारी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--इनमें ज्यादातर दुकानें, मेरे ख्याल में १,१०० दुकानें, ऐसी हैं जो अर्से से खुली हुई हैं। लेकिन ३-४ सौ के करीब दुकानें गुजिश्ता महीने से और बढ़ी हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री को सूचना है कि पूर्वी यू० पी० की बहुत सी दुकानों पर जहां ३० मन गल्ला वितरित होता था, वह घटाकर २० या १५ मन कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार उसे पूरा करने के लिए क्या कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---एक थोड़ा जमाना बीच का हुआ था जब मुख्तलिफ कारणों से हमारे यहां अनाज नहीं आ सका था और कमी पड़ गयी थी। लेकिन अब कमी पूरी हो गयी है और अब गालिबन हर दुकान से ३० मन गल्ला तकसीम होगा।

श्री गेंदासिंह---भावों की जो चिट्ठी इसमें दी हुई है, क्या उसे उन्होंने गौर से देख लिया है कि बनारस में १६ रुपये मन और मेरठ में १६ रुपये ६ आने मन गेहूं बिक रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, यही सूची दी हुई है। मुझे जाती इल्म तो नहीं है लेकिन जो इत्तला मेरे पास है वह मैंने पेश करदी है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने गल्ला अधिकतर पूर्वी जिलों के लिए दिया है और वह पश्चिमी जिलों में स्टोर हो रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---स्टोर तो मुख्तलिफ जगहों पर होता है। उसमें पश्चिमी जिले भी हैं। जहां कमी होती है वहां भेजा जाता है और वहां वह इस्तेमाल होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---सब से ताजी सूचना के अनुसार यू० पी० के पूर्वी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में कितने ग़ल्ले की माहवार कमी है और कितने की केन्द्रीय सरकार से मांग की है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह कौन बतला सकता है कि माहवार कमी कितनी है। दुकानों से जितना गल्ला ख़र्च हो जाता है उससे कुछ अन्दाजा होता है कि कितनी कमी है। बाज महीनों में यह होता है कि अगर हम ३० मन ग़ल्ला देते हैं तो उसमें से १० मन ही ख़र्च होता है और बाज दफ़ा २९, ३० मन तक ख़र्च हो जाता है। लेकिन मैं यह नहीं बतला सकता हूं कि मनों में कितनी कमी है जिसे हमें पूरा करना है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---गोंडा में कितनी दूकानें खोली गईं ?

श्री सैयद अली जहीर---५, ६ खोली गई हैं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---और खोलने का कोई इरादा है ?

श्री सैयद अली जहीर---१२ दूकानें।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या नयी और पुरानी दूकानों के भावों में भी कुछ अन्तर रखा गया है ? पुरानी दूकानों पर २ सेर १२ छटांक दिया जाता है और नई पर २ सेर ९ छटांक या ११ छटांक दिया जाता है, क्या सरकार को यह मालूम है ?

श्री सैयद अली जहीर---वैसे तो आमतौर पर जो कीमत है वह २ सेर १२ छटांक है। उसूल यह है कि नो-प्राफिटनो-लास के बेसिस पर अनाज दिया जायगा। बाज वक्त यह होता है कि अनाज की ट्रांसपोर्ट में, इधर से उधर लेजाने में, ज्यादा ख़र्च हो जाता है जिसकी वजह से भाव में फर्क हो जाता है।

जिलों के उद्योग, सूचना तथा डेवलपमेंट अफसरों को वेतन मिलने में विलम्ब

****७---श्री बुलाकीराम** (जिला हरदोई)---क्या सरकार जानती है कि सूबे में जिला उद्योग आफिसर, जिला सूचना आफिसर, समस्त ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स, जिला केन डेवलपमेंट आफिसर आदि का वेतन पिछले चार मास से नहीं दिया गया है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---जिला उद्योग अफ़सरों की पोस्टें, इस वित्तीय वर्ष में ३१ अगस्त, १९५७ तक के लिये इसी महीने के द्वितीय सप्ताह के लगभग स्वीकृत की गई हैं। आशा है कि इन पदाधिकारियों का वेतन, जो अभी तक नहीं दिया जा सका है, अब शीघ्र ही मिल जायगा।

जिला सूचना अफ़सरों का वेतन केवल जून, १९५७ का मिलना शेष है। ये पदाधिकारी ३० मई, १९५७ को गजटेड बनाए गए थे। ये लोग जब अपने-अपने "चार्ज सार्टीफिकेट", "सर्विस बुक" और "लास्ट पे सार्टीफिकेट" एकाउन्टेंट जनरल, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करा देंगे, तब एकाउन्टेंट जनरल, उत्तर प्रदेश उनके वेतनों की "पे-स्लिप" जारी करेंगे और उनके वेतन उन्हें मिल जायंगे।

जहां तक ब्लाक डेवलपमेंट आफ़िसरों का प्रश्न है, जो निकट भूत में ही "गजटेड" बनाये गये हैं, इनकी "सर्विस बुकें" अभी पूरी नहीं हैं। इन्हें पूरी कराने तथा एकाउन्टेंट जनरल, उत्तर प्रदेश से इन पदाधिकारियों की "पे-स्लिप" जल्दी से जल्दी जारी कराने के सतत प्रयत्न किए जा रहे हैं।

जिला केन डेवलपमेंट अफसरों के विषय में राज्य सरकार के पास इस सम्बन्ध की कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री बुलाकीराम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला उद्योग अधिकारियों का पद ३१ अगस्त, १९५७ तक होने पर भी उनका वेतन अभी तक क्यों नहीं दिया गया? इस देरी का क्या कारण है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---गवर्नमेंट आफ इंडिया से जब तक इन पदों के लिये रुपया मिलता है उसी वक्त तक उनको कंटीन्यू करने की लिखा-पढ़ी हो रही है। अभी स्वीकृति नहीं आई है। इसलिये देरी हो गयी।

श्री बुलाकीराम---क्या सरकार बतायेगी कि जिला सूचना आफिसरों की चार्ज शीट्स, सर्विस बुक्स, लास्ट पे सार्टिफिकेट को मेनटेन करने की जिम्मेदारी किस पर है? ये कागजात अभी तक क्यों नहीं बनाये गये?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह हाल की ही बात है जबकि इन्हें गजटेड अधिकारी बनाया गया है। उनके पास सूचना भेज दी गयी है कि उनके पद गजटेड हो गये हैं। उसके बाद से अन्य आवश्यक कार्यवाही हो रही है। इस प्रकार से यह हाल ही का मामला है।

तारांकित प्रश्न

*१-२---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---[२९ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*३-४---श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)---[१ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

नैनीताल जिले में विकास योजनायें

*५---श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बतायेगी कि नैनीताल की पट्टी चौगढ़ विश्चूला, चौलसी व मल्लीलौ क्षेत्र में सरकार की ओर से आज तक कौन-कौन सी विकास योजनायें निर्मित की गई हैं?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---इस सम्बन्ध में एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४१०-४१८ पर)

सहारनपुर जिले के ओलापीड़ित क्षेत्रों को सहायता

*६--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि गत ६ अप्रैल को सहारनपुर जिले में जो ओला पड़ा था उससे कितने गांवों को कितनी-कितनी हानि पहुंची है और सरकार कितनी सहायता इन गांवों को देने जा रही है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--सहारनपुर जिले में गत रबी की फसल को ओले से हानि का विवरण इस प्रकार है :

कुल प्रभावित गांवों की संख्या	हानि की मात्रा, गांवों की संख्या		
	४ आने तक	८ आने से कम लेकिन ४ आने से अधिक	८ आना या अधिक
४४०	३२०	२२	९८

जिन गांवों में हानि रुपये में आठ आना या उससे अधिक है उनकी मालगुजारी की वसूली स्थगित है तथा कायदे के अनुसार छूट तथा मुल्तवी के आदेश जारी किये जायेंगे ।

पीड़ित क्षेत्र में २ सस्ते गले की दूकानें खोली गईं तथा गरीबों को पुराने कपड़े बांटे गये ।

आजमगढ़ जिले में विकास-कार्य

*७--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में आजमगढ़ जिले में विकास के कौन-कौन से विशेष कार्य होंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इस सम्बन्ध की विवरण पत्रिका माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी ' ग ' आगे पृष्ठ ४१९ पर)

श्री विश्रामराय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम वर्ष में आजमगढ़ जिले में पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जो कार्य हुये थे उनमें से कौन से पूरे हो गये हैं, कौन से आरम्भ नहीं हुये और कौन से अधूरे रह गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जो तालिका आपके पास भेजी गयी है उसमें यह सब दिया हुआ है ।

अल्मोड़ा जिले के भूमिहीन किसानों को नैनीताल जिले के ढिमरी ब्लाक से हटाया जाना

*८--श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला अल्मोड़ा के दानपुर बारामंडल परगनों व पिथौरागढ़ परगने को जोहार, दारमा, आदि पट्टियों में घोर अन्नाकाल, भूमि की कमी, ओले और भूमि के बह जाने से पड़ रहा है जिससे वहां के ५०० से अधिक परिवार ढिमरी ब्लाक, थाना रुद्रपुर, जिला नैनीताल में रहने को आये हैं ? यदि हां, तो सरकार इन लोगों को बसाने का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चरणसिंह--सिवाय पट्टियात मनसियारी और धारचूला के जो कि तिब्बत की सरहद के पास हैं, जिला अल्मोड़ा में कहीं घोर अन्नाकाल नहीं था । इस जिले के कुछ भूमिहीन परिवार जिला नैनीताल में ढिमरी ब्लाक के सुरक्षित वनों (protected Forests) में अवैध रूप से घुस आये थे । उन्हें वहां से हटा दिया गया है क्योंकि उक्त सुरक्षित ब्लाक में खेती करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती । उन्हें अन्यत्र जमीन देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*९—श्री गोविन्दसिंह विष्ट (अनुपस्थित)—क्या इन लोगों की अर्जियां इस ढिमरी ब्लाक के कुछ राय सिक्खों के आतंक से, जो इन्हें मारने पीटने की धमकियां देकर निकालने तथा स्वयं वहां बसने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने के सम्बन्ध में आई हैं ?

श्री चरणसिंह—इनमें से कुछ लोगों की एक अर्जी सरकार के पास इस आशय की आई है।

*१०—श्री गोविन्दसिंह विष्ट (अनुपस्थित)—यदि हां, तो सरकार इन लोगों की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चरणसिंह—जैसा कि प्रश्न ८ के उत्तर में बताया गया है, इन लोगों को ढिमरी ब्लाक से हटा दिया गया है। अतएव इनकी सुरक्षा का प्रश्न नहीं उठता।

खीरी जिले के ओलापीड़ित क्षेत्रों को सहायता

*११—श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी में तहसील लखीमपुर, निघासन तथा मोहम्मदी में ५ मार्च, १९५७ को होने वाली ओला वर्षा से कितनी हानि हुई है ?

श्री चरणसिंह—५ मार्च, १९५७ को ओला वर्षा से जिला खीरी की तीन तहसीलों के ६२३ गांवों की फसल को हानि पहुंची। २६९ गांवों में हानि रुपये में ८ आना या उससे अधिक हुई।

*१२—श्री सुरथबहादुरशाह—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षति-ग्रस्त क्षेत्रों में उनको क्या सहायता देने का विचार है ?

श्री चरणसिंह—क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में कायदे के अनुसार मालगुजारी में उचित छूट दी जायगी। जिन क्षेत्रों में छूट देने का प्रस्ताव है उनकी मालगुजारी की वसूली स्थगित है। अन्य सरकारी मतालबों में भी उचित छूट या मुल्तवी की जायेगी।

*१३—श्री सुरथबहादुरशाह—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में फसल पूर्णतया नष्ट हो गई है उन क्षेत्रों में खाने तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिये तकावी दी जा रही है ?

श्री चरणसिंह—जी हां। सरकार ने १,२९,००० रु० की धनराशि जिले में तकावी वितरण के लिये स्वीकृत की है जिस में विपत्तिकालीन तकावी भी शामिल है।

श्री सुरथबहादुरशाह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वहां सहायता देने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री चरणसिंह—मैंने अर्ज कर दिया।

उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा निर्धारण में विलम्ब

*१४—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यू० पी० व बिहार प्रदेशों में सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और कब तक यह कार्य समाप्त हो जाने की आशा है ?

श्री चरणसिंह—उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा निर्धारण करने के प्रश्न पर अभी भारत एवं बिहार सरकार से परामर्श हो रहा है। अतः अभी से यह नहीं कहा जा सकता है कि इसको पूरा करने में अभी कितना समय और लगेगा।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय माल मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह परामर्श कितने दिनों से चल रहा है ?

श्री चरणसिंह--बिहार गवर्नमेंट से तो कोई १५,२० वर्ष से परामर्श चल रहा है और भारत सरकार से गालिबन डेढ़ साल से, लेकिन मैं सही नहीं कह सकता।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय माल मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ३७ में एक कमटी इसके लिय बनायी गयी थी और उस कमेटी ने कहा था कि इसके कार्य को आगे बढ़ाया जाय ?

श्री चरणसिंह--मैं इस वक्त इस प्रश्न के सारे इतिहास को पढ़कर नहीं आया हूं लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह बहुत पुराना प्रश्न है और १५, २० वर्ष का है। मुमकिन है सन् ३७ रहा हो या सन् ३८ से रहा हो।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि २० साल से लटके हुये इस सवाल का जल्दी फैसला हो जाय ?

श्री चरणसिंह--दूसरी राज्य सरकार उतनी ही हैसियत की है जितनी कि हमारी राज्य सरकार। इसलिए जब कोई मामला आम तौर से उलझ जाता है तो उसमें देर लगती ही है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जिल्दी तय हो जाय।

श्री सुरथबहादुरशाह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इसके तय होने में इतनी देर क्यों हो रही है ?

श्री चरणसिंह--मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम और बिहार दोनों हम हैसियत हैं, देर का यही कारण है।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--क्या माननीय माल मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सीमा निर्धारण कमीशन ने भी इस सम्बन्ध में अपनी कोई राय प्रकट की है ?

श्री चरणसिंह--शायद आपका मतलब स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन से था। इस तरह का प्रश्न उसके विचार के लिए नहीं पेश किया गया था, यह उसके टर्म्स आफ रेफ्रेंस में नहीं था। यह तो घाघरा और गंगा नदी का मामला है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती रही हैं। दुनिया भर का अब तक जो कायदा रहा है वह यह कि जो डीप स्ट्रीम नदी की हो वही सीमा समझी जायगी। हमारे यहां के रेवेन्यू मैनुअल और बिहार के रेवेन्यू मैनुअल में भी यह नियम है। अब हमारी तरफ से यह कहा जा रहा है कि कोई परमानेंट बाउन्डरी इसकी हो जाय। वह बहुत विवादग्रस्त प्रश्न है, कोई मामूली प्रश्न नहीं है।

*१५--श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--[५ अगस्त, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१६--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--[२९ जुलाई, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिलाधीश, लखनऊ के कार्यालय के अस्थायी चपरासी

*१७--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)----क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिले के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में कितने ऐसे चपरासी हैं जो एक साल से अधिक से सेवा कर रहे हैं तथा अभी स्थायी नहीं हुए हैं ?

श्री चरणसिंह--जिलाधीश, लखनऊ के कार्यालय में ३७ चपरासी ऐसे हैं जिनकी सेवा अवधि एक वर्ष से अधिक है और वे अभी स्थायी नहीं हुए हैं।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय माल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एक साल से अधिक की सेवा होने पर भी वे लोग कन्फर्म क्यों नहीं हुए हैं ?

श्री चरणसिंह---ये सब कन्फर्म वैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि वे जगहें परमानेंट हैं ही नहीं। ३७ में से २५ जगहें तो टेम्पोरेरी हैं। जगहें तब मुस्तकिल की जाती हैं जब यह समझ लिया जाता है कि आइन्दा भी इन जगहों की जरूरत पड़ेगी। केवल १२ जगहें ऐसी हैं जिनको स्थायी हो जाना चाहिए था, लेकिन बोर्ड आफ रेवेन्यू ने अपने एक आदेश से सन् १९५३ में उनको मुस्तकिल होने से रोक दिया था। अब उन्होंने फिर इनको परमानेंट कर देने के लिए रिपोर्ट दी है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे लोग इनमें से हैं जिनकी सेवा ४ या ५ साल से अधिक की है?

श्री चरणसिंह---मैं नहीं जानता था कि मेरे माननीय मित्र को इसमें इतनी दिलचस्पी है। उन्होंने एक साल से अधिक के बारे में सवाल पूछा था, यदि वे चाहेंगे, तो मैं और तफसील में इत्तला मंगवा लूंगा।

*१८-१९---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---[३० जुलाई, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या १७-१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२०---श्री त्रिलोकीसिंह---[२९ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

चार वर्षों से एक ही जिले में रहने वाले डी० एस० पी०

*२१---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कितने D.S.P. ऐसे हैं जिनका तबादला एक जिले से दूसरे जिले में ४ वर्षों से नहीं हुआ है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१५।

अस्थायी जुडीशियल अफसरों को स्थायी करने पर विचार

*२२---श्री भुवनेश भूषणशर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुडिशियल आफिसर्स जिन्हें ८ साल तक काम करते हो गये हैं अभी तक मुस्तकिल नहीं किये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

*२३---श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार ऐसे लोगों को मुस्तकिल करने का विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जुडिशियल अफसरों का यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुछ ऐसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं जो ८ साल से कम के हैं और स्थायी कर दिये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों की सर्विसेज ८ साल से अधिक हो गयीं, उनको अभी तक स्थायी क्यों नहीं किया जा रहा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सन् १९५१ में हमारे यहां २०० से ऊपर जुडिशियल आफिसर्स की तादाद थी और वह अस्थायी थे, सन् १९५१ में हम ने यह तय किया कि उनमें से ६० जगह स्थायी की जायं और दो साल के ऊपर वाले जितने भी जुडीशियल आफिसर्स थे, उन सबके कागजात

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिये गये थे। उनमें से उन्होंने ६० आदमी चुन लिये, वह चाहे दो साल के या तीन, चार जितने भी साल के रहे हों। इसके बाद सन् १९५५ में ६० पोस्ट्स और स्थायी करने की बात तय की गयी और फिर सब के कागजात पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजे गये और उनमें से ६० व्यक्तियों को कमीशन ने फिर चुना। इस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से लोग चुने गये, चाहे उनकी सर्विस उस समय कितनी ही क्यों न रही हो।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि वह इस सम्बन्ध में कोई स्थायी नियम क्यों नहीं बनाते जिससे हर साल निर्णय न लेना पड़े ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह सब काम को देख कर होता है। जब जब समझ में आता जाता है कि अब जुडिशियल आफिसर्स की जरूरत है तब तब इस प्रश्न पर विचार कर लिया जाता है। यह तय नहीं है कि इस वक्त जितने जुडिशियल आफिसर्स हैं, वे हर सूरत में आगे रहेंगे ही।

मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील से चकबन्दी के खिलाफ शिकायतें

*२४--श्री गयूर अली खां (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार के पास जिला मुजफ्फरगनर की तहसील कैराना में चकबन्दी में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में कुछ गम्भीर शिकायतें आयी हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरणसिंह--जिला मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना में चकबन्दी के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रार्थना-पत्र, जिनमें मुख्यत:, नियमों के विरुद्ध कार्य करना, भ्रष्टाचार, चकों का बेतरतीव बनाना इत्यादि आरोप लगाये गये थे, अब तक सरकार के पास आते र हैं। अधिकतर यह प्रार्थना-पत्र उन्हीं विषयों पर होते थे जिनके बारे में रिट (writs) हाई कोर्ट में चल रही थीं।

*२५--श्री ग़यूर अली खां (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री चरणसिंह--उपर्युक्त शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यकतानुसार प्रार्थना-पत्रों में किये गये आरोपों पर पूरी-पूरी जांच काफी कड़ाई से की गयी है और आवश्यक कार्यवाही हुई है। जहां कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप सत्य सिद्ध हुए हैं, वहां उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गयी है। परन्तु अधिकतर आरोप गलत पाये गये हैं।

*२६--श्री गयूर अली खां (अनुपस्थित)---क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि जिन किसानों ने चकबन्दी में हुई अनियमितताओं (irregularities) से असन्तुष्ट होकर रिट दायर किये थे, उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--सरकार को यह सूचना मिली है कि कुछ ऐसे किसानों ने जिन्होंने कि शान्ति भंग करने की चेष्टा की थी उनकी गिरफ्तारी के लिए मैजिस्ट्रेट ने दफा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी कानून के अन्तर्गत वारन्ट जारी किये थे। उन किसानों में से कुछ ऐसे किसान भी थे, जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर किये थे। केवल रिट दायर करने के कारण किसी किसान को गिरफ्तार नहीं किया गया।

झांसी जिले में मऊ व गरौंठा तहसीलों के एस० डी० ओ० का सदर मुकाम मऊ रानीपुर में कायम करने की प्रार्थना

*२७--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार को पता है कि गत वर्ष में जिस समय माननीय माल मन्त्री जी मऊ-गरौंठा तहसीलों का दौरा करने गये थे उस समय वहां की जनता ने उनसे वहां के एस० डी० ओ० का सदर मुकाम मऊरानीपुर में कायम करने के लिए प्रार्थना की थी तथा इस सम्बन्ध में कुछ आवेदन-पत्र भी सरकार के पास आये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसे कोई आवेदन-पत्र सरकार को प्राप्त नहीं हुए और न माल मन्त्री जी को ही इस सम्बन्ध में अब कुछ याद है ।

*२८--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह दोनों तहसीलों की जनता की सुविधा के लिए वहां पर उक्त अधिकारी का सदर मुकाम कब तक कायम कर देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एस० डी० ओ० के सदर मुकाम का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को मालूम है कि अब से १५ साल पहले एस० डी० ओ० साहब का सदर मुकाम वहीं था और अब भी उनकी अदालत की इमारत वहां मौजूद है और वहां से सदर मुकाम झांसी इस लिए हटाया गया था, क्योंकि उस वक्त वहां उनके बच्चों के पढ़ने के लिए कोई हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वहां का १५ साल पहले का इतिहास क्या था यह तो मुझे नहीं मालूम कि वहां कौन एस० डी० ओ० थे, उनके कितने लड़के थे, उनके पढ़ने का क्या प्रबन्ध था, लेकिन जो कुछ माननीय सदस्य कहते हैं, वह शायद ठीक होगा।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्यों कि यह मामला बहुत दिनों से विचाराधीन है, इस लिए क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी वहां पर सदर मुकाम कायम करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जैसा कि पहले भी सदन में कहा जा चुका है कि लोग जरूर इस बात को चाहते हैं कि एस० डी० ओ० का स्थान वहां रहे और एस० डी० एम० के हेड क्वार्टर वहां रहें और इस दृष्टि से वह मऊरानीपुर में होने चाहिए । लेकिन इस सवाल पर गौर भी किया गया, लेकिन वहां जैसी इमारतों की इस काम के लिए जरूरत है वैसी इमारतें नहीं ह और इस वक्त नयी इमारतों के बनाने में काफी पैसा खर्च होगा और आजकल रुपये की जो दिक्कत है, उसका परिचय माननीय सदस्य को भी है । इसलिए इस प्रश्न पर आगे विचार करना अभी कुछ समय के लिए रोक दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि वहां पर जो पुरानी इमारतें मौजूद हैं, और जो इस काम के लायक हैं, वहां पर परगनाधीश का स्थान बना दिया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१५ साल में तो बहुत फर्क हो गया होगा, लेकिन अब जो इमारतें हैं, वे काफी नहीं हैं, जो हैं उनको देख लिया गया है ।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--क्या सरकार विचार करेगी कि इस तरह की इमारतें जो खाली हो गयी हैं और जिनमें एन० ई० एस० ब्लाक्स वगैरह हो गये हैं, वहां पर सदर मुकाम खोल दिये जायं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, इस पहलू से भी हम देख लेंगे ।

लखनऊ तहसील में जमीन के गलत इन्दराज के दावे

*२९--श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील लखनऊ में जमीन के गलत इन्दराज के कितने दावे अदालतों में सन् १९५५-५६ में दायर किये गये ?

श्री चरणसिंह--१,०१० ।

उन्नाव तहसील में चकबन्दी का कार्य

*३०—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले की उन्नाव तहसील में चकबन्दी का कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ?

श्री चरणसिंह—उन्नाव जिले की उन्नाव तहसील में चकबन्दी का कार्य सम्भवतः जून, १९५८ तक समाप्त हो जायगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माल मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तहसील से चकबन्दी का कार्य समाप्त होने के बाद उसी जिले की किस तहसील में कार्य शुरू किया जायगा ?

श्री चरणसिंह—अभी यह निश्चय नहीं हुआ है।

*३१-३२—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—[२७ अगस्त, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या १९-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जिला मुजफ्फरनगर के कैराना राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड द्वारा धन का व्यय

*३३—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या नियोजन मन्त्री बतायेंगे कि कैराना राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड, मुजफ्फरनगर में आज तक कितना धन जनहित में कहां-कहां व्यय किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिला मुजफ्फरनगर के कैराना राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड में, जिसकी स्थापना २ अक्तूबर, १९५६ को हुई थी, जनहित के निम्नलिखित कार्यों के लिए निम्नलिखित धनराशियां खर्च की गयीं :—

(क) ३१-३-५७ तक सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाओं के लिए ऋण के रूप में दी गयी धनराशि ५,००० रु० (विस्तृत ब्योरे के लिए संलग्न विवरण 'अ' देखें)।

(ख) ३१-५-५७ तक उन अनुदानों की धनराशि जो दिये जा चुके हैं (और जिनका कार्य सम्पूर्ण हो चुका है) ४,१४५ रु० (विस्तृत ब्योरे के लिए संलग्न विवरण 'ब' देखें)।

(ग) ३१-३-५७ तक सामाजिक शिक्षा के सम्बन्ध में खर्च की गयी धनराशि—४,९९९ रु० ३ आ०।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४२० पर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—माननीय नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितनी धनराशि कैराना एन० ई० एस० ब्लाक को सरकार द्वारा प्राप्त हुई थी जिसमें से यह धनराशि जो क, ख, ग में बतलायी गई है, व्यय हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसका टोटल तो जोड़ नहीं रखा है। मगर इस तरह है—कार्यकर्ताओं का वेतन ५,३६० रु० १२ आ०, भत्ता महंगाई २,४९५ रु० ७ आने, अनुदान की धनराशि ४,१४५ रु० रेकरिंग और नानरेकरिंग खर्चा १०,५७७ रु० १४ आ० ९ पा० , सामाजिक शिक्षा पर ४,९९९ रु० ३ आ०, सिंचाई साधनों पर ५,००० रु०। टोटल जोड़ लीजिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय नियोजन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आपने यह बताया कि क, ख, ग इसका टोटल १३ हजार १ सौ ४४ रुपया है, इसके अलावा कितनी और धनराशि कैराना एन० ई० एस० ब्लाक को सरकार द्वारा दी गयी थी और उसमें कितनी धनराशि बिल्डिंग और वेतनों के ऊपर और कितनी जनहित के कार्यों के ऊपर थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

कानपुर जिलान्तर्गत अमरौधा विकास क्षेत्र में मजरासिमटिया में कुआं न बनने की शिकायत

*३४--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के अमरौधा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रहरौली घाट के मजरासिमटिया में कुएं के निर्माण के लिये १,००० रु० दिया गया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-- जी हां।

*३५--श्री रामस्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि सरकार को उक्त कुएं के पूरे बन जाने की रिपोर्ट भी दी जा चुकी है जब कि कुआं अधूरा पड़ा हुआ है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-- जी हां।

*३६--श्री रामस्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि उक्त ग्रामवासियों ने जिलाधीश तथा प्लानिंग आफिसर के पास इस सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना-पत्र दिये हैं? यदि हां, तो उन पर आज तक क्या कार्यवाही हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों की ओर से एक शिकायती पत्र १०-४-५७ को जिला नियोजन कार्यालय में प्राप्त हुआ था। पत्र मिलने के बाद उपयोजना अधिकारी अमरौधा द्वारा जांच कराई गई और वास्तविकता का पता चलने पर श्री राम रूप शुक्ल, सभापति को कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में नोटिस दे दिया गया है।

एन० ई० एस० ब्लाक पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर के कार्य तथा व्यय

*३७--श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन० ई० एस० ब्लाक पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर को १९५६-५७ में कितना धन दिया गया, वह किस-किस कार्य में व्यय हुआ और कितना शेष है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सघन विकास क्षेत्र, पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर के लिए वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में, कुल ३,६६,८७२ रु० की धनराशि का प्राविधान विभिन्न मदों में किया गया था, जिसमें से ३,०७,९०९ रु० १० आ० व्यय हुआ तथा ५८,९६२ रु० ६ आ० वर्ष के अन्त में शेष रह गया।

उक्त ३,०७,९०९ रु० १० आ० किन-किन मदों में खर्च हुआ--इसका विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

खर्च की गई उपरोक्त धनराशि के अतिरिक्त १०,००० रु० कृषि उन्नति के लिए तथा ५,००० रु० उन्नतिशील पशु खरीदने के लिए, जिसका प्राविधान माल विभाग द्वारा किया गया था, व्यय हुये।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४२१-४२५ पर)

*३८--श्री रामदास आर्य (अनुपस्थित)--उक्त ब्लाक में कौन-कौन से उद्योग धन्धे जारी किये गये हैं? क्या ब्लाक की योजना में रोजगार दिलाने की भी व्यवस्था है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सघन विकास योजना के अन्तर्गत पुरकाजी में कम्बल बुनाई तथा चमड़े के उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के पश्चात्, सहकारी समितियां बना कर, इन्हीं रोजगारों में लगाने की व्यवस्था है।

आजमगढ़ जिले के पूरबपट्टी ग्राम में अग्निकाण्ड

*३९—श्री विश्रामराय--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्राम पूरबपट्टी, तहसील सदर, जिला आजमगढ़, थाना अहिरौला में मार्च, १९५७ के अन्तिम सप्ताह में भयंकर अग्निकांड की दुर्घटना हुई?

श्री चरणसिंह—जी हां, ग्राम पूरबपट्टी, तहसील सदर, जिला आजमगढ़, थाना अहिरौला में ३१ मार्च, १९५७ ई० के रात में अग्निकांड की दुर्घटना हुई थी।

*४०--श्री विश्रामराय--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने लोगों की, कितनी क्षति हुई?

श्री चरणसिंह—उक्त अग्निकांड से उक्त ग्राम में १२ व्यक्तियों को क्षति पहुंची। उसके आंकड़े निम्नलिखित हैं :--

क्रम-संख्या	नाम व्यक्ति जिसे क्षति पहुंची	क्षति का अनुमान रुपयों में
१	श्री रामपलट राय	१,९२५
२	श्री झूरी राय	७३०
३	श्री भीखम	४००
४	श्री काशी प्रसाद	५९५
५	श्री जगरोपन	५००
६	श्री महंगू	४०८
७	श्री अर्जुन	४०८
८	श्री बलई	१३६
९	श्री मंगरू	४७
१०	श्री मुन्नू	१२०
११	श्रीमती दुइजी	५१
१२	श्रीमती तुलिया	५१

श्री विश्रामराय—क्या माल मंत्री जी बतायेंगे कि इन लोगों को कुछ सहायता भी दी गई?

श्री चरणसिंह—जी हां, सहायता दी गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री जी बतायेंगे कि कुल कितनी सहायता दी गई?

श्री चरणसिंह—मालगुजारी की वसूली रोक दी गई और उस पर विचार हो रहा है कि आया कुछ छूट वगैरह की जरूरत है या नहीं और ३८५ रुपया नकदी सहायता भी दी गई।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आग लगने या ऐसी और किसी आपदा के समय पर जो सहायता दी जाती है उसके लिये जिलों में जो निर्धारित कैलेमिटी फंड होता है, चाहे जितनी बड़ी आपदा हो या आग हो, बढ़ाया नहीं जाता?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, बढ़ाया जाता है अगर जरूरत पड़ती है।

श्री गौरीशंकर राय--आजमगढ़ जिले में इतनी ज्यादा आग लगने पर कितना बढ़ाया गया ?

श्री चरणसिंह--मैं तो इसे ज्यादा आग मान नहीं रहा हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--जिन लोगों की बरबादी अग्निकांड से हो जाया करती है उनके मकान वगैरह के लिये भी कोई विशेष रकम गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित की गई है ?

श्री चरणसिंह--मकान वगैरह के लिये कोई विशेष धनराशि अलग से निश्चित नहीं की जाती। ५ हजार रुपया हर साल हर जिलाधीश को दे दिया जाता है इस गरज से कि कहीं आग वगैरह लगे तो तत्काल सहायता पहुंचा सकें बजाय इसके कि बात-बात के लिये वह गवर्नमेंट को लिखें। उनके पास एक नैचुरल कैलेमिटी फंड भी होता है जो वे फिलेन्थ्रोपिक लोगों से इकट्ठा कर लेते हैं। किसी जिले में कुछ है, किसी में कुछ, यह तो जिलाधीश के अपने इन्टरप्राइज के ऊपर मुनहसिर करता है। रहा मकान बनाने आदि के सिलसिले में तो कहीं-कहीं जहां जंगल नजदीक होता है लकड़ी, फूस आदि देने में सहायता कर देते हैं।

नैनीताल में स्टेडियम बनाने की योजना

*४१--श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार का विचार नैनीताल में देश और प्रदेश के खेलों के प्रोत्साहन के लिये पेविलियन बनाने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। आशा है कि नैनीताल में लगभग २ लाख रुपये की लागत का एक स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम बनने का कार्य पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर आरम्भ होगा।

बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में फीस मुआफी के लिए अनुदान

*४२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की फीस मुआफी के मद में प्रत्येक बाढ़-पीड़ित जिलों को अलग-अलग कितना-कितना अनुदान दिया गया है ?

श्री चरणसिंह--अपेक्षित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४२६ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो रकम जिलों को दी गई है इसके अलावा मांग के अनुसार और रकम भी बाकी है ?

श्री चरणसिंह--फीस की माफी जिस मुद्दत के लिये थी वह तो मार्च, १९५७ के लिये थी और जितना वहां से आया वह रुपया उनको दिया गया। अब किसी जिले विशेष की मांग पड़ी हो तो मैं नहीं कह सकता, उसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

विलीन रियासतों के कर्मचारियों को पेन्शन मिलने में विलम्ब की शिकायत

*४३--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि विलीन रियासतों के कर्मचारियों को समय से पेंशन न मिलने की शिकायतों की जांच करने के लिये वह कोई विशेषाधिकारी या कोई कमेटी नियुक्त करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं ।

आजमगढ़ जिला प्लानिंग विभाग का सड़कों पर व्यय

*४४--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला प्लानिंग विभाग ने गत वर्षों में अर्थात् १९५४, ५५, ५६ तथा ५७ में अब तक किन-किन सड़कों के नव-निर्माण अथवा मरम्मत के हेतु कितना-कितना धन दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इस सम्बन्ध में एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४२७ पर)

*४५--श्री रामसुन्दर पांय-ड-क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिन सड़कों के लिये रुपया दिया गया है वे अब तक बन नहीं पाई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी नहीं । जितना रुपया व्यय हुआ है उतने का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूची में १९५६ में जो धन अम्बारी-दीदारगंज रोड, खुरहट-रानीपुर रोड, कम्हरिया-चन्देसर रोड, मधुवन-दुबारी रोड और अजमतगढ़-अमिला रोड, के लिए दिया गया है और जो धन व्यय हुआ है उसमें से शेष रकम जो निर्धारित की गई है उसके नहीं लगाने का कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--चूंकि पूरा पैसा भी उपलब्ध नहीं था और सम्भवत: वहां कुछ मजदूरों की भी कमी रही होगी उस वक्त लेकिन मैं कह नहीं सकता ठीक तरह से । बाकी जो रुपया होगा वह उनको मिल जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या नियोजन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सड़कें जो बनायी जा रही हैं वह किस विभाग द्वारा बनायी जा रही हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसके लिए नोटिस चाहिए ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)--माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि वहां पर मजदूरों की कमी की वजह से जो रुपया दिया गया उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो सका, क्या यह सच नहीं है कि वहां पर टेस्ट वर्क चालू किया गया था और यह देखा गया कि मजदूर वहां काफी संख्या में उपलब्ध थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैंने निश्चय रूप से यह बात नहीं कही । मैंने कहा कि सम्भवत: मजदूरों की कमी भी रही होगी । वैसे प्लानिंग कमेटी में पैसा भी पूरा नहीं पहुंचा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या नियोजन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस सूची में नम्बर १, ४, ६ और ८ की सड़कों के लिए जो धन दिया गया है उस पर काम शुरू ही नहीं किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जो खाली हैं उनमें तो नहीं ही हुआ होगा ।

नैनीताल जिले की चौगढ़ पट्टी में नरभक्षी शेर का आतंक

*४६--श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि जिला नैनीताल की पट्टी चौगढ़ में जो एक आदमखोर शेर पिछले वर्ष से लगा है वह अब तक कितने नर, नारी और बच्चों को मार चुका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--(१) पुरुष--१०, (२) स्त्रियां--७, (३) बच्चे कोई नहीं।

*४७--श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार की ओर से उक्त आदमखोर को मारने की कुछ व्यवस्था हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उस आदमखोर को मारने के लिये निम्नलिखित प्रयत्न किये गये हैं --

(१) प्रमुख शिकारियों को कई बार लिखा जा चुका है।

(२) शिकारियों को हर प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं और संबंधित पट्टियों में पटवारियों को भी शिकारियों की सहायता लेने के लिये आदेश जारी किये गये हैं।

(३) वन विभाग द्वारा भी उस शेर को मारने के प्रयत्न किये गये हैं।

(४) उस शेर को मारने के लिये ४०० रु० पारितोषिक की घोषणा की जा चुकी है।

(५) फलस्वरूप दो शेर वन विभाग द्वारा और चार शेर शिकारियों द्वारा मारे जा चुके हैं। नरभक्षी शेर को मारने का प्रयत्न जारी है।

*४८-५०--श्री गुप्तारसिंह--[१ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५१--डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)--[२९ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

अलीगढ़ जिले के ग्राम हरसुख की नगरिया में प्राकृतिक प्रक्रिया से हानि

*५२--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार बतायेगी कि गत नवम्बर, १९५६ में अलीगढ़ शहर से ३० मील दूर "नगरिया हरसुख" ग्राम में किसी प्राकृतिक प्रक्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी में भारी दरार पड़ गई और आस-पास के मकान तथा जमींनें खराब हो गई हैं ?

श्री चरणसिंह--जी हां। नवम्बर, १९५६ में अलीगढ़ जिले की तहसील खैर के ग्राम हरसुख की नगरिया में प्राकृतिक प्रक्रिया के फलस्वरूप एक दरार पड़ गई थी जिससे कुछ मकानों की दीवारों में भी दरारें आ गई थीं।

*५३--श्री झारखंडेराय--यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस विषय में पूरा विवरण क्या है और उसकी ओर से ग्रामीणों की सहायता के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चरणसिंह--प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण की जानकारी प्राप्त करने के लिए जियोलोजिकल विभाग के अधिकारियों ने उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया और हरसुख की नगरिया तथा निकटवर्ती ग्रामों की मिट्टी छोटे-छोटे ५ थैलों में अन्वेषण हेतु ले गये। जियोलोजिकल विभाग की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्त प्रक्रिया के फलस्वरूप किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। अतः किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जियालोजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जब इस पर रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी, तो उस रिपोर्ट से इस सदन को भी अवगत करायेंगे ?

श्री चरणसिंह----पर अभी रिपोर्ट प्राप्त तो हो जाय । यह तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ।

श्री अध्यक्ष---लेकिन यह तो सर्टेन है कि रिपोर्ट प्राप्त होगी ।

श्री चरणसिंह---अब यह नहीं कहा जा सकता । गवर्नमेंट आफ इन्डिया का डिपार्टमेंट है ।

*५४---श्री रामदास आर्य---[२२ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किया गया ।]

मन्थली बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स का प्रकाशन

*५५---श्री शिवप्रसाद नागर (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मंथली बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स केवल अंग्रेजी ही में छपता है ? यदि हां, तो वह हिन्दी में क्यों नहीं छपता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मंथली बुलेटिन आफ स्टैटिस्टिक्स का सितम्बर, १९५६ तक का अंक केवल अंग्रेजी में ही छपा था । उस के पश्चात् क्रमशः हिन्दी में भी कुछ तालिकायें छापी जाने लगीं । जनवरी, १९५७ के अंक से बुलेटिन पूर्णतया द्विभाषी कर दी गयी है और सारी सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपती है ।

शाहजहांपुर जिले में रामगंगा के कटाव में आई भूमि के लगान में छूट

*५६---श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला शाहजहांपुर के क्षेत्र जलालाबाद में कुन्डरा-पहाड़पुर, अतरी-निजामपुर, कौलापुर, सोहड़, धिरोला, बिधापुर, कसारी, लालपुर, औरंगाबाद, मनिहार की जमीन दरिया रामगंगा में कटकर बेकार हो गयी है ?

श्री चरणसिंह---जी हां ।

*५७---श्री हरदयालसिंह (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त भूमि के किसानों का लगान माफ करने अथवा छूट देने में सहायता की है ?

श्री चरणसिंह---जी हाँ ।

बांदा जिले में पटवारियों की पुनर्नियुक्तियां

*५८---श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)---क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या १२-२-५३ के सरकारी आदेशानुसार पुराने पटवारी पुनः नौकरी में लिये गये हैं?

श्री चरणसिंह---१२-२-५३ को ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं जारी हुआ। किन्तु सरकारी आदेश संख्या ६५२२/१-ब---१२३७-बी-१९५४, दिनांक २३-१०-१९५४ के आधार पर पुराने पटवारियों को पुनः लेखपाली के पद पर नियुक्त करने का आदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक १२-११-१९५४ को जारी हुआ ।

*५९---श्री जगपतिसिंह---क्या यह सही है कि बांदा, बबेरू, नरैनी की तहसीलों में पुराने पटवारी कुछ लिये गये हैं और कर्बी मऊ तहसीलों में अब तक एक भी पटवारी नौकरी पर नहीं लिया गया ?

श्री चरणसिंह----जी नहीं, बांदा जिले की सभी तहसीलों से पुराने पटवारी नौकरी पर लिये गये हैं ।

श्री जगपतिसिंह--क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि राम अवतार, पुत्र दशरथ, ग्राम सरथुआ को जिसका नम्बर पन्द्रह-सोलह पर है जगह नहीं दी गयी और ४८ नम्बर वाला दूसरा आदमी ढ़ाई साल से काम कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो वैयक्तिक सवाल है और बहुत व्योरे का आप पूछ रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ४-५ वर्ष के अनुभव के बाद वे लेखपालों से ज्यादा मुहब्बत करते हैं या पुराने पटवारियों से ?

श्री चरणसिंह--उनको अपनी बात याद होगी जो उन्होंने सन् १९५३ में कही थी। उन बातों को दृष्टि में रखते हुए मैं लेखपालों से ही ज्यादा मुहब्बत करता हूं।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय माल मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उनको इस बात की सूचना है कि जब से लेखपाल नियुक्त हुए हैं तबसे लेखपालों के खिलाफ पटवारियों की अपेक्षा अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें आयी हैं ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, यह बात नहीं है। उसका सब से बड़ा कारण यह है कि लेखपालों के इतने अधिकार नहीं हैं जितने कि पटवारियों को थे।

बदायूं जिले में सहायक चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत

*६०--श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बदायूं में चकबन्दी योजना को चालू होने के समय से कितने A. C. Os. के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें से कितने A. C. Os. निकाले गये ?

श्री चरणसिंह--जिला बदायूं में चकबन्दी योजना के लागू होने के समय से ३१ मई, १९५७ तक १५ सहायक चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुयीं। उन में से २ सहायक चकबन्दी अधिकारी निकाले गये।

श्री शिवराजसिंह यादव--क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि १३ ए० सी० अोज० जिन के खिलाफ शिकायतें थीं और जिन्हें निकाला नहीं गया, तो वे दोषी नहीं पाये गये या उन्हें माफ कर दिया गया ?

श्री चरणसिंह--निकाले नहीं गये हैं, लेकिन निकाले जाने और माफी के बीच में कई मंजिलें पड़ती हैं जैसे, डिग्रेडेशन, वार्निग और ट्रांस्फर।

मुरादाबाद जिले की हसनपुर तहसील में तकावी का वितरण तथा मालगुजारी में छूट

*६१--श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि पिछले तीन वर्षों में तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद में बाढ़ के कारण कितनी तकावी दी गयी तथा कितना लगान माफ किया गया ?

श्री चरणसिंह--पिछले तीन वर्षों में तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद में बाढ़ के कारण निम्नलिखित तकावी वितरित की गयी तथा मालगुजारी में छूट दी गयी :-

वर्ष	वितरित तकावी	मालगुजारी में छूट	
	रु०	रु० आ० पा०	
१९५४-५५	५०,०००	१६,३२८-१२-९	खरीफ १३६२ फ०
१९५५-५६	८१,०००	१,२९,६९०-१५-६	खरीफ १३६३ फ०
१९५६-५७	१,९०,०००	प्रस्ताव विचाराधीन है	(खरीफ १३६४ फ० ।)

*६२--श्री गुप्तारसिंह--[१ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

बोर्ड आफ रेवन्यू के नवीन अधिकार

*६३--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने बोर्ड आफ रेवेन्यू के अधिकारों को बढ़ाया है ? यदि हां, तो इस प्रकार उक्त बोर्ड को कौन-कौन से नये अधिकार एवं दायित्व प्रदान किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। सरकार ने कर सम्बन्धी विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्रशासन का सभी काम अब बोर्ड आफ रेवेन्यू को दे दिया है। लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर का विभाग भी बोर्ड में मिला दिया गया है। साथ ही डिप्टी कलेक्टरों, जुडिशियल अफसरों तथा स्पेशल रेलवे मैजिस्ट्रेटों की तैनाती, स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति और इन अफसरों को चार माह की छुट्टी प्रदान करने का अधिकार भी बोर्ड को दे दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--बोर्ड आफ रेवेन्यू को यह अधिकार किसकी सिफारिश पर बढ़ाये गये हैं और कब से बढ़ाये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मुझको याद पड़ता है, २६ और २७ जून को इस किस्म की आज्ञा गई है। एक चीज और निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसका अन्तिम भाग डिप्टी कलेक्टरों इत्यादि के सम्बन्ध में है। उसके कुछ पहलुओं पर मैं स्वयं गौर कर रहा हूं और सम्भव है कि हमको इसमें कुछ संशोधन करने पड़ें। मैं ज्यादा ब्योरे में इस समय बतलाने में असमर्थ हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतलायेंगे कि बोर्ड आफ रेवेन्यू के अधिकार टैक्सेशन के मामले व जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के मामले में बढ़ाने से क्या फायदे होंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक लैन्ड रिफार्म कमिश्नर की बात है यह तो एकानामिक कमेटी की सिफारिश थी कि पृथक विभाग रखने की जरूरत नहीं।

जहां तक टैक्स की बात है, माननीय सदस्य को मालूम होगा कि केन्द्र में भी एक सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू हैं और बहुत से फुटकर जितने टैक्स हैं, उसी के अन्तर्गत हैं। तो हम समझते हैं कि एक जगह कर देने से आसानी होगी और किफायत भी होगी, एफिशियेंसी भी होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या बोर्ड आफ रेवेन्यू में कोई टैक्सेशन एक्सपर्ट भी नियुक्त किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उसी किस्म के एक्सपर्ट हैं जिस किस्म के कि सेक्रेटेरियट में आम तौर से रहते हैं और हैं।

कलक्ट्रेट्स के पुनस्संगठन की रूपरेखा

*६४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कलक्ट्रेट्स के पुनर्संगठन की रूपरेखा सदन की मेज पर रखेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कलक्ट्रेट्स के पुनर्संगठन की रिपोर्ट† तथा आदेश-पत्र की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रक्खी है।

---

†प्रतियां छापी नहीं गयीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस प्रकार के रिआर्गनाइजेशन करने का परिणाम अब तक क्या हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हमारा अब तक का तो अनुभव है कि परिणाम बहुत ही अच्छा हुआ है और इसी आशा पर जो माननीय वित्त मन्त्री का भाषण था, उस में कुछ किफायत की आशा भी प्रकट की गयी थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस कलेक्टोरेट रिआर्गनाइजेशन के सम्बन्ध में आदेशों का सेकेन्ड इन्स्टालमेंट कब तक निकल जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस समय तो कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---९ जिलों में रिआर्गनाइजेशन इन्क्वायरी रिपोर्ट निकली है, तो अन्य जिलों की कलेक्टोरेट की कब तक निकल जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, धीरे धीरे और बढ़ाते जायेंगे।

श्री गेंदासिंह----क्या ९ जिले स्केयरसिटी वाले जिले हैं या दूसरे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिले तो स्केयरसिटी वाले नहीं हैं, लखनऊ में स्केयर-सिटी नहीं है।

कानपुर जिले में गंगा की बाढ़ से खरीफ की फसल को हानि

*६५---श्री मुरलीधर कुरील---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले में बिठूर, ईश्वरीगंज, सिंहपुर आदि ग्रामों के आस-पास गंगाजी की गत बाढ़ से खरीफ व रबी की फसल की हानि कितनी व किस अनुपात में हुई है ?

श्री चरणसिंह---कानपुर जिले के बिठूर, ईश्वरीगंज, सिंहपुर आदि के आस-पास के २२ ग्रामों की लगभग २,७६९ एकड़ की फसल को गंगा जी की गत बाढ़ से फसल खरीफ में १२ आने से १४ आने तक की हानि हुई। रबी की फसल साधारण रही और इसमें कोई हानि नहीं हुई।

*६६---श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)---[२९ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

मैनपुरी जिले की करहल तहसील को तोड़ने पर विचार

*६७---श्री नत्थूराम (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी की तहसील करहल को तोड़कर उसे दूसरी तहसीलों में मिलाने का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री चरणसिंह---सरकार के सामने न केवल छोटी तहसीलों को तोड़ने का ही सवाल है बल्कि बड़ी-बड़ी तहसीलों को छोटा करने का प्रश्न भी विचाराधीन है ताकि शासन में आसानी पैदा हो जाय। अतः यह अभी नहीं कहा जा सकता है कि मैनपुरी जिले की तहसील करहल को तोड़ा जायगा या नहीं।

खीरी जिले में नदी के कटाव में आयी भूमि के लगान में छूट

*६८---श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में दरियाबुर्दी से कृषि योग्य भूमि कट जाने के कारण किन-किन गांवों को मुस्तकिल छूट सन् १९५६-५७ में दी गई ?

नोट---तारांकित प्रश्न ६४ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चरणसिंह---खीरी जिले में सन् १९५६-५७ में दरियाबुर्दी से कृषि योग्य भूमि कट जाने के कारण ६८ गांवों को मुस्तकिल छूट दी गई जिसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४२८ पर)

*६९---श्री रामहेतसिंह---[२९ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के सलाना तालाब में डूबे खेतों का लगान

*७०---श्री इन्दुभूषण गुप्त---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के ताल सलोना के किनारे के ग्रामों के कितने खेत जिनका सरकार कृषकों से लगान वसूल करती है अब तक पानी में रहे हैं और उनमें कृषक कोई फसल पैदा नहीं कर सके हैं?

श्री चरणसिंह---आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के ताल सलोना के किनारे के ग्रामों में ऐसे किसी खेत की जो अब तक पानी में रहे हैं तथा कृषक उनमें कोई फसल नहीं पैदा कर सके हैं सरकार ने कृषकों से लगान या मालगुजारी वसूल नहीं की है।

स्टैटिस्टिक्स विभाग में उपभोक्ता भाव (जीवन निर्वाह व्यय) सूचकांक तैयार होना

*७१---श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार के स्टैटिस्टिक्स विभाग में प्रदेश भर का मासिक कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स तैयार किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार के स्टैटिस्टिक्स विभाग में इस समय प्रदेश के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक उपभोक्ता भाव (जीवन निर्वाह व्यय) सूचकांक प्रतिमास तैयार किये जाते हैं। दोनों क्षेत्रों में विशेष अन्तर होने के कारण दोनों को मिला कर एक बनाया हुआ सूचकांक अर्थविहीन एवं भ्रममूलक सा होगा।

रेह का कृषि योग्य भूमि पर प्रभाव

*७२---श्री रामसिंह चौहान (जिला आगरा)---क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश की कितनी भूमि रेह से दब कर खेती के अयोग्य हो रही है?

श्री चरणसिंह---रेह जिस भूमि में होती है उसी भूमि ही में रहती है और किसी अन्य भूमि में फैलकर उसे खेती के अयोग्य नहीं बनाती। अतः यह प्रश्न कि कितनी भूमि रेह से दब कर खेती के अयोग्य हो रही है नहीं उठता।

*७३---श्री रामसिंह चौहान---ऐसी भूमि पर लगान कितना और कब से वसूल किया जा रहा है?

श्री चरणसिंह---यह प्रश्न ही नहीं उठता।

लेखपाल एवं पंचायत राज सेक्रेटरी के पदों को मिलाने का विचार

*७४---श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या सरकार ने कभी लेखपाल एवं पंचायत राज सेक्रेटरी के पदों को एक करने का विचार किया था?

श्री चरणसिंह---जी हां, यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

*७५--श्री जगन्नाथप्रसाद--यदि यह सत्य है, तो उक्त योजना के बारे में क्या निर्णय हुआ ?

श्री चरणसिंह--इस योजना के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

बरौली गुजरा, तहसील आगरा की दरियाबुर्द जमीन

*७६--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बरौली, गुजरा, तहसील आगरा, में कुछ दरियाबुर्द आराजी है ?

श्री चरणसिंह--ग्राम बरौली, गुजरा तहसील आगरा, में २२ एकड़ क्षेत्रफल की दरियाबुर्द आराजी है। ग्राम बिसराना की कोई जमीन दरियाबुर्द नहीं हुई है।

अल्मोड़ा जिले में किसानों को निर्धारित भूमि देने की आवश्यकता

*७७--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अल्मोड़ा जिले में कितने ऐसे हिस्सेदार हैं जिन के पास १०० एकड़ से अधिक, ५० और १०० एकड़ के बीच, २५ और ५० एकड़ के बीच, १० और २५ एकड़ के बीच, ५ और १० एकड़ के बीच और ५ एकड़ से कम जमीन है ?

श्री चरणसिंह--अल्मोड़ा जिले के भूमि सम्बन्धी कागजात बहुत अरसे से दुरुस्त नहीं किये गये हैं। अपेक्षित सूचना एकत्रित तो की जा रही है, किन्तु इसमें, बहुत समय लगेगा। फिर भी वह बिल्कुल ठीक न होगी। सही आंकड़े उसी समय मालूम हो सकेंगे जब अल्मोड़ा जिले में रिकार्ड आपरेशन का कार्य समाप्त हो जायेगा।

*७८--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसने यह निश्चय या निर्धारित किया है कि किसी हिस्सेदार या किसान के परिवार के जीवन निर्वाह के लिये कम से कम कितनी भूमि होनी आवश्यक है ?

श्री चरणसिंह--ऐसा कोई निश्चय या निर्धारण नहीं हुआ है।

फतेहपुर-सीकरी में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड का न खुल सकना

*७९--स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तारीख १ अप्रैल, ५७ से फतेहपुर-सीकरी में खुलने वाले एन० ई० एस० ब्लाक को वहां न खोल कर दूसरी जगहों को प्राथमिकता दी गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--विकास खंड फतेहपुर-सीकरी १ अप्रैल, ५७ को नहीं खोला जा सका। इसका कारण यह है कि कुछ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड जो वर्ष ५६-५७ में खुलने वाले थे और अब तक नहीं खोले जा सके थे, उनको खोलने में प्राथमिकता देना उचित तथा आवश्यक था। इसके अतिरिक्त ११ प्रशिक्षण केन्द्रों के क्षेत्रों को भी विकास में सम्मिलित करने के लिये उन केन्द्रों से सम्बद्ध राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोलना अनिवार्य था। इसलिये उन्हें प्राथमिकता दी गई ।

आगरा जिले के बाढ़ तथा ओला पीड़ित क्षेत्रों को सहायता

*८०--स्वामी विश्वेश्वरानन्द--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले के बाढ़ तथा ओलापीड़ित क्षेत्रों में सरकारी क्या सहायता दी गई है ?

श्री चरणसिंह---आगरा जिले के बाढ़ तथा ओलापीड़ित क्षेत्रों में निम्नलिखित सहायता सरकार द्वारा दी गई---

	बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिये	ओलापीड़ित क्षेत्रों के लिये
१---अहेतुक सहायता ..	५१,००० रु०	१०,००० रु०
२---ऐक्ट १२ के अधीन तकावी	३,१०,००० रु०	१,५०,००० रु०

इसके अतिरिक्त बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खरीफ १३६४ फ० के ५८,७६१ रु० के मालगुजारी की वसूली स्थगित कर दी गई है तथा तहसील किराओली के ८७ ग्रामों में ८५,०९३ रु० की मालगुजारी में छूट दी गई।

ओलापीड़ित क्षेत्रों में रबी १,३६४ फ० में २,२२, ६३६ रु० की मालगुजारी में छूट दी गई। आगरा जिले के बाढपीड़ित क्षेत्रों में मुफ्त वितरण के लिये २२५ कम्बल भी दिये गये।

हरदोई जिले के ओलाग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

*८१---श्री बुलाकीराम---क्या सरकार के पास जिलाधीश हरदोई ने परगना पछोहा, तहसील शाहाबाद तथा परगना बंगर, तहसील हरदोई के गांवों में ओलावृष्टि से हुई क्षति की रिपोर्ट भेजी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---हरदोई जिले में ओला से हुई क्षति के सम्बन्ध में जिलाधीश की प्रारम्भिक रिपोर्ट सरकार को मिल गई है और जिलाधीश को लिख दिया गाय कि जिन खातों में ०-८-० या उससे अधिक क्षति हो उनकी मालगुजारी की वसूली स्थगित रक्खें। अन्तिम रिपोर्ट आने पर मालगुजारी में उचित छूट दी जायगी। जिले के ओलापीड़ित क्षेत्र में २०,००० रु० की तकावी वितरित की गई।

गोरखपुर जिले में अग्नि-पीड़ितों को सहायता

*८२---श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर जिले में बैठवा लिया, गौरा निपनिया गिरहिया, कटहरी तथा सोनबरसा ग्राम में भीषण अग्निकाण्ड हुये हैं जिन में अपूर्णीय साम्पत्तिक क्षति के अतिरिक्त जन्तु हानि भी हो चुकी है ? यदि हां, तो उन स्थानों पर जनकष्ट निवारणार्थ सरकार की ओर से क्या किया गया है ?

श्री चरणसिंह---जी हां, गोरखपुर जिले के बैठवालिया, गौरा निपनिया, गिरहिया, कटहरी तथा सोनबरसा ग्राम में इस साल अग्निकांड हुये हैं जिनमें अपूर्णीय साम्पत्तिक क्षति के अतिरिक्त जन्तु हानि भी हो चुकी है। उन स्थानों पर जो सहायता दीगई है वह निम्नलिखित रूप में है :---

(अ) ग्राम बैठवालिया---इस ग्राम में आग लगने के बाद तुरन्त ही १०० रु० नकद और १०० रु० का गल्ला बांटा गया। छप्पर छाने के लिये खर का भी प्रबन्ध किया गया इसके बाद २,०४० रु० का खर और बल्ली बटवाई गई। पीड़ितों को २,८२५ रु० की तकावी दी गई और मालगुजारी की वसूली स्थगित कर दी गई है।

(ब) गौरा निपनिया---इस गांव का अग्निकांड बहुत ही मामूली था तथा पीड़ितों को जंगल विभाग से खर और बल्ली घर बनाने के लिये दी गई है।

(स) गिरहिया---इस मौजे में पीड़ितों को घर बनाने के लिये खर और बल्ली व १५ रु० फी झोपड़ी के हिसाब से मुफ्त बांटी गई।

(द) कटहरी--इसमें भी जंगल विभाग से पीड़ितों को घर बनाने के लिये ५४० रु० का खर और बल्ली मुफ्त दी गई, इस के अलावा ४३५ रु० तकावी में दिया गया। मालगुजारी की वसूली रोक दी गई है और छूट की कार्रवाई की जा रही है।

(प) सोनबरसा--इस मौजे में भी दूसरे मौजों की भांति जंगल विभाग से खर और बल्ली, पीड़ितों को घर बनाने के लिये मुफ्त दी गई और ४३५ रु० तकावी दी गई।

आजमगढ़ जिले में खुलने वाले राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड

*८३--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के रानी की सराय कस्बे में प्रसार सेवा खंड खुलने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रदेश में इस महीने ६५ नये प्रसार सेवा खंड खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। इनमें से एक रानी की सराय में भी खोलने का इरादा है।

*८४--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ की सदर तहसील में अब तक एक भी प्रसार सेवा खंड न खुलने का क्या कारण है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रसार सेवा खण्ड खोलने के लिये जिला नियोजन समिति ने सदर तहसील क्षेत्र की अपेक्षा जिले के अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है।

प्रांविंशियल सिविल सर्विस के स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए हरिजन विधायकों का कथित डेपुटेशन

*८५--श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)--क्या यह सही है कि हरिजन विधायकों का एक डेपुटेशन मुख्य मन्त्री से अप्रैल, १९५७ में इस आशय का मिला था कि प्रांविंशियल सिविल सर्विस (एग्जीक्यूटिव) के स्पेशल रेक्रूटमेण्ट की परीक्षा में बैठने के लिए हरिजन स्नातकों को द्वितीय श्रेणी के प्रतिबन्ध से छूट दी जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या फैसला हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कोई जाब्ते का डेपुटेशन नहीं मिला था। प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद जिले में कथित दुर्भिक्ष

*८६--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कौन-कौन तहसीलों में दुर्भिक्ष होने के समाचार सरकार के पास आये हैं और सरकार ने उसको रोकने की कौन-कौन सी कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह--जिला इलाहाबाद की किसी भी तहसील में अभी तक दुर्भिक्ष होने की स्थिति नहीं है, और न निकट भविष्य में ऐसी स्थिति होने की आशंका ही है। प्रश्न का दूसरा भाग उठता नहीं है।

पूर्वांय जिलों में रबी की फसल की क्षतिपूर्ति के लिए आदेश

*८७--श्री रामायणराय--क्या सरकार को सूचना है कि पूर्वीय उत्तर प्रदेश में रबी की फसल नाम मात्र को हुई है ?

श्री चरणसिंह--उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा गोरखपुर कमिश्नरियों के ९ जिलों में गत रबी की फसल सन्तोषजनक नहीं हुई। आम तौर से फसल साधारण के मुकाबिले रुपये में १० आना से अधिक नहीं हुई। कुछ क्षेत्रों में उपज और भी कम हुई।

*८८--**श्री रामायणराय**--यदि हां, तो ऐसी दशा में सरकारी देयों की वसूली के स्थगित किये जाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह--इस सम्बन्ध में सरकार ने मई ४, व मई ९, १९५७ को उचित आदेश जारी कर दिये थे।

*८९-९०--**श्री रामलक्षण** (जिला बलिया)--[२९ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

बदायूं जिले के रजपुरा परगने में बाढ़पीड़ितों को सहायता

*९१--**श्री जमुनासिंह** (जिला बदायूं)--क्या सरकार को ज्ञात है कि परगना रजपुरा, तहसील गिन्नौर, जिला बदायूं में विगत वर्ष भारी बाढ़ आयी जिससे सारी खड़ी फसलें क्षति विक्षित हो गयीं ?

श्री चरणसिंह--गत वर्ष, परगना रजपुरा, तहसील गिन्नौर, जिला बदायूं के ८८ गांवों की २६,४२३ एकड़ में से १६,४८७ एकड़ की फसल को बाढ़ से क्षति पहुंची। हानि की मात्रा ४ आने से १६ आने तक थी।

*९२--**श्री जमुनासिंह**--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त परगने में बाढ़-पीड़ितों को पुनर्वास हेतु अब तक क्या-क्या सहायता दी गयी है ?

श्री चरणसिंह--बाढ़पीड़ितों को इस विपत्ति के बाद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जो सहायता दी गयी है, वह संलग्न तालिका में दिखा दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४२९ पर।)

बदायूं जिले के लिए तकावी की स्वीकृति

*९३--**श्री शिवराजसिंह यादव**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बदायूं में १९५६-५७ में बीज की तकावी को छोड़ कर अन्य तकावी बांटने के सम्बन्ध में उसने कितना रुपया और किस-किस महीने में भेजा ?

श्री चरणसिंह--निम्नलिखित तकावी महीनेवार जिला बदायूं में सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी :

वर्ष	माह	स्वीकृत तकावी
		रु०
१९५६	अप्रैल	१२,०००
	मई	२३,४००
	जून	१०,०००
	जुलाई	३५,८००
	अगस्त	कुछ नहीं।
	सितम्बर	५०,०००
	अक्तूबर	३३,२५०
	नवम्बर	७९,५००

वर्ष	माह				स्वीकृत तकावी
					रु०
	दिसम्बर	..	..	..	२,७५,०००
१९५७	जनवरी	..	..	..	३२,०००
	फरवरी	..	..	..	५,०००
	मार्च	..	..	..	४१,२५०
	योग	..	..	..	५,९७,२००

उपरोक्त स्वीकृत तकावी में बीज के लिए दी गई तकावी भी सम्मिलित है, क्योंकि बीज के लिए तकावी पृथक शीर्षक में स्वीकृत नहीं की जाती है ।

*९४--श्री शिवराजसिंह यादव--क्या सरकार बतायेगी कि जिला बदायूं में बीज की तकावी को छोड़कर कितनी-कितनी अन्य तकावी की रकम फरवरी, १९५७ तक बांटी गयी और कितनी रकम मार्च, १९५७ में बांटी गयी ?

श्री चरणसिंह--उपर्युक्त तकावी में से ३,६५,९४१ रु० ६ पा० फरवरी, १९५७ तक व २०,४९५ रु० १५ आ० ६ पा० माह मार्च में वितरित किये गये ।

*९५--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--[२९ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किया गया ।]

बलिया जिले की रसड़ा तहसील में रबी की फसल न होने के कारण सहायता

*९६--श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार को विदित है कि रसड़ा, तहसील (बलिया) की अधिकांश भूमि की रबी की बोवाई विशेष देर में होने के कारण फसल बहुत कम हुई एवं जो कुछ हुई वह भी ओले से विनष्ट हो गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां के किसानों को सहायता एवं सुविधा देने पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह--रसड़ा तहसील, जिला बलिया में रबी की ज्यादातर फसल देर में बोवाई की वजह से कमजोर हुई और कुछ हिस्से में ओले से भी नुकसना हुआ । प्रभावित हिस्से की सरकारी मालगुजारी और तहसील भर में दूसरे सरकारी मुतालबों की वसूली मुलतवी कर दी गई है, माफी मालगुजारी के नक्शे बन रहे हैं और तकावी भी बांटी गयी है ।

*९७--श्री गंगाप्रसाद सिंह--[२९ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किया गया ।]

बनकट, जिला आजमगढ़ में जूनियर हाई स्कूल खोलने का कथित निश्चय

*९८--श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिला अन्तर्गत सगड़ी तहसील के बनकट स्थान पर सन् १९५६ ई० में जिला नियोजन समिति ने जूनियर हाई स्कूल खोलने का निश्चय किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं । इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव जिला नियोजन समिति द्वारा पारित नहीं किया गया है ।

अस्थायी कलेक्शन नायब तहसीलदार

*९९--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलेक्शन नायब तहसीलदारों को जो लगभग पांच साल से अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं उनको कब तक स्थायी बनाने के लिए सरकार विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह---प्रश्न केवल कलेक्शन नायब तहसीलदारों के ही स्थायी करने का नहीं है, बल्कि पूरी योजना के स्थायी करने का है और कलेक्शन नायब तहसीलदारों की सेवा (service) को स्थायी करने का प्रश्न उस समय पैदा होगा, जब पूरी योजना स्थायी हो जायगी।

तराई भावर खाम इस्टेट के काश्तकारों को हक़-हकूक की लकड़ी न मिलने की शिकायत

*१००---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस सीजन में तराई-भावर खाम इस्टेट के काश्तकारों को हक-हकूक की लकड़ी अन्य वर्षों की तरह जंगलात विभाग द्वारा नहीं दी गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---अन्य वर्षों की भांति इस सीजन में भी तराई-भावर खाम इस्टेट के काश्तकारों को हक-हकूक की लकड़ी तराई-भावर वन विभाग द्वारा दी गई और दी जा रही है। कर्मचारियों के गत आम चुनाव के कार्य में व्यस्त रहने के कारण कुछ विलम्ब अवश्य हो गया।

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद जिले की मंझनपुर तहसील में रबी की फसल को क्षति के कारण सहायता के लिए आश्वासन

१---**श्री जवाहरलाल** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मंझनपुर तहसील में गत रबी की फसल में कितना नुकसान हुआ है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या-क्या कदम उठाये हैं?

श्री चरणसिंह---इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर के लगभग ३१६ गांवों में गत रबी की फसल को असमय वर्षा, गेरुई तथा बोवाई में देरी की वजह से ०-६-० से ०-१६-० तक की हानि बताई जाती है। प्रभावित ग्रामों में मालगुजारी में छूट या मुल्तवी कायदे के अनुसार दी जायगी।

२-३---**श्री महीलाल**---[२९ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

हरदोई जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

४---**श्री चन्द्रहास मिश्र** (जिला हरदोई)---क्या सरकार कृपा कर सन् १९५५-५६, १९५६-५७ व १९५७-५८ में हरदोई जिले के उन गांवों की सूची सदन की मेज पर रक्खेगी जिनमें बाढ़ से खेती को नुकसान पहुंचा है?

श्री चरणसिंह---हरदोई जिले में १९५५-५६ में ५१६ तथा १९५६-५७ में ५४७ ग्रामों में बाढ़ से खेती को नुकसान पहुंचा। इन ग्रामों की सूची कार्यालय में देखी जा सकती है। १९५७-५८ में अभी तक हरदोई जिले में बाढ़ नहीं आई अतः ग्रामों की संख्या का प्रश्न ही नहीं उठता।

५---**श्री चन्द्रहास मिश्र**---क्या सरकार कृपा कर बतलायगी कि उक्त ग्रामों में १९५५-५६, १९५६-५७ व १९५७-५८ में सरकार द्वारा क्या व कितनी सहायता प्रदान की गई है?

श्री चरणसिंह--हरदोई जिले के उक्त ग्रामों को १९५५-५६ व १९५६-५७ में दी गई सहायता का ब्योरा निम्न प्रकार है :--

वर्ष			अहेतुक सहायता रु०	तकावी रु०
१९५५-५६	..	..	५००	१,८५,०००
१९५६-५७	..	..	५,०००	२,००,०००

खरीफ १३६३-६४ फसली की मालगुजारी में छूट देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त १९५६-५७ में १०० कम्बल बाढ़पीड़ित ग्रामों में मुफ्त वितरित किये गये तथा ५०० रु० के पुराने फौजी कपड़े भारत सरकार से खरीद कर मुफ्त वितरित किये गये।

१९५७-५८ में अभी तक हरदोई जिले में बाढ़ नहीं आई अतः सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

६--श्री चन्द्रहास मिश्र--[२९ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

कार्यसूची में कम प्रश्न रखने अथवा प्रश्नोत्तर का समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना

श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह देखा जा रहा है कि ५०-६० सवालों से ज्यादा नहीं हो पाते हैं। सवालों की संख्या सूची में बहुत ज्यादा आ जाती है, उसका नतीजा यह होता है कि बहुत से सवाल जो एजेंडे में रहते हैं, वह नहीं आ पाते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि या तो उतने ही सवाल रखे जायं जो हो सकें .....

श्री अध्यक्ष--२३ जुलाई को भी ऐसा ही प्रश्न उठाया गया था। उसका मैंने जवाब दे दिया था। मेरे हाथ की बात नहीं है, माननीय सदस्य अगर बहुत सवाल रखते हैं और कायदे के अनुसार वह ठीक होते हैं तो उन्हें मंजूर करना पड़ता है। पर ये तो छुट्टियों के सवाल हैं, क्योंकि असेम्बली अब तक प्रोरोग नहीं हुई, इसलिए व्यपगत नहीं हुए। ४ महीने से जो प्रश्न पड़े हैं वे सब इकट्ठे हो गये हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि कुछ दिनों के बाद जब ये प्रश्न खत्म हो जायंगे तो आइंदा इतने ज्यादा नहीं रहेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और प्रश्नों के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं कि जिस समय यह एक घंटा मुकर्रर हुआ था उस समय २२८ सदस्यों की संख्या थी और आज ४३१ सदस्यों की संख्या है और इतनी संख्या में .....

श्री अध्यक्ष--तो आप यह चाहते हैं कि दो घंटे रख दिये जायं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--या तो इसके समय को रोजाना के लिये बढ़ा दिया जाय, या अल्टरनेट डेज पर .....

श्री अध्यक्ष--नियमों का जब प्रश्न आवे तो उस वक्त आप सुझाव दे सकते हैं। नियमों की कमेटी बन चुकी और उसने रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। जब एक दो दिन में वह सदन के सामने आ जायगी उस समय कुछ संशोधन उपस्थित करना चाहें तो कर दें।

†कतिपय विधेयकों के लिए कार्य परामर्श समिति द्वारा समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव— (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—श्री शिवप्रसाद ने अपना प्रस्ताव पेश कर दिया था जो इस प्रकार है कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों के संबंध में कार्य परामर्श समिति द्वारा प्रस्थापित समय निर्धारण से सहमत है :—

(१) उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७।

(२) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

(३) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७।

(४) उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण) (उपबन्ध) विधेयक, १९५७ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

समय निर्धारण की सूचना नत्थी 'ख' में दी हुई है जो कल पढ़ कर सुना दी गई थी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संशोधन विधेयक के मूल अधिनियम की प्रतियां न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, अभी जो बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की सिफारिश स्वीकार की गई है उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अमेंडिंग बिल्स आते हैं उनके प्रिंसिपल ऐक्ट्स के मिलने में बड़ी दुश्वारी होती है। वह न तो लेजिस्लेचर लाइब्रेरी में मिलते हैं और न बाजार में मिलते हैं। इसलिये ऐसी व्यवस्था कर दें कि जब अमेंडिंग बिल्स आयें तो प्रिन्सिपल ऐक्ट भी सदस्यों को टेबिल पर रख दिये जायं ताकि अमेंडमेंट्स भेजने में सहूलियत हो।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इतने प्रिंसिपल ऐक्ट्स नहीं मिल सकते हैं। मुझे भी दिक्कत होती है। एक आध ही अपटूडेट मिल पाते हैं। जिस वक्त बिल्स बंटते हैं मेम्बर्स अपने पास रखते नहीं हैं। जो संशोधन होते हैं वह अलग होते हैं और पुराना ऐक्ट अलग होता है इसलिये गड़बड़ी हो जाती है। मैं इतना कर सकता हूं कि हर एक पार्टी के लिये यह सम्भव हो सके कि उनके नेता के पास एक एक कापी भिजवा दूं और उसका इस्तेमाल आपस में कर सकें या कम होंगी तो दो एक नेता को दे दूंगा, वह आपस में इस्तेमाल कर लें।

श्री त्रिलोकीसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने तो गुजारिश की थी कि वह यहां रखवा दी जायं।

श्री अध्यक्ष—हां, यह हो सकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—ऐसी सुविधा ट्रेजरी बेंचेज वालों को भी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यह तो सभी के लिये होगी।

१९५७-५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद—(क्रमागत)

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बजट जो किसी हुकूमत के सामने पेश होता है, उसका मंशा यह होता है कि हमारे सामने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†२४ जुलाई, १९५७ की कार्यवाही से क्रमागत।

[श्री सुल्तान आलम खां]

आने वाले एक साल का प्रोग्राम रखा जाय और उस बजट के अन्दर हुकूमत के इरादे और ख्वाहिशात की एक झलक पाई जाती है। अगर उस उसूल पर इस बजट को जांचने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि हमें यह मानना पड़ेगा कि बजट में इस बात की कोशिश की गई है कि हम वेलफेयर स्टेट की तरफ आगे कदम बढ़ायें और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी हमारे यहां कायम हो।

मैं जानता हूं कि यह बजट एक घाटे का बजट है और पिछले सालों के बजट भी घाटे के तैयार होते रहे हैं। इस बजट में ११ करोड़ रुपये का घाटा है और उसमें से दो करोड़ रुपया इस सूरत से पूरा करने की कोशिश की गयी है कि कुछ बचत की जायगी और इसके अलावा कुछ टैक्सेज लगाये जायंगे। लेकिन टैक्सेज और लगाये जाने में इस बात का खयाल रखा गया है कि उसका बोझ गरीबों पर न पड़ने पाये और इसके अलावा जो मौजूदा टैक्सेज हैं उनमें जहां तक मुमकिन हो सके रिलीफ़ दी जाय। यह सही है कि इस सब के बावजूद सिर्फ़ दो करोड़ का घाटा बजट में पूरा हो सकेगा और ९ करोड़ की रक़म को हमें कहीं और तलाश करना पड़ेगा। वित्त मंत्री का खयाल है कि ९ करोड़ की रकम बजाय इसके कि हम कहीं से कर्ज़ लें, जिसे गवर्नमेंट आफ इंडिया पसन्द नहीं करती है, उसके लिये हमें स्माल सेविंग्स ड्राइव करना पड़ेगा। यह सही है कि जो हमारा बजट है वह हमारी जो पांचसाला योजना है उसका साल ब साल का डिटेल है। पांच साला योजना कोई एक पार्टी का प्लान नहीं है, वह एक नेशनल प्लान है जो नीचे से बनाई गई है और जब तक हम सब लोग मिल कर उसमें अपना पूरा सहयोग न दें उस वक्त तक वह सफल नहीं हो सकती। इसलिये जब हमें ९ करोड़ रुपये के घाटे की जरूरत पड़ेगी तो स्माल सेविंग्स ड्राइव हमें करना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि उसमें कोई पार्टी का सवाल न रख कर अगर हम सब अपना सहयोग दें तो इस घाटे के बजट को सरप्लस बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो रेवेन्यू रिजर्व फंड से बार-बार रुपया लेकर घाटा पूरा किया जाता रहा है उससे अब काम नहीं बनेगा। वह फ़ंड तो लड़ाई के जमाने में जब अंग्रेजों ने तमाम कैपिटल काम बन्द कर रखे थे और उनकी मंशा यह थी कि लोग फौज में भर्ती हों इसलिये जो रुपया कैपिटल वर्क्स का बचा था उसका एक फंड उन्होंने कायम कर दिया था जिससे हम बराबर रुपया लेते रहे हैं। अब हालत यह है कि इस साल और अगले साल के बजट में हम भले ही कुछ रुपया ले लें लेकिन फिर हमारा वह फंड भी खत्म हो जायगा और तब हम बड़ी परेशानी में पड़ जायंगे। इसलिये एक बुनियादी पहलू यह पैदा होता है कि हमारी जो दूसरी पांच साला योजना है उसको हमें एग्जामिन करना पड़ेगा।

जनाबवाला, पहली पांच साला योजना चली और खत्म हो गयी। दूसरी का भी दूसरा साल है जो इस बजट के साथ-साथ शुरू हो रहा है। दूसरी पांच साला योजना में जो कुछ किया गया है और जो कुछ करना है वह बहुत जरूरी है, इसके मुताल्लिक मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन जिन हालात से हम गुजर रहे हैं और जिन फाइनेन्शयल डिफिकल्टीज में हमारा मुल्क मुब्तला है उसको देखते हुए मैं तो यह समझता हूं कि यहां या वहां, पोसमोल तरीके पर खर्च कम करें या बहुत सी स्कीमें जिन पर हमारा रुपया खर्च हो चुका है उनको बन्द करें। बेहतर यह होगा कि हम प्लान को कट कर दें या उसे स्प्रेड ओवर कर दें इसलिये कि हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें जो दिक्कत और मुश्किलात के बायस करनी पड़ रही हैं वे ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिये लेकिन गवर्नमेंट के हाथ टाइट हैं, उसके पास कोई आल्टर्नेटिव नहीं है इसलिये उसे ऐसा करना पड़ रहा है।

अभी दो एक दिन पहले की बात है कि प्रान्तीय रक्षक दल को खत्म करने का फैसला हुआ है। वह कई साल से इस सूबे में काम कर रहा है और उसके मुताल्लिक मैं समझता हूं कि किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं कि प्रान्तीय रक्षक दल एक अच्छा इन्स्टीट्यूशन था और अगर अच्छा नहीं था तो हमने उसे इतने दिन चलाया क्यों? आज इतने दिन तक चला चुकने के बाद उसे बन्द कर देने से मैं समझता हूं कि इससे लोगों के विश्वास को एक धक्का लगेगा। अगर हमको किसी काम को रोकना है तो हम मजबूर न करें गवर्नमेंट को कि वह सिर्फ़

एकोनामी की खातिर वैसा करे, बल्कि वह प्लान की ओवरआल पिक्चर देखे कि उसे कट कर दिया जाय या फैला दिया जाय। मेरे खयाल में यह ज्यादा बेहतर होगा।

परसों से बजट पर जो बहस हो रही है मैंने उसे बहुत गौर से सुना और कुछ तकरीरें जब मैंने सुनीं तो ताज्जुब से अपनी आंखों को मला। मैं सोच रहा था कि वाकई अगर इतनी बातें जो इस ऐवान में कही जाती हैं किसी हकूमत के लिये सही हो सकें तो फिर वाक़ई वह हुकूमत नहीं है और वह वजारत की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरा यह यक़ीन है और मैं बगैर किसी खौफ के कह सकता हूं कि यह बात नहीं है। मैं मानता हूं कि करप्शन है, वेस्टेज भी है और बहुत सी दिक्क़तें व दुश्वारियां जो एक नए मुल्क में होती हैं वह इस सूबे में भी हैं, लेकिन जिस तरीके से वह एवान के सामने रखी गयी हैं वह ठीक नहीं और इसके साथ-साथ जो उनका इलाज तजवीज किया गया है वह इलाज भी ज्यादा बदतर किस्म का है।

इसी हाउस के सामने बहुत सी तजवीजें सामने आयी हैं। कहा गया कि बिल्डिंग्स बनाई जायं और लीडर आफ अपोजिशन की तनख्वाह मुकर्रर की जाय, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन हो सकता है? आज हमने एक फैसला ले रखा है और वह यह है कि हमको इस प्लान के जरिये से मुल्क को आगे बढ़ाना है तो उस प्लान के लिये कहीं से पैसे का इन्तजाम करना पड़ेगा और उसके लिये हमको किफायत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यह सोच लें कि इस प्लान को चलाना नहीं है और मुल्क को तरक्की नहीं देनी है तो हम बेशक ऐसा कर सकते हैं और जिस सूरत से अभी तक देश में रहते चले आये हैं उसी तरीके से रहते चले जायं। लेकिन अगर इस प्लान को चलाना है तो पैसा लाने के लिये सही तरीके से हमको दिमाग से सोचना पड़ेगा।

मुझे इस बात की खुशी है कि इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस बात का एलान किया कि सन् १९५८ से जो गल्ले पर टैक्स लगता है वह सिंगल प्वाइन्ट टैक्स कर दिया जायगा। मैं चाहता तो यह था और मेरी गुजारिश यह थी कि वह फौरन कर दिया जाता मगर उन्होंने बतलाया कि कुछ ऐसी दिक्क़तें हैं जिससे वह फौरन नहीं किया जा सकता। मैं यह चाहता हूं कि गल्ले पर टैक्स नहीं लगना चाहिये और गल्ले पर टैक्स न लगने की गवर्नमेंट आफ इंडिया की भी राय थी लेकिन वह नहीं हो सका और टैक्स लगा और गवर्नमेंट इसके लिये राजी हो गयी। मेरी गुजारिश यह है कि टैक्स सिंगल प्वाइन्ट जल्दी से जल्दी होना चाहिये और जो एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्क़तें हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये।

मेरी गुजारिश यह है कि जैसा मैंने शुरू में कहा कुछ दिक्क़तें हैं, तो उनके लिये कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन होना चाहिये जिनसे कुछ नफा हासिल हो सके। हम किसी चीज को बुरा कहें और उसके साथ ही कंस्ट्रक्टिव प्रोपोज़ल उसके लिये न रख सकें तो वह एक तरह से कन्फ्यूजन पैदा करने वाली चीज होगी। पहले ही हमारा सूबा बहुत बड़े कन्फ्यूजन से गुजर रहा है। अगर इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश नहीं की गई तो इससे दुश्वारियां और बढ़ेंगी। इससे किसी एक पार्टी का इन्टरेस्ट जियोपरडाइज नहीं होगा बल्कि सभी पार्टीज के इन्टरेस्ट में यह चीज नहीं जायगी।

इस सिलसिले में मैं चन्द सजेशन गवर्नमेंट के सामने रखना चाहता हूं। कुछ दुश्वारियां ऐसी हैं, रेड टेपिज्म के कवायद और रूल्स ऐसे हैं कि जिनमें कभी कभी हम ऐसे जकड़ जाते हैं कि बावजूद इसके कि अगर वाक़ई हम काम भी चाहें तो नहीं कर सकते हैं। मेरे नज़दीक भी एक ऐसा केस आया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक मुलाजिम था। उसने ३० साल तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सर्विस की, लेकिन वह ३० साल तक टेम्पोरेरी रहा। ३० साल के बाद जब वह हटा तो उसने रिप्रिज़ेन्टेशन दिया, लेकिन ३० साल तक काम करने के बाद भी न उसको पेन्शन मिली और न कोई और रिम्युनरेशन ही मिला। मैंने भी इसमें कुछ कोशिश की लेकिन यही कहा गया कि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल्स बने हैं जिनकी वजह से पेन्शन उसको नहीं मिल सकती। उसको एक किस्म से कम्पन्सेटरी अलाउन्स दिया जा सकता था लेकिन मालूम यह हुआ कि वह रूल्स रिवाइज हो गये अब उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं

[श्री सुल्तान आलम खां]

हैं। तो यह तमाम पुराने रूल्स और रेग्युलेशन्स जिनके तब्दील होने की जरूरत हो उनको तब्दील किया जाय, लेकिन इसका ख्याल रखा जाय कि रूल्स और रेग्युलेशन्स जो बनते हैं वे इन्सान के लिये, सोसाइटी के आराम के लिये बनते हैं। उनकी प्राबलम्स को हल करने के लिये बनते हैं लेकिन कोई रूल्स रेग्युलेशन्स ऐसे हैं जो इसके बरअक्स हैं तो उनको कायम नहीं रहना चाहिये।

जनाबवाला, मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क इस वक्त बड़ी भारी एमरजेंसी से गुजर रहा है। आज हमारे सामने रोटी का सवाल है, कपड़े का सवाल है, ऐम्प्लायमेंट का सवाल है, रेडटेपिज्म का सवाल है, लेकिन इन तमाम चीजों में हमें प्रायरिटी रखनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें बड़ी भारी दुश्वारी होगी। आज गवर्नमेंट की यह कोशिश है कि वह हर फण्ड को टैकिल करे। मैं यह अर्ज करूंगा कि जो आज कन्फ्यूज़न फैला हुआ है वह इसी वजह से है कि हमने अपनी ऐक्टीविटीज़ को हर फ्रन्ट पर फैला दिया है और वह इतना बढ़ गया है कि उसको हम कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक प्रायोरिटी कर ली जाय कोआर्डिनेशन कर लिया जाय तो सुभीता हो सकता है। अगर हम प्रायोरिटी के उसूल से देखें तो हमें ऐजूकेशन को सब से आगे रखना होगा। हमारी एजूकेशन पिछले दो सालों से अच्छी हालत में नहीं है उसको रिओरियन्ट करने की जरूरत है। हर तरफ से आवाज़ भी इसी की है। डिटेल में तो मैं इसको इस वक्त बयान नहीं कर सकता लेकिन अगर ऐजूकेशन के मामले को ले लिया जाय और उसका बन्दोबस्त कर लिया जाय तो बहुत सी हमारी दुश्वारियां दूर हो सकती हैं।

यह भी कहा गया कि आफीसर करप्ट हैं। मैं समझता हूं कि करप्ट लोग भी हैं, लेकिन साथ साथ यह भी समझता हूं कि सबके लिये स्वीपिंग रिमार्क दे देना भी मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि इस हुकूमत को अगर कोई सब से बड़ा क्रेडिट मिल सकता है तो वह जेनरल इलेक्शन्स का मिल सकता है जिसमें बड़े भारी करप्शन होने की गुंजाइश होती है। पिछली दफा जो डिबेट हुई उसमें हर तरफ से यह आवाज बुलन्द की गयी कि यहां जो फ्री और फेअर जनरल इलेक्शन्स हुए हैं उनकी मिसाल यहीं नहीं, दुनियां में नहीं मिल सकती। इसलिये अधिकारियों के लिये ऐसी बात कह देना ज्यादा अच्छा नहीं मालूम होता है। जब हमें अपनी फूड प्राब्लम को हल करना है, हम इन तमाम आफिसरों को हटा कर दूसरे रक्खें तो काम नहीं चल सकता। हमें उन्हीं को ठीक करना है। हमें उन्हीं के साथ हमदर्दी रख कर, उन्हीं के कोआपरेशन से इन कामों को पूरा करना है, मैं समझता हूं इस तरह से हमें ज्यादा कामयाबी हासिल हो सकती है। पार्टी क्वेश्चन को अलग रख कर हमें अपनी खाने कपड़े आदि की प्राबलम्स को हल करना है। किसी के पास अलादीन का चिराग तो है नहीं कि जादू से किसी भी काम को पूरा कर दिया। ये नेशनल वर्क्स तब तक हल नहीं हो सकते जब तक कि सभी पार्टीज इसमें कोआपरेट न करें, सर्विसेज कोआपरेट न करें। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर हम नेशनल इंटरेस्ट की हर चीज को हमदर्दी से देखें और कोआर्डिनेशन से काम करें, कांस्ट्रक्टिव सजेशन्स दें तो हमारी जो प्राबलम्स हैं वे जल्द ही हल हो सकती हैं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये बजट को गौर से देखने के बाद मुझे काफी निराशा हुई है। उधर से कुछ माननीय सदस्यों ने वित्त मंत्री जी की नीयत की सराहना की है लेकिन संभवतः वे इस बात को भूल जाते हैं कि सामाजिक जीवन में नीयत का कोई स्थान नहीं होता है बल्कि परिणाम का जो मूल्य है उसका अधिक स्थान होता है। मैं यह दावे के साथ कहूंगा कि परिणाम का मूल्य जो है वह वित्त मंत्री जी और उनकी सरकार के खिलाफ है।

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा अपने बजट भाषण में प्रथम पंच वर्षीय योजना की सफलता के बारे में बहुत दावा किया है। उन्होंने

उसकी कामयाबी के बारे में खुद अपनी सराहना की है और अपनी सरकार की सराहना की है । इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो कामयाबी हुई है वह केवल इस तरह से हुई है कि अपने मुंह से अपनी तारीफ वित्त मंत्री महोदय तथा उनकी सरकार के लोगों ने कर ली है । लेकिन आम जनता उसकी सराहना और उसकी तारीफ नहीं कर सकती ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि प्रदेश की समस्या इससे काफी हल कर ली जायगी, लेकिन, श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सदन के आदरणीय सदस्यों को बतलाऊं कि इस सूबे की कुल संख्या का ७४ फीसदी कृषि के ऊपर निर्भर है यानी ७४ फीसदी लोगों का जीवन निर्वाह खेती की उपज पर होता है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जब हम देखें, उसका विश्लेषण करें तो हमको यह नतीजा मालूम होता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल खर्च होने वाली पूंजी २५३ करोड़ है । उसमें से, श्रीमन्, देखा जाय तो खेती के ऊपर कुल खर्च होने वाली पूंजी ११.७८ करोड़ है यानी कुल खर्च होने वाली पूंजी में से ५ फीसदी से कम खेती की उन्नति करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूंजी लगायी जायगी । करीब ७४ फीसदी जनता के जीवन स्तर को उठाने के लिये इस सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय का केवल ५ फीसदी रखा गया है। श्रीमन्, इस तरह से औसत केवल सवा दो करोड़ रुपया सालाना ७४ फी सदी जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिये पड़ता है। माननीय वित्त मंत्री महोदय को बड़ा इत्मीनान है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में खेती करने लायक जमीन की मिकदार उन्होंने बढ़ा ली है । लेकिन शायद उनको नहीं मालूम है कि यह उनकी कोशिश की वजह से नहीं बढ़ी। फिर क्या वजह है कि खेती करने लायक जमीनों की मिकदार बढ़ी है ?

(इस समय १२ बज कर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये ।)

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन के कारण जो भूतपूर्व जमींदारों ने अपनी ऊसर, बंजर व परती जमीनों का पट्टा किया, उसका इन्तजाम किया, भले ही आज उसमें खेती होती हो या न होती हो, उनकी वजह से खेती करने लायक जमीन का रकबा बढ़ गया है । वित्त मंत्री महोदय और सरकार की कोशिशों से यह नहीं बढ़ा है । और तारीफ तो उस वक्त होती जब कि खेती करने लायक जमीन और सिंचाई के साधनों के बढ़ने के साथ-साथ इस प्रदेश की उपज भी बढ़ी होती, तब हम समझते कि वित्त मंत्री महोदय अपनी सराहना करने लायक थे । खेती की उपज के आंकड़े मैं विस्तार में प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन केवल इतना कह देना चाहता हूं कि सन् ५२ से लेकर आज तक के आंकड़े अगर देखे जायं तो खेती की पैदावार घटी ही है और वित्त मंत्री महोदय ने हिम्मत नहीं की है सन् ५५-५६ के आंकड़े छूने की और केवल सन् ५३, ५४, ५५ के आंकड़ों से ही मुकाबला कर के माननीय वित्त मंत्री जी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि प्रदेश की पैदावार बढ़ी है, लेकिन सरकार के आंकड़ों के आधार पर ही मेरा दावा है कि सन् ५२ से आज तक इस प्रदेश में अनाज की पैदावार बढ़ी नहीं है बल्कि घटी है ।

मुझे बड़ा अफसोस हुआ बजट को देखकर कि आज हमारी देहात की बेचारी गरीब ग्रामीण जनता कर्ज से लदी जाती है और हम इन थोड़े से सालों में रूरल इनडेटेडनेस इस कदर बढ़ा है कि गांव के लोग उस के कारण तबाह हो रहे हैं । मुझे बड़ी खुशी होती अगर माननीय वित्त मंत्री जी और उनकी सरकार इस बात की चेष्टा करती और बजट में इस बात का प्रबन्ध करती कि गांवों में लोगों पर जो कर्जे का भार है उसको कम किया जाय, परन्तु मुझे यह देख कर निराशा हुई कि इस ओर कोई भी प्रबन्ध सरकार ने नहीं किया है । कोई भी प्रबन्ध जरुरतमन्द लोगों को चीप क्रेडिट सप्लाई करने के लिये

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

बजट में नहीं किया गया है । देहात की जनता के लिये या किसानों के लिये मार्केटिंग फेसिलिटीज देने का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। क्रय-विक्रय की तनिक भी सुविधायें उनके लिये नहीं दी जा रही हैं और सरकार की ओर से किसी प्रकार का इस सम्बन्ध में प्रबन्ध नहीं है । इसका नतीजा यह होता है कि किसान की पैदावार के दाम फसल के दिनों में कम रहते हैं और जब फसल या सीजन खत्म हो जाता है तब उसी अनाज के दाम महंगे हो जाते हैं और इस तरह से २५ प्रतिशत तक का वेरीयेशन सीजन और नान-सीजन के दामों में हो जाता है और सारा नफा मिडिलमेन ले जाता है और किसान तबाह का तबाह ही रहता है । इसका कोई प्रबन्ध होना चाहिये था ।

इसके अलावा उद्योग के उत्पादन और खेती के उत्पादन की चीजों के दामों में संतुलन लाने की कोई भी चेष्टा सरकार की ओर से नहीं हुई है । उधर के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि नेता विरोधी दल ने मर्ज की तशखीस तो कर दी है लेकिन उस का इलाज नहीं बताया । बड़ी हैरत होती है । मर्ज की तशखीस करने के बाद भी अगर आप मर्ज का इलाज नहीं कर सकते हैं तो फिर बेहतर होगा कि हम इधर बैठने वाले उधर जा कर बैठें और उधर वाले इधर आकर बैठें और हम खुद मर्ज का इलाज भी कर लेंगे ।

अभी कुछ दिन से इस प्रदेश की सरकार ने एक नया तजुर्बा किया है । दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह, किसी राज्य या देश में शिक्षा और पुलिस विभाग एक ही मंत्री के हाथ में नहीं रहते हैं लेकिन यहां पर यह चीज भी है । यहां के पुराने शिक्षा मंत्री महोदय कहा करते थे कि अगर हम नये स्कूल खोलेंगे तो उसके साथ ही हमें पुलिसमेन की संख्या भी बढ़ानी होगी और शायद इसीलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुलिस और शिक्षा विभाग एक ही मंत्री के सुपुर्द कर दिया है कि अगर वह एक तरफ स्कूलों की तादाद बढ़ावें तो साथ ही पुलिसमेन की संख्या भी बढ़ा दें, मार्के की बात है गौर करने की बात है कि इस सूबे का कुल बजट १०८ करोड़ का है, उसमें से ९ करोड़ की रकम कर्जे की अदायगी में जायगी और इस तरह से कुल १०० करोड़ रुपया बचता है । उसमें से १५ करोड़ १० लाख रुपया शिक्षा और ९ करोड़ २४ लाख पुलिस पर और ४७ लाख रुपया रुपया सूचना विभाग पर व्यय होगा। इस तरह से अगर सब को जोड़ लिया जाय तो करीब २५ करोड़ के विभाग एक ही मंत्री महोदय के हाथ में रखे गये हैं । यह कहां का बटवारा है, कुल मिनिस्टरों की तादाद १४ है, बजट के चौथाई भाग के लिये एक मंत्री और बाकी १२ मिनिस्टरों के लिये वित्त मंत्री को छोड़ कर शेष बजट का बाकी हिस्सा । यह अजीब नमूना है । एक छोटा मोटा सा नादिरशाह पैदा कर दिया गया । श्रीमन, यह भी एक अजीबोगरीब चीज है । दुनिया में कहीं नहीं मिसाल मिलेगी कि किसी भी देश का या प्रदेश का फाइनेंस मिनिस्टर खर्च वाला विभाग अपने हाथ में रखता हो । यह भी एक उत्तर प्रदेश का नया नमूना है कि इस सूबे के वित्त मंत्री महोदय आमदनी का विभाग तो रखते ही हैं खर्चे के भी कई एक विभाग अपने साथ रख लिये हैं ।

अनएम्प्लायमेंट को दूर करने का तो बड़ा दावा है हमारे वित्त मंत्री महोदय का, लेकिन श्रीमन्, मैं यह दावे के साथ कह देना चाहता हूं कि ज्यादा तफसील में न जाकर, मेरे पास मई, १९५७ तक के आंकड़े हैं जिसमें मई महीने में ३० हजार ९ सौ ४६ एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रियां हुई और मई तक जो कुछ एम्प्लायमेंट में रजिस्टर्ड थे उनकी संख्या १ लाख २६ हजार २ सौ ४१ है । इसमें केवल ३ हजार २ सौ १० आदिमयों को आपने रोजी दी । कैसे हम उम्मीद करें कि पांच साल में आप बेकारी दूर कर देंगे ? इसके अलावा एकानामी के नाम पर पी० आर० डी० विभाग को जो तोड़ रहे हैं उसमें से कितने लोग बेकार होने जा रहे हैं उनके लिए आल्टरनेटिव एम्प्लायमेंट आपके पास क्या है ? इसका जवाब क्या है ? रिटायरमेंट की अवस्था ५५ से ५८ कर दी । यह बहुत कंट्रोवर्शल इश्यू है ।

लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि तीन साल में जो लोग नयी नौकरी पाने वाले थे, अब तीन साल तक नये नौकर नहीं होंगे उनके लिए क्या आल्टरनेटिव इम्प्लायमेंट का साधन है ? यह हम जानना चाहते हैं ।

जितना ह्युमन पावर का वेस्टेज हमारे इस प्रदेश और देश में हो रहा है उतना शायद सारे संसार के किसी देश और प्रदेश में नहीं हो रहा है। बेकारी और बेरोजगारी दूर करने के लिए मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक हेवी इंडस्ट्रीज और काटेज इन्डस्ट्रीज अधिकांश संख्या में नहीं खोली जायंगी तब तक बेकारी और बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है और वह भी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योग धंधे जो हैं वह शहरों में और कस्बों में न खोल कर के गांव-गांव में, घर-घर में, खोलने होंगे, तभी बेकारी और बेरोजगारी खत्म हो सकती है ।

श्रीमन्, यह भी आपके द्वारा मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि गांव में रहने वाला किसान जिसको लोग यह समझते हैं कि उसके पास काम है, वह भी साल में पांच महीने बेकार रहता है । हमेशा उसको काम नहीं रहता है ।

श्रीमन्, इंडस्ट्रीज विभाग की तरफ आपके द्वारा मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । तीन करोड़ रुपये की लागत में तीन नयी इंडस्ट्रीज खोलने की योजना इस सरकार की है। इनमें एक इंडस्ट्री सोडा ऐश फैक्ट्री, वाराणसी और रेअन सिल्क की दो फैक्ट्रीज कानपुर हैं। तीन करोड़ रुपया कर्जा इनको दिया गया है लेकिन आज तक कोई निशान नहीं है कि कहां वह इंडस्ट्रीज खोली जायंगी ।

प्लानिंग की प्रगति के बारे में सिर्फ एक निवेदन करूंगा । मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं । हमारे आजमगढ़ जिले के लिये माननीय सदस्य ने जो उधर बैठे हैं आज से दो तीन रोज पहले इसी सदन में एक सवाल किया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आजमगढ़ जिले में कितनी नयी या पक्की सड़कें निर्माण होने वाली हैं, तो जबाव मिला कि कुल ६ मील। २२ लाख आबादी पर पांच साल के अन्दर सिर्फ ६ मील सड़क बनने वाली है। यही द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की इनकी प्रगति की रफ्तार है। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि हम कहां तक प्रगति कर सकते हैं ।

श्रीमन्, किसी भी वेलफेयर स्टेट की यह पहचान है कि उस स्टेट का जो बजट है, उसका ज्यादातर हिस्सा सेवा कार्यों में खर्च किया जाय और कम हिस्सा प्रबन्ध कार्यों में खर्च किया जाय ।

मुझे निराशा होती है और अफसोस भी अपने प्रदेश की सरकार का बजट देख कर होता है जहां सेवा कार्य पर कुल ४० फीसदी खर्च किया जाता है और प्रबन्ध कार्य पर ६० फीसदी । यह तो नमूना है इस कल्याणकारी राज्य का ।

अन्त में आध मिनट में आपकी आज्ञा से एक बात और कह देना चाहता हूं । माननीय सदस्यों को याद होगा कि माननीय राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में एक संकेत किया था, खोखला वादा किया था । उन्होंने कहा था कि कोआपरेटिव डेवलपमेंट फंड और कोआपरेटिव क्रेडिट गारन्टी फंड क्रीएट करेंगे, ऐसा उनका संकेत था । लेकिन हमें अफसोस है कि इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है कहीं भी इसका नाम निशान नहीं है ।

*श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, जो वाद विवाद सदन में बजट के ऊपर चल रहा है उसमें हिस्सा लेने का मेरा इरादा नहीं था मगर हमने देखा कि विरोधी दलों के कुछ नेताओं ने ऐसी बातें कहीं है जो तथ्य से परे हैं । विरोधी दल के नेता श्री त्रिलोकी सिंह ने यह कहा है कि इस प्रान्त की इंडस्ट्री पहले से घट गई है । परन्तु तथ्य यह है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बेचनराम गुप्त]

इस प्रान्त की इंडस्ट्री पहले से बहुत बढ़ी है। हमारे मित्र श्री झारखंडे राय को इस बात से बड़ा डिसएप्वायंटमेंट हुआ कि यह बजट समाजवादी प्रदेश का बजट नहीं है और उस ओर अग्रसर नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं कि समाजवाद की व्याख्या विरोधी दल के नेताओं ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है। डाक्टर लोहिया जिस समाजवाद की व्याख्या को करते हैं उसको श्री जयप्रकाश नारायण जी नहीं मानते हैं और उसी दल के नेता श्री अशोक मेहता उनसे भिन्न बातें करते हैं। तो सरकार के लिये बड़ी कठिनाई की बात है कि कौन सी व्याख्या मान करके सरकार आगे चले। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि आपस में सलाह करके एक व्याख्या निश्चित कर लें और वित्त मंत्री को बता दें कि समाजवाद की व्याख्या यह सही है और अगला बजट उसी प्रकार से बनाया जाय। यह निश्चय है कि जिस प्रकार का समाजवाद झारखंडे राय जी चाहते हैं उससे माननीय गेंदासिंह या श्री त्रिलोकी सिंह जी कभी सहमत नहीं होंगे। जिसमें बोलने और स्वतंत्र विचार का कोई अवसर नहीं है, इस सदन में कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा।

विरोधी दल से इस बजट की कटु आलोचना की गई। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि क्या केवल आलोचना ही करना उनका कर्त्तव्य है? क्या रचनात्मक सुझाव उनकी तरफ से आये? किसी ने कोई सुझाव दिया होता कि बजट इस प्रकार से नहीं दूसरी प्रकार से होता तो अच्छा होता। श्री झारखंडे राय जी ने कुछ नेशनलाइजेशन की बातें कहीं। उनको शायद यह अनुभव नहीं है कि जो इंडस्ट्री नेशनलाइज की गई इस प्रान्त में, उसकी क्या हालत है। मैं केवल दो इंडस्ट्रीज का अनुभव उनके सामने रखता हूं। एक तो गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क और दूसरे कानपुर की इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी। जो सीमेंट चुर्क फैक्ट्री से निकलती है निश्चय ही उसकी कीमत ए० सी० सी० कम्पनी के सीमेंट से अधिक है। उनका कास्ट प्रोडक्शन पर ज्यादा है। उसी प्रकार से आप देखें कि कानपुर की एलेक्ट्रिसिटी का रेट पहले की कम्पनी के रेट से ज्यादा है और प्राफिट भी दोनों का जो हुआ है वह ऐसा नहीं है जैसा किसी प्राइवेट सेक्टर की कम्पनी का होना चाहिए था। अभी तक चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का हिसाब-किताब देखने का मुझे मौका नहीं मिला है, सम्भव है कि उसमें कुछ मुनाफा हो। मगर कानपुर में एलेक्ट्रिसिटी का इन्तजाम जो सरकार के हाथ में है उसका कुछ हिसाब-किताब देखने का मौका हमको मिला है और हम कह सकते हैं कि उसी को अगर प्राइवेट सेक्टर ने मैनेज किया होता तो उसका मुनाफा ज्यादा हुआ होता।

एक माननीय सदस्य ने यह निवेदन किया कि इस सरकार को केरल सरकार से शिक्षा लेनी चाहिए। शायद उनका ख्याल यह है कि केरल की सरकार ने एक बजट बनाया है जो कि सरप्लस है। मैं उनसे निवेदन करूं कि बजट के पंडित सरप्लस बजट को अच्छा नहीं मानते, बैलेंस्ड बजट तो अच्छा हो सकता है मगर सरप्लस बजट इस बात का द्योतक होता है कि वहां की सरकार रुपया ठीक से खर्च करना नहीं जानती।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कुछ आंकड़े फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट से कोट किये कि इस प्रान्त की तीन शुगर फैक्ट्रीज दूसरे प्रान्तों में चली गईं और एक संभवतः बन्द हो गई और कपड़े की नौ मिलें भी बन्द हो गईं और तेल की इंडस्ट्री प्रायः समाप्त ही हो गई। श्रीमन्, मैं निवेदन करूं कि जहां तक इंडस्ट्री के खोलने का सवाल है वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के एक ऐक्ट के अनुसार होता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया उसके लिए लाइसेंस देती है। मगर जहां के माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने आंकड़े कोट किये उसी जगह वह देखेंगे कि शुगर मिलें ६३ से ६७ इस प्रान्त में हो गईं और प्रोडक्शन भी सन् १९५३-५४ में ५,५९,६५४ टन से बढ़ करके ५४-५५ में ९,०३,४४१ टन हो गया। आप देखेंगे कि चीनी का प्रोडक्शन पहले से प्रायः दूना हो गया। इसके अलावा चार मिलें कोआपरेटिव बेसिस पर इस प्रान्त में खोली जा रही हैं। एक किछा में है, दूसरी बाजपुर में है, तीसरी बागपत में है

और चौथी सहसवान में है। इन चारों मिलों में काम शुरू हो गया है और आशा है कि साल दो साल में ये चारों मिलें काम करना शुरू कर देंगी। अगर इन चारों मिलों ने प्रोडक्शन शुरू किया तो, श्रीमन्, हम देखेंगे कि शुगर का प्रोडक्शन चौगुना हो जायगा।

जहां तक कपड़े की इंडस्ट्री का सवाल है। श्रीमन्, मैं निवेदन करूं कि यह कपड़े की मिलें अनइकोनामिक थीं। बहुत दिनों की पुरानी थीं। उनकी अवस्था ठीक नहीं थी। एक उनमें से बनारस की काटन मिल है जिसको कि हम जानते हैं कि बहुत पुरानी मिल हो गई है। बहुत कोशिश की गई उसको चलाने की मगर सभी लोग असफल रहे क्योंकि मशीन बहुत पुरानी है। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया गवर्नमेंट आफ इंडिया इस प्रकार की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इस प्रान्त में बहुत कम लाइसेंस देती है। फिर भी चार मिलें इस प्रान्त में खुलने वाली हैं और शायद उनको लाइसेंस भी मिल गया है। एक श्री पद्मपत सिंहानिया की यार्न फैक्ट्री है कानपुर की, एक मोदी साहब की सिल्क फैक्ट्री है मोदीनगर की, एक मोदी साहब की यार्न मिल है मोदीनगर की और एक जयपुरिया की यार्न मिल नैनी में है। इसके अलावा, श्रीमन्, एक सोडा ऐश फैक्टरी रामनगर और मुगलसराय के बीच जोरों से खुल रही है और आशा है साल-दो साल में वह तैयार हो जायगी। इसके अलावा हिन्दुस्तान में आटोमेटिक बाटल्स बनाने की तीन मिलें हैं जिनमें से एक हमारे प्रान्त में है विभूति ग्लास वर्क्स। दूसरी कलकत्ते में और तीसरी बम्बई में है। इन आंकड़ों से आप देखेंगे कि हमारे प्रान्त की इंडस्ट्रीज़ पहले से बढ़ी हुई है, घटी नहीं है। फिर छोटी-मोटी इंडस्ट्रीज़ बहुत सी हैं जिनको मैं गिनाना नहीं चाहता।

एक बात माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने भ्रष्टाचार के बारे में कही। उन्होंने कहा कि आज ६० फीसदी भ्रष्टाचार माल विभाग में और ४० फीसदी पुलिस तथा अन्य विभागों में है। भ्रष्टाचार की बात इस सदन के भीतर व बाहर विरोधी दलों द्वारा अक्सर कही जाती है। मैं, श्रीमन्, निवेदन करूं, क्या कोई सुझाव विरोधी दल से आया कि भ्रष्टाचार इस तरह से दूर हो सकता है? श्रीमन्, देखेंगे कि हर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक कमेटियां बनी हुई हैं। मैं नहीं जानता कि हमारे माननीय सदस्य इन कमेटियों में जाते हैं और सहयोग देते हैं या नहीं। अगर सहयोग देते होते तो निश्चय ही इस प्रान्त के भ्रष्टाचार में कमी होती। मैं निवेदन करूं कि माल विभाग में भ्रष्टाचार है। लेकिन माननीय त्रिलोकी सिंह जी हमसे सहमत होंगे कि टाप पर नहीं है, मिडिल में नहीं है, परन्तु बाटम में जरूर है। उसको हम भी कबूल करते हैं और खास कर पटवारी, कानूनगो और कुछ नायब तहसीलदारों में भी भ्रष्टाचार पाया जाता है। क्या त्रिलोकी सिंह जी को यह मालूम नहीं कि इस प्रान्त के जितने पटवारी थे एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब बरखास्त कर दिये गये और उनकी जगह पर लेखपाल नियुक्त किये गये? लेकिन क्या लेखपालों में भ्रष्टाचार नहीं है? मैं कहता हूं कि उनमें भी है। मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार ऐसा सोशल ईविल है जिसके बारे में माननीय त्रिलोकी सिंह व हम लोग बैठ कर विचार करें कि किस प्रकार से यह दूर हो सकता है। केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार चिल्लाने से तो वह बढ़ेगा ही, दूर नहीं होगा। मैं, श्रीमन्, यह भी निवेदन करूं कि प्रजातंत्र में कुछ भ्रष्टाचार बढ़ ही जाता है। शायद माननीय त्रिलोकी सिंह जी को मालूम होगा कि अमेरिका जैसे बड़े देश में भी बड़े से बड़ा जज रिश्वत लेता है तो अपने देश का क्या कहना जो २०० साल से गुलाम रहा है। अगर उसमें कोई ऐसा ऐब है तो कोई ऐसी बात नहीं है।

श्रीमन्, माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने एक नई थ्योरी ईजाद की। मौत की संख्या इसलिये घटी है कि ज्यादा उम्र में लोगों की शादी होती है? मैं, श्रीमन्, निवेदन करूं कि यह तथ्य से बहुत दूर है। आप, श्रीमन्, देखेंगे कि इस प्रान्त में प्लेग नहीं रहा। कालरा कहीं-कहीं सुना जाता है, मलेरिया भी नाम मात्र को है। इन सबों के साथ सरकार की काफी लड़ाई हुई, काफी पैसा खर्च किया गया। इसलिये यह थ्योरी कि अधिक उम्र में शादी होती है जिसके कारण डेथ रेट घटा है, गलत है।

[श्री बेचनराम गुप्त]

एक बात की ओर, श्रीमन्, मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब हम जेल में थे तो हम जेल के बारे में रिफार्म्स करने की बात सोचते थे और संभवतः शायद हम लोगों ने कुछ किया भी, परन्तु आज समाजवादी हमारे भाई जो जेल में हैं उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है मैं निवेदन करूं कि वह बर्ताव अच्छा नहीं है और ऐसा नहीं है जो राजनैतिक कैदियों के साथ होना चाहिये। शायद हम लोगों को भी कभी जेल जाने की आवश्यकता पड़े, यह हम भूल न जायं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि ब्रिटिश की हुकूमत में जो हमारे साथ बर्ताव था, सोशलिस्टों के साथ उससे अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। निश्चय ही अच्छा बर्ताव था उनका। बनारस की जेल में मुझे कुछ दृश्यों को देखने का मौका हुआ। हमने देखा जैसे कि किसी बाड़े में जानवर इकट्ठे कर दिये जाते हैं, वैसे हमने सोशलिस्टों का एक गिरोह पाया। अन्दर बहुत गन्दगी थी। उनको साफ करने के लिये कपड़ा या बदन साफ करने के लिये साधन नहीं दिया जाता। माननीय राजनारायण सिंह ने मुझ से शिकायत की कि उनको वही भोजन दिया जाता है जो और कैदियों को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमको लकड़ी दे दी जाय, हम स्वयं खाना बनाने का इन्तजाम कर सकते हैं। मैं, श्रीमन्, यह निवेदन करूं कि इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। मैंने देखा है कि जो गल्ला जेल डिपार्टमेंट से जेलों के लिए खरीदा जाता है, शायद मिडिल क्लास की फ़ैमिलीज में उतना अच्छा गल्ला न खरीदा जाता हो, परन्तु जो भोजन बना के दिया जाता है वह इतना खराब होता है कि गरीब से गरीब आदमी उससे अच्छा खाना खाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से भोजन बनाया जाय। थोड़ी सी लकड़ी की बात के लिए राजनैतिक कैदियों को तकलीफ देना मैं कोई अच्छी बात नहीं समझता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं, श्रीमन्, जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पैश किया है उसका स्वागत करता हूं। यह बजट हमें समाजवाद की ओर ले जाता है और एक कल्याणकारी बजट है।

विरोधी दल को वाद-विवाद में अधिक समय देने की प्रार्थना

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसकी क्षमा चाहता हूं कि मिनट दो मिनट इस आदरणीय सदन का समय दो बातें आप की सेवा में और आप के द्वारा इस आदरणीय सदन की सेवा में अर्ज करने में लगा रहा हूं।

एक बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बजट के वाद-विवाद में और उसकी सारी कार्यवाही में संसदीय प्रथा पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस यह रही है कि विरोधी दल का मुख्य हाथ होता है और किसी भी दशा में उसे जो समय बहुमत दल को दिया जाता है, उससे कम नहीं मिलना चाहिये।

मैं, श्रीमन् का ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ २९३ में जो लिखा हुआ है उस ओर दिलाऊंगा और उसी की पुष्टि में जेनिंग्स की किताब में यह भी लिखा हुआ है पृष्ठ ५२ पर कि साधारणतया जब एक स्पीकर एक पक्ष का होता है तो दूसरा बोलने वाला दूसरे पक्ष का होता है। श्रीमन् से मैं निवेदन करूंगा कि इसी प्रथा का अनुसरण यदि इस आदरणीय सदन में भी किया जाय तो हम एक स्वस्थ प्रथा की पुष्टि करेंगे और मैं यह भी समझता हूं कि हम अपने मान को बढ़ायेंगे।

दूसरी बात यह है कि यह मेहरबानी सरकार के बहुमत दल ने इस निवेदन को स्वीकार कर की है कि बजाय तीन दिन के बजट पर आम वाद-विवाद के लिये चार दिन की रज़ामंदी दी। मैं, श्रीमन् से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने रज़ामन्दी हासिल कर ली है माननीय वित्त मंत्री की, जो इस सदन के उपनेता हैं कि आज इस वाद-विवाद का समय बजाय ५ बजे के ६ बजे तक कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय त्रिलोकी सिंह का बहुत ही अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने इस संसदीय परम्परा की तरफ मेरा ध्यान दिलाया। मैंने भी इन बातों को अध्ययन किया है, मैं उनसे सहमत हूं कि अन्य देशों की भांति हमारे यहां भी इस संसदीय परम्परा का यदि पालन हो तो बहुत उत्तम है और यथासम्भव चेयर की तरफ से इसी बात का प्रयत्न हुआ है। अब तक कांग्रेस के २७ मेम्बरान ने भाषण किया है और अपोजीशन के १८ मेम्बरान ने। लेकिन जहां तक समय का सवाल है अब तक कांग्रेस पार्टी को पौने सात घंटे और विरोधी दल को सवा सात घंटे का समय दिया गया है। इस तरह से हमने संसदीय परम्परा का ध्यान रखा है और इसके साथ ही साथ माननीय सदस्यों के चुनाव क्षेत्रों का भी ध्यान रखा है। इन दोनों चीजों को सामने रख कर हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इस प्रकार की संसदीय परम्परा का प्रचलन हो और अच्छी परम्परा बने।

दूसरी बात में आप लोगों को यह बतला देना चाहता हूं कि मेरे पास सौ, सवा सौ माननीय सदस्यों के स्लिप्स आये थे कि हमें बोलने का मौका दिया जाय और समय सीमित है। पिछले साल यह हुआ था कि प्रत्येक सदस्य के लिये पहले दिन १५ मिनट, दूसरे दिन १० मिनट और फिर ७ मिनट और ५ मिनट तक का समय कर दिया गया था। इस समय भी "देर आयद दुरुस्त आयद" वाली बात हो सकती है। यह सदन का काम था। अब आप चाहें तो आज से माननीय सदस्य दस-दस मिनट भाषण दें, इस पर किसी को एतराज नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में थोड़ा समय बढ़ाया भी जा सकता है। आमतौर से माननीय सदस्य दस-दस मिनट भाषण दें तो काफी मेम्बरों को सुविधा होगी।

इस दस मिनट के बारे में सदन की क्या राय है, मैं यह जानना चाहता हूं (आवाजें--- ठीक है, ठीक है।)

मैं विशेष परिस्थिति में कुछ ढील दे दूंगा, लेकिन यह उचित होगा कि दस मिनट का समय दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि जो सदन के ५ के बजाय ६ बजे तक बैठने की बात है, उसके लिये उपयुक्त समय पर प्रस्ताव आ जाना चाहिये।

श्री त्रिलोकीसिंह---वह तो मैंने अपने भाषण में प्रस्ताव रख दिया है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि आज सदन शाम के ६ बजे तक बैठे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५७-५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अन्तः करण की समस्त अनुभूतियों के साथ आप से यह प्रार्थना करता हूं कि हम लोग शान्तिप्रिय हैं और पंचशील के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं, इसलिये हमको लाल लाइट न दिखाई जाय।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो मैं समझता हूं कि सदन के बहुत से माननीय सदस्यों का प्यारा रंग है।

श्री यशपालसिंह---हम लोग तो शान्ति और अमन को मानते हैं। यह लोग ओबीडियेंट हैं, यह तो केरल में शोभा दे सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं आशा करता हूं कि आप वह नौबत नहीं आने देंगे।

श्री यशपालसिंह—जो बजट आपके सामने प्रस्तुत हुआ है उसके विषय में काफी लम्बी चौड़ी बातें हुई हैं। मुझे ज्यादा नहीं कहना है। बजट में समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई है बल्कि व्हाइट वाशिंग की गई है, लीपापोती की गई है। मिसाल के तौर पर मैं दो तीन बातें अर्ज कर सकता हूं जैसे नहर के पानी के मुताल्लिक—ट्यूब वैल्स के पानी के मुताल्लिक यह दिखाया गया है कि आबपाशी का रकबा दुगना हो गया है। लेकिन हकीकत यह है कि ८ इंच के जो कुलाबे थे उनको काट कर ४-४ इंच का कर दिया गया है और जो ५०० बीघा जमीन सैलाब होती थी वह १,००० बीघे दिखा दी गई है और हकीकत यह है कि वहां २०० बीघे जमीन में भी पानी नहीं पहुंच सकता है। यह चीज मैंने गंगा नहर के किनारे पर घोड़े की पीठ पर बैठ कर देखी है। गवर्नमेंट तो इस कोशिश में थी कि यह दिखाया जाय कि आबपाशी का रकबा बढ़ गया है, लेकिन हुआ उल्टा। जो चार इंच के कुलाबे थे, जब मई की गर्मी पड़ी और कड़ाके की लू चली तो जमीन ने पानी पीना शुरू कर दिया और पानी आगे नहीं चल सका और तरक्की के बजाय तनज्जुली हुई है।

इसी प्रकार से यह जो हमारे सामने ७० साला स्कीम रखी गई है २५ लाख रुपये की, उसमें भी व्हाइट वाशिंग किया गया है। चूंकि गरीब आदमी तो ७० साल तक जी नहीं सकता, उसकी हड्डियां तो ४० साल में ठंडी हो जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा ५० साल में अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर लेता है। ७० साल तक जियेंगे माननीय हाफिज जी, पंतजी, मोदी साहब, बिरलाजी, सिंहानिया जी। गरीब आदमी या तो बच्चा ही होता है या बूढ़ा हो जाता है। शायर के लफ्जों में—

"तिफली गई अलामते पीरी अयां हुई,
हम मुन्तजिर ही रह गये अहदे शबाब के।"

७० साला स्कीम से जो फायदा होगा वह होगा कुछ कांग्रेसी मिनिस्टरों के रिश्तेदारों का जो खाते-पीते लोग हैं। वह गलत तरीके से असहाय बन कर उन पेन्शनों को हासिल करेंगे। जो दरहकीकत गरीब है उस तक न वह पेन्शन पहुंचेगी और न वह ७० साल तक जिन्दा रहेगा। कहते हैं कि बाबा जी जब मरे तो किसी ने कहा कि गऊदान कर दो, तो छोटे भाई ने कहा कि जो गाय खो गई है वह दान कर दो। इस पर बड़े भाई ने कहा कि जो खो गई है उसके तो मिलने की भी आशा है, जो मर गई है वह दान कर दो। नतीजा यह होगा कि ७० साल तक न गरीब आदमी जी सकेगा और न वह पेन्शन पा सकेगा।

हर मामले में जहां किफायत की जानी चाहिये थी वहां नहीं की गई और जहां नहीं की जानी चाहिये थी वहां की गई है। कोयलों पर मुहर लगाई गई है और अशर्फियों को बिखेरा गया है। मिसाल के तौर पर मैं चकबन्दी के महकमे को लेता हूं। हमारा यह दुर्भाग्य है कि माननीय माल मंत्री जी यहां इस समय शोभायमान नहीं हैं। अगर वे मौजूद होते तो उनसे और ज्यादा खुल कर बातें होतीं। सारे चकबन्दी के महकमे में एस० ओ० सी० के पास एक जीप रहती थी। जो एस० ओ० सी० ईमानदार हुये उनको यह खतरा रहता था कि पता नहीं किस वक्त कोई आ जाय। उनसे वह जीप छीन ली गई और वे बेचारे या तो गांव के घोड़े मांग कर सफर करेंगे या पैदल। उनकी अपनी कारें कच्चे में नहीं पहुंच सकती हैं, जहां जीप पहुंच सकती थीं।

दूसरे हमारे यहां एक मुजफ्फराबाद जगह है जहां के महमूद अली साहब एम० एल० ए० हैं। वहां लगभग चार लाख रुपये कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिये दिये गये, लेकिन न वहां कुयें बने, न वन महोत्सव हुआ, न अन्न महोत्सव। बी० डी० ओ० साहब की कार शहर में एक बार आयी तो पूछने पर मालूम हुआ कि उनके यहां नींबू नहीं रहे थे। दूसरी दफा जब उनकी कार आयी तो मालूम हुआ कि बी० डी० ओ० साहब के यहां शलजम नहीं रहे थे। यह कोई बहाना नहीं है कि वह जीप सेंटर की है। वह भले ही सेंटर की हो, लेकिन उसके लिये पैट्रोल और टी० ए० का इन्तजाम हम लोग करते हैं।

सबसे पहली तालीम इंसान के लिये सीधे खड़े होने की है। जिस महकमे में यह तालीम दी जाती थी, जिसे प्रान्तीय रक्षक दल कहते थे अब वह तोड़ा जा रहा है। चल कौन प्रोग्राम रहा है, जिसे कंचन या कल्चर प्रोग्राम कहते हैं, नाच गाने का प्रोग्राम है वह दिन रात चलता है। जरूरत इस बात की थी कि देश के जवान को सीधे खड़े होने की तालीम दी जाती, लेकिन वह महकमा खत्म किया जा रहा है। हमारे पास का मुल्क पाकिस्तान है। वहां हर एक जवान के लिये जो २४ साल का है मिलिटिरी ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गयी है। लेकिन एक हमारा मुल्क है जहां २४ साल के जवान को अम्बर चर्खे की तालीम दी जा रही है। मैं अम्बर चर्खे को बुरा नहीं कहता, लेकिन अम्बर चर्खे की तालीम लड़कियों को देनी चाहिये और लड़कों को मिलिटरी ट्रेनिंग दी जानी चाहिये।

"क़सीदे से न चलता है न यह दोहे से चलता है,
समझ लो खूब कारे सल्तनत लोहे से चलता है।"

अकेले सेंटर से पंडित नेहरू कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा फर्ज है कि हम देश की हिफाजत करें। मेरी आपसे यह अर्ज है कि अगर वाकई आप देश के गरीब का भला करना चाहते हैं तो इस बजट पर फिर से गौर कीजिये। एक से एक आपके हितैषी यहां बैठे हुये हैं। यह वहम आप निकाल दीजिये कि हम आपोजीशन में है। मैं अपने उपाध्यक्ष महोदय से अर्ज करूंगा अगर मेरा सजेशन माना जाय तो मैं यह भी प्रार्थना करने के लिये तैयार हूं कि अपोजीशन लफ्ज अनगाडली वेस्ट (ungodly west) का दिया हुआ है। इस पार्टी का नाम "हितकारी मंडल" या "खैरख्वाह पार्टी" हो। अपोजिशन पार्टी लफ्ज तो यूरोप से आया है। हम अपने देश की किश्ती को आगे ले जाना चाहते हैं। हम को आपसे कोई किसी तरह की ग्रज नहीं है। हम आपके शत्रु नहीं हैं, विरोधी नहीं हैं। हम आपसे यह अर्ज करना चाहते हैं कि दुनिया का यह कायदा है और नीति शास्त्र भी इस बात को कहता है कि "पुरुषाः वहवो राजन् सततं प्रियवादिनः, अप्रियस्यतु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः"। जो सच्चे हितैषी हैं वह हमेशा ऐसी बात कहेंगे कि जो कड़वी लगती हो, लेकिन आखिर में जाकर उसका नतीजा अच्छा निकलेगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप कर्नल नासिर की तरह गरीब जिन्दगी नहीं बितायेंगे, जब तक आप ईरान के मुसद्दिक की तरह से अपना रहन सहन नहीं करेंगे तब तक आपका देश आगे नहीं जा सकता है। ईरान का डा० मुसद्दिक बिना एक पैसा लिये ही अपने देश की सेवा करता था।

हिन्दुस्तानी कल्चर और भारतीय संस्कृति जिसको आप कहते हैं उसके अनुसार तो एक पैसा भी नहीं लिया जाता था और तब कोई वजीर तनख्वाह नहीं लेता था। एक तो उनको कुर्सी दें और जिम्मेदारी दें, इज्जत दें और दूसरे उनको पेट भरने के लिये पैसा भी। यह दोनों नहीं मिलना चाहिये। चुपड़ी और दो-दो यह बात यूरोप के बेसिस पर कही जाती है। हमारे यहां कि कोई इस प्रकार की बेसिस नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ महाराजा चन्द्र गुप्त का महामन्त्र चाणक्य माना जाता है जिसको कौटिल्य शास्त्र का कर्त्ता कहते हैं। उस चाणक्य की तस्वीर किसी महल में नहीं बल्कि एक झोपड़ी में है। उसके पास महल नहीं था, उसके पास झोपड़ी थी जिसपर वह लकड़ी और कंडे सुखाते सुखाते झोपड़ी नीचे झुक गयी थी। उपलशकल मेतत् भेदकं गोमयानाम्। वटुभिः उपहृतानां बोहिषां स्तोमएष। ईरान के डा० मुसद्दिक जिस तरह से रहते थे उस तरह से अगर हमारे वजीर साहब रहें तो हम मान सकते हैं। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि वे त्याग और आदर्श का नमूना हमारे सामने रखेंगे। गांधी जी ने जो अनुमान लगाया था उसी उसूल पर अमल करने का प्रयत्न करेंगे। देश के महान् नेता हमारे राजेन्द्र बाबू आज जिस पोस्ट पर हैं उसके लिये गान्धी जी ने ५०० रुपया तय किया था। उस हिसाब से यू० पी० के वजीर के लिये १२५ रुपया हिस्से में आता है। यदि आप उन उसूलों पर चल कर दिखायें, हमारे वजीर साहबान उस त्याग के साथ रहें तो फिर किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि उसी तरह से न करे। जब आपही उन आदर्शों पर अमल नहीं करते हैं तो सरकारी कर्मचारियों को क्या जरूरत

[श्री यशपालसिंह]

हैं कि वह त्याग का आदर्श उपस्थित करें। त्याग आपके यहां से शुरू होगा । जिस दिन आप यह आदर्श उपस्थित करेंगे, जिस दिन नासिर को तरह से रह कर दिखायेंगे तो देश का कल्याण शीघ्र होगा। अगर हमारे वजीर सादगी को मानें और महात्मा गान्धी के उसूलों के पाबन्द हो जायं तो इस देश से गरीबी दूर हो जाय और हमारा बजट जो है वह वाकई में इस प्रदेश का सुन्दर बजट होगा ।

आज यह प्रदेश का सुन्दर बजट नहीं है । आज तो यहां अनाज पर भी टैक्स लगाया जाता है और दरवेश बन कर उस टैक्स को मांगने की बात कही जाती है। आप मुहाफिज रहें या दरवेश बनें, पब्लिक तो टैक्सों के नीचे कराह रही है। आपकी दरवेशी। मुझे इकबाल के लफ्जों में कहना पड़ता है--

"खुदा बन्दा ये तेरे सादा लौह बन्दे किधर जायें,
कि सुलतानी भी अय्यारी है दरवेशी भी अय्यारी ।"

अब तो देश का खून पिया जा रहा है। जो टैक्स लगाया जा रहा है गरीबों पर लगाया जा रहा है। मेरी गुजारिश है कि टैक्स लगाइये गूजरमल मोदी पर, बिड़ला पर और डालमिया पर टैक्स लगेगा तो आपके पास ज्यादा पैसा आयेगा । मेहरबानी करके काश्तकार को छोड़ दीजिये। मैं अंग्रेजी जमाने का छोटा-सा काश्तकार हूं। तब मैं ४ बैलों का काश्तकार था, लेकिन आज इस सो-काल्ड राम राज्य में मेरे पास ३ बैल ही रह गये हैं। आज उस जमाने की निस्बत पांच गुना टैक्स देता हूं। मेरी गुजारिश है कि इस टैक्स को खत्म किया जाये वरना अन्न उत्पादन नहीं हो सकता है । अन्न उस वक्त उत्पादन किया जा सकता है जब अन्न पैदा करने वाले को प्रोत्साहन दिया जायगा। आज अन्न पैदा करने वाले को लटा जा रहा है। शराब पर टैक्स हो और जो विलास की चीजें हैं उन पर टैक्स हो। आपने यह वायदा किया था कि किसान को सुखी रखेंगे, लेकिन देवबन्द के काश्तकारों का १२ लाख रुपया मिलमालिकों क ऊपर बाकी है। मेरी ख्वाहिश है कि हमार गन्ना मन्त्री और माननीय वित्त मन्त्री या तमाम सरकार के मन्त्री इस बात के लिये प्रयत्न करें कि वह वहां के रुपया एक सप्ताह के अन्दर काश्तकारों को मिल जाय, वरना वहां के काश्तकार इस वक्त भूखों मरने की हालत में हैं। बस मुझे यही निवेदन करना था ।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा वित्त मंत्री जी को इस प्रगतिशील बजट के लिये मैं बधाई देना चाहती हूं। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में जो ५ रुपये की बढ़ोत्तरी की है तथा ७० वर्ष के बूढ़ों को सहायता देने के लिये जो कदम उठाया है वह सराहनीय कदम है। हमारे विरोधी दल का कहना है कि इतना सा रुपया बढ़ा देने से उनका क्या लाभ होगा ? उनको यह ध्यान नहीं है कि गरीब देश में जिनको देश बनाना है, समाज बनाना है, उनको संभल संभल कर कदम बढ़ाना होता है, तरक्की संभल संभल कर करनी होती है। डूबने वाले के लिये तो तिनके का सहारा ही काफी होता है । इसलिये ५ रुपये की तरक्की देकर सरकार ने जो कदम उठाया है, मैं समझती हूं वह एक प्रगतिशील कदम है, मैं उसकी सराहना करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा में प्रगति हुई है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। स्कूल और कालेजेज बढ़े हैं। गांवों में भी जाकर देखें तो वहां भी बढ़े दिखायी देते हैं। यह जरूरी है कि गांवों में उनके भवनों की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकी है, लेकिन जितने काम किये गये हैं उनकी सराहना होनी ही चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने छठी कक्षा तक नि शुल्क शिक्षा देने के लिये एक कदम उठाया है। इसके लिये भी मैं उनकी सराहना करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप विश्राम करके दूसरे वक्त अपना भाषण जारी रक्खें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुल्तान आलम खां के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत---अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में मैं कह रही थी कि हमारी सरकार ने छठी कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने का विचार किया है, यह उसने एक सराहनीय कदम उठाया है और इससे साधारण जनता को काफी राहत मिलेगी। जिनके घर में ५, ६ बच्चे हैं उनको पढ़ाने में उनको बड़ी कठिनाई होती थी और दिक्क़तों का सामना करना पड़ता था। अब पूरी आसानी तो नहीं हो सकी है, लेकिन कुछ तो राहत उनको मिलेगी ही। हमारी सरकार ने सोचा है कि आगे चल कर वह आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा कर देगी। हमारी सरकार ने साधारण तनख्वाह वाले कर्मचारियों के बच्चों की ६वीं कक्षा तक की फीस भी आधी कर देने का विचार किया है।

सरकार ने प्रान्त में प्राइमरी शिक्षा जो अनिवार्य किया है। यह तो सराहनीय बात है ही, लेकिन माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं लड़कियों की शिक्षा की तरफ भी दिलाना चाहती हूं। उन्होंने प्रान्त के शहरों में तो अनिवार्य शिक्षा कर दी, लेकिन वह केवल लड़कों के लिये ही है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह सोचते हैं और क्या यह चाहते हैं कि लड़कों की उन्नति हो और लड़कियों की उन्नति न हो? जब आप ने हमको संविधान में समान अधिकार दिया है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी समान अधिकार होना चाहिये तथा समान विचार भी होना चाहिये। लड़कों और लड़कियों की शिक्षा की तरफ सरकार को एक स्तर पर ही विचार करना चाहिये। बजट बनाते समय आप को लड़के और लड़कियों को एक साथ मिला कर ही सोचना चाहिये था। जितना खर्चा लड़कों के लिये करते उतना ही लड़कियों के लिये करते, तो हम इसको समझते, लेकिन आपने पूरे प्रान्त के शहरों में लड़कों के लिये अनिवार्य शिक्षा कर दी है, लेकिन लड़कियों को छोड़ दिया है। कुछ जिलों में लड़कियों के लिये अनिवार्य शिक्षा आपने किया है, यह सराहनीय बात है और यह भी मैं समझती हूं कि लड़कियों के लिये अनिवार्य शिक्षा करने में आप को दिक्क़तों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सब गांव वाले अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिये घर से नहीं भेजते हैं, यह सही है, लेकिन जब समाज का उत्थान करना है, देश का उत्थान करना है, देश को ऊंचा उठाना है तो कठिनाइयों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मैं आपको सुझाव देती हूं कि प्रान्त के बड़े जिलों में तो आप अनिवार्य शिक्षा अवश्य ही कर दें।

हमारी सरकार ने जिले में मनोवैज्ञानिक केन्द्र खोले हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से मनोवैज्ञानिक केन्द्र में बच्चों की बुद्धि की परीक्षा होती है, बुद्धि का अनुसंधान होता है, लेकिन वहां भी जो बच्चे बुद्धि के तेज होते हैं उनका तो ध्यान कर लिया जाता है, लेकिन जिन बच्चों की बुद्धि का विकास अभी नहीं हुआ है और जो असाधारण बुद्धि वाले बच्चे हैं उन का ध्यान नहीं किया जाता। उनके लिये सिवा मांटसरी स्कूल के कोई जरिया नहीं है। वहां भी मांटसरी वाले कहते हैं कि हम इन बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं दे सकते। यह बड़े दुख की बात है कि हमारी सरकार के पास इन असाधारण बच्चों के लिये कोई स्कीम नहीं है। मैं उनकी ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं। वह इस ओर भी ध्यान दें और कोशिश करें कि उनकी बुद्धि का भी विकास हो। इस तरह से स्कूल बनारस में या इलाहाबाद में खोलने की व्यवस्था करें। हमारी सरकार ने मनोवैज्ञानिक केन्द्रों के लिये तो सब कुछ किया है, लेकिन वहां पर बच्चों का विकास होता है या नहीं इसकी अच्छी तरह से वहां छानबीन नहीं होती। इसकी भी सरकार को खोज करानी चाहिये।

स्वास्थ्य विभाग ने हमारे यहां काफी उन्नति की है इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता। पूर्वी जिलों में पहले महामारी हर साल सताया करती थी, हैजा, मलेरिया और प्लेग आदि रोग हर साल वहां सताया करते थे, उनका प्रकोप अब बहुत कम हो गया है, इसके मानने से

[श्रीमती सज्जनदेवी महनोत]

कोई इन्कार नहीं कर सकता। हमारी सरकार ने अस्पताल और जच्चा-बच्चा केन्द्र बहुत से खोले हैं, लेकिन अच्छी दाइयों आदि की शिक्षा की अभी बहुत कमी है, दाइयों को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती, मिडवाइव्ज ट्रेन्ड नहीं मिलतीं और जो दाइयां देहातों में काम करती हैं वह गन्दे हंसिया और छुरियों से बच्चों का नार काटती हैं। मुझे यहां भवन में कहते हुये बड़ी शर्म आती है कि सैकड़ों नवजात शिशु इस तरह से बेमौत मर जाते हैं। इन अनट्रेन्ड दाइयों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं चाहती हूं कि उनको ३ मास की ट्रेनिंग देनी चाहिये और उनको एक पेटी कैंची, टिन्चर आदि दे कर भेजना चाहिये ताकि जच्चा और बच्चा की रक्षा हो सके। मैं अधिक बात करने के लिये नहीं खड़ी हुई हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि देहाती इलाकों में अभी ट्रेन्ड दाइयों और मिडवाइव्ज की बहुत कमी है, इस का ध्यान सरकार अवश्य रखे।

हमारी सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिये दूध का प्रबन्ध किया है यह बड़ी खुशी की बात है, लेकिन वह दूध किन बहिनों को मिलना चाहिये इसका ध्यान सरकार ने कम रखा है। इस तरह के गर्भवती महिलाओं को दूध देने के लिये जो केन्द्र खुले हैं वह अधिकतर शहरों में खुले हैं। शहरों में तो साधारण लोग अधिक हैं पर देहात में बहुत गरीब लोग रहते हैं। सब के लिये तो सरकार पूर्ति नहीं कर सकती, लेकिन जो गरीब हैं उन महिलाओं की ओर सरकार का अधिक ध्यान जाना चाहिये था जो देहात में अधिक हैं। इसके अलावा गर्भवती औरतों के केन्द्र किसी संस्था द्वारा अगर चलाये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा।

समाज कल्याण का कार्य भी हमारी सरकार ने इस प्रदेश में बड़े जोर शोर से आरम्भ किया है इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है। आज हमारे यहां ३ तरह की संस्थायें इस सम्बन्ध में खोली जा रही हैं। एक तो वे हैं कि जिनमें सतायी हुई मातायें, बहिनों को स्थान दिया जाता है, दूसरे वे हैं जहां अनाथ बहिनों को रखा जाता है और तीसरी वे हैं जिनमें अनाथ बच्चों को स्थान दिया जाता है। मैं सरकार का ध्यान इन होम्स की ओर दिलाना चाहती हूं और चाहती हूं कि जो समाज में कार्य करने वाली बहिनें हैं उनकी कमेटी द्वारा ही यह संस्थायें या होम्स चलवायें जांय तो अच्छा होगा। जिलाधीश का सब कामों में रखना उचित न होगा क्योंकि उनके पास बहुत से काम होते हैं और उनके कारण वे हर काम पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो मैं आप के द्वारा अपनी सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि वह कदापि जिलाधीशों को अध्यक्ष न बनायें। हमारे समाज को किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को बनायें जिससे उन होम्स का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके।

समाज कल्याण विभाग का कार्य आज कई विभागों द्वारा होता है। उसमें खर्च भी काफी होता है और व्यवस्था में भी झंझट पड़ती है। अगर हमारी सरकार उचित समझे तो मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि समाज कल्याण विभाग का कार्य एक ही विभाग के द्वारा होना चाहिये। कहीं प्लानिंग से हो रहा है तो कहीं और जरिये से हो रहा है। अगर वह एक जरिये से होने लगे तो हमें काफी सुविधा और काफी वर्कर भी मिल जायेंगे।

समाज कल्याण के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा आज जो हमारे सेंटर चल रहे हैं अगर उन्हीं केन्द्रों की और मांग की जाय तो हमें केन्द्र से आधे रुपये मिलते हैं, हमें १०० में केवल २५ ही देने हैं, २५ लोकल जनता देती है। इस प्रकार हमें कम ही खर्च करना पड़ेगा।

हमारे माननीय मंत्रियों ने अपनी तनख्वाहों में एक सौ रुपये की कमी की है। उन्होंने समाजवादी व्यवस्था की ओर कदम उठाया है। उन्होंने समय को देखते हुये कदम बढ़ाया है। इसमें सन्देह की बात नहीं है। हमारे विरोधी दल का कहना है कि उन्होंने एक सौ रुपये की कमी की तो क्या किया, लेकिन आप उनके जीवन को देखिए। वह कोई ऐशोआराम के लिये उन रुपयों को नहीं चाहते हैं। उनको खर्चा तो मिलना चाहिये। सारा जीवन उन्होंने इसी राष्ट्र की सेवा में, कांग्रेस की सेवा में बिताया है वह उसका बदला नहीं चाहते हैं।

आज साधारण घरों का खर्च एक हजार रुपया महीना होता है। तो मंत्रियों के अपने बच्चे पालने के लिये, अपने परिवार के पालन-पोषण के लिये भी कुछ होना चाहिये। वह अपने चौबीसों घंटे देश सेवा में लगाते हैं।

निर्माण कार्यों में तरक्की हुई है। प्लानिंग में तरक्की हुई है। हमने कई और काम बड़े-बड़े बढ़ाये हैं, लेकिन आज हमारे चरित्र गिरे हैं, अनुशासन हमारा मिटता गया है और शिष्टाचार हमें छू कर नहीं जा रहा है।

अंत में मैं बजट प्रस्तुत करने पर धन्यवाद देती हूं।

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस सम्मानित सदन में गत तीन दिनों से, आज चौथा दिन है, हमारे १९५७-५८ के आय-व्ययक पर सामान्य वादविवाद चल रहा है। इस सम्बन्ध में पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि इस बजट के सम्बन्ध में, जहां तक उसकी रूपरेखा का सम्बन्ध है, मैं कोई विशेष विवादास्पद बात कहने नहीं उपस्थित हुआ हूं। मैंने जहां तक बजट को देखा है, और माननीय वित्त मंत्री जी का संकल्प जो भाषण के रूप में है, उसको पढ़ा तो दो बातें मेरे सामने आयीं। पहली यह कि बजट एक सामान्य प्रकार का बजट है जैसा सदैव सभी सरकारों का होता है।

दूसरी बात जो नीति सम्बन्धी है उससे मैं थोड़ी उलझन में हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम इस बजट के द्वारा अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे जो हमारा लक्ष्य समाजवादी समाज स्थापित करने का है। अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आमतौर से समाजवाद की अगर कल्पना की जाय तो सामान्य जनों के मस्तिष्क में कुछ नहीं आ सकेगा क्योंकि आज समाजवाद की विभिन्न परिभाषाएं हैं, कितने ही रूप हैं। उन सब को कहना मैं समझता हूं सीमित समय में और उसके सम्बन्ध में बतलाना, समय का दुरुपयोग होगा। आज विश्व के देशों में हम देखते हैं कि कहीं साम्राज्यशाह समाजवाद चल रहा है। रानी और राजा भी हैं, उनके विशिष्ठ अधिकार भी हैं। फिर भी समाजवाद कहा जाता है। कहीं मार्किस्ट समाजवाद है। कहीं देशों का शोषण और उत्पीड़न है, इधर उधर से उपनिवेशों का बढ़ाना, इस तरह की सरकारें भी समाजवादी कहलाती हैं। इसके साथ ही साथ एक मार्क्स वादी समाजवाद भी है और एक भारतीय समाजवाद की कल्पना भी है। अधिष्ठाता महोदय, मैं तो यह समझता था कि हमारे इस आदरणीय मंत्रिमंडल द्वारा जिसमें हमारे देश के उत्कृष्ट कोटि के समाजवाद के विद्वान मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं, निश्चय ही समाजवाद के सम्बन्ध में एक निश्चित कल्पना, एक सम्पूर्ण मान्यता और एक निर्धारित लक्ष्य हम लोगों को बताया जायगा कि समाजवाद की ओर चलते हुए हमें इतने-इतने कार्य करने हैं। किन्तु मैं समझता हूं कि उस विषय की उपेक्षा की गई और मेरा विनम्र निवेदन है कि वह जानबूझ कर की गई। इसलिये मैं निवेदन करूंगा हमारी सरकार समाजवाद के सम्बन्ध में या तो स्वयं भ्रम में है अथवा दूसरी बात यह हो सकती है कि हमारी सरकार का लक्ष्य वास्तविक कुछ और है जिसे वह कहने में संकोच करती है।

मैंने बजट को जहां तक देखा मैं समझता हूं वह उसी पूंजीवादी पद्धति का समर्थक बजट है जिस प्रकार का शासन आज संसार के बहुत से देशों में पाया जाता है। बहुत से हमारे मित्रों ने इस सम्बन्ध में दूसरे दल की ओर से इस बजट की प्रशंसा की है। कभी कभी मुझे भ्रम हुआ कि संभव है इस बजट के रूप में समाजवाद का एक नया अवतार हुआ है और उसके लिये कितने ही मंगलगान गाये गये, परन्तु प्रमाण स्वरूप जो कुछ कहा गया वह केवल यह कि कुछ अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को ५ रु० की सुविधा दी गई है और साथ ही एक अच्छा निश्चय यह किया गया है कि ७० वर्ष की अवस्था वाले वृद्धों को पेंशन दी जाय। अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिस देश में, जिस प्रदेश में आज प्रति वर्ष जब-जब परीक्षायें समाप्त होती हैं, लाखों जवान यह सोच कर जीवन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं कि उन्हें जीवनयापन की सुविधायें मिलेंगी और वे दूसरों के समान सुख पूर्वक जी

[श्री रामकुमार वैद्य]

सकेंगे और आप भली भांति जानते हैं कि देश में सारे देश में भी बेरोजगारी है और यह प्रश्न बहुत बड़ा है उसको हल करने की दिशा में मैं नहीं देखता इस बजट में कोई सुविधा दी गई है। मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि हमारी सरकार अपनी वित्त क्षमता से बाहर जा कर कुछ करे या करने का प्रयास करे। बहुत से मित्रों ने कहा है विरोधी दल की ओर से कुछ असम्भव कल्पनायें हमारे सामने प्रस्तुत की गईं, लेकिन भाषणों को सुनकर मैं नहीं समझ सका कि कौन सा असम्भव प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से किया गया था। हमारी मांग यह थी कि आप जो कुछ करें उसके सम्बन्ध में एक निश्चित लक्ष्य हो, एक स्पष्ट मार्ग हो और उसके लिये एक दृढ़ संकल्प हो। कौन सा कारण है हम अपनी योजना छोटी न कर सकें, कौन सा कारण है बहुत से विभागों को कम न कर सकें और अपने त्याग से अच्छा स्वरूप उपस्थित करके अपने कर्मचारियों में कार्यक्षमता न बढ़ा सकें ? किन्तु यहां पर सरकार पूंजीवाद की समर्थक है। मैं विनम्रता पूर्वक कहूंगा हमारी सरकार की नीति भी उसी प्रकार है जैसी कि उन सरकारों की जो सरकारें प्रायः इसी तरह की सुविधायें दिया करती हैं। जहां लोग रोटी मांगते हैं वहां एक टुकड़ा दे देना, जहां हम कहते हैं हमारे सामने जीवनयापन का प्रश्न कठिन हो गया है वहां राहत थोड़ी देना और उसके बाद फिर समाजवाद का नारा लगाना, संसार के सामने यह कहना कि हम जनकल्याणकारी राज्य स्थापित करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं समीचीन नहीं है। जब विभिन्न कार्यों के लिये धनराशि उपलब्ध करने का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय इस तरह की भावुकता पूर्ण नारेबाजी से काम नहीं लेना चाहिये ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं रुपये-पैसे की बात हमेशा हिसाब-किताब से ही ठीक रखी जाती है बमुकाबले इसके कि हम नये नये स्लोगन्स दें और जब वास्तविकता देखें तो कुछ भी न हो। मैं पूछना चाहूंगा वित्त मंत्री जी से इस प्रकार का बजट तो, जहां तक मैं जानता हूं, १० बार सदन में आ चुका और कई वर्षों से शासक दल समाजवाद का नारा भी स्वीकार कर चुका। तो उस तथाकथित समाजवाद के सम्बन्ध में कितने कार्य पूरे हो चुके और भविष्य में क्या होगा, किस तरह की रूप रेखा होगी उस समाज की और उसके सम्बन्ध में क्या कार्य आप निश्चित करने जा रहे हैं इसे कहने में आप संकोच क्यों करते हैं ? मैंने माना कि आपको यह शिकायत है कि विरोधी दल आपके सामने यह बात नहीं रखता कि आप यह करें या वह करें। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा अपने माननीय मन्त्री महोदय से कि यदि हम ऐसा नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं। हम भ्रम में हो सकते हैं। हमसे भूल हो सकती है, परन्तु आप पर तो इस प्रान्त की जनता को प्रजातांत्रिक रूप से शिक्षित करने की जिम्मेदारी है। आप पर एक जिम्मेदारी है कि आप एक नया शासनतंत्र, एक नया समाज निर्माण करें किन्तु उस समाज के सम्बन्ध में यदि आपकी कोई कल्पना ही न हो तो यह स्थिति दुखद और असह्य है। अतः मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सरकार को एक स्पष्ट लक्ष्य की घोषणा करनी चाहिए थी। अभी भी उसके लिए समय है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी जब इस सदन में प्रस्तुत किये गए विचारों का उत्तर देंगे तो इस सम्बन्ध में बतायेंगे कि इस वर्ष के लिए उनका समाजवादी लक्ष्य क्या है।

इसके साथ ही साथ एक परम्परा हो गई है कि शासन के दोषों का वर्णन करने की। किन्तु अधिष्ठाता महोदय, मैं वैसा नहीं करूंगा। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि पुलिस में कितना भ्रष्टाचार है, रेवेन्यू में कितना भ्रष्टाचार है, अमुक जगह कितना भ्रष्टाचार है। इसके विपरीत मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो कुछ भी हमसे त्याग करने को कहें हम त्याग करेंगे भूखे रह कर और नंगे रह कर भी। हम अपना सर्वस्व अपने देश के नव निर्माण के लिए अर्पण कर देंगे। किन्तु श्रीमन्, हृदय फट जाता है, बहुत दुख होता है, जब हम देखते हैं कि जिस आयोजना के लिए यह बड़े-बड़े टैक्स लगाये जाते हैं, यह बजट भी जिस

पंचवर्षीय योजना के अधीन प्रस्तुत किया गया है उसको करने का जो यंत्र है यानी प्लानिंग उसमें भी जिले की कमेटियों में बैठ कर देखा जाता है कि भ्रष्टाचार होता है, तो हम किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं। केवल इतने ही शब्दों में अपनी बात रखने को मैं प्रस्तुत हुआ था। आपने मुझे जो इस सदन में बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

*श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन के सामने जो यह बजट प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले तीन चार दिन से इस बजट का इस भवन में भलीभांति पोस्टमार्टम किया गया। विभिन्न पार्टियों के माननीय सदस्यों ने कई किस्म की विचारधारायें अपनी-अपनी पार्टियों की ओर से इस बजट के बारे में पेश कीं। इस बजट को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक देखा। पिछले पांच सालों में भी इस सदन में कई बजट मेरे सामने आये, मगर मैं यह बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि यह सबसे पहला बजट है जिसमें कई किस्म की विचारधारायें इस प्रकार की रखी गई हैं जो कि सोशलिस्टिक पैटर्न की पूरी नहीं तो कुछ अंश तक पूर्ति करती हैं। वैसे तो कितना ही बड़ा बजट बनाया जाय, विरोधी दल कुछ न कुछ तो आपत्ति पैदा ही किये रहेंगे। आप देखें कि इंग्लैंड का ५,६८० करोड़ रुपये सालाना का बजट बनता है। उस पर भी वहां का विरोधी दल कभी अपना संतोष प्रकट नहीं करता जब कि वहां की आबादी हमारे प्रान्त की आबादी के मुकाबले २/३ है। तो हमारे यहां ६ करोड़ ३२ लाख की आबादी के लिए १०८ करोड़ रुपये का बजट बनाने पर हम यह आशा करें कि विरोधी दल भी उसके लिए वाह-वाह करे तो यह एक बड़ी अनोखी सी बात होगी और असम्भव सी बात होगी। तो मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि विरोधी दल इसको राटेन बजट कहे या कितना ही बुरा बजट कहे। मगर यह हम लोगों के संतोष की बात है, ट्रेजरी बेंच को अवश्य इसमें संतोष होना चाहिए कि हमारे देश की जितनी आर्थिक व्यवस्था है उसके मुताबिक जितने अच्छे से अच्छे काम इस बजट के अन्दर किये जा सकते थे उसके लिए प्रयास किया गया है और ईश्वर ने चाहा और भविष्य में इस देश की भी आर्थिक व्यवस्था वैसी सुधर गई जैसी कि पाश्चात्य देशों की है तो एक दिन ऐसा आयेगा कि जब हम इस देश में समाजवादी ढांचे को जिसको कि हम आज एक आवाज या नारे के रूप में रखते हैं, उसको प्रत्यक्ष रूप से देख पायेंगे।

मैं बजट के बारे में बहुत ज्यादा न कह कर खास कर पर्वतीय प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि पर्वतीय प्रदेश के बारे में ट्रेजरी बेंच से अभी तक एक भी माननीय सदस्य न बोल सके। पर्वतीय प्रदेश का जो मसला है वह इन ५२ जिलों में एक अनोखा स्थान रखता है। हमारे बजट का हमेशा यही एक मक्ष्य रहता है कि हम ५२ जिलों में समान रूप से उनके विकास की योजना बनाया करते हैं। मगर पर्वतीय प्रदेश का एक स्थान होना चाहिए। इसी बात को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस विचार धारा पर गम्भीरता से सोचेंगे और देखेंगे कि कहां तक हम लोगों ने पर्वतीय प्रदेश की अब तक अवहेलना की है और भविष्य में इस किस्म की विचारधारा होना चाहिये जिससे जो पिछड़ा हुआ भूभाग है, जहां दुख और दरिद्रता है, जहां न रेल, मोटर या २० वीं शताब्दी की आधुनिक सभ्यता की सहूलियतें हैं जैसे स्कूल, सड़कें या अस्पताल और जहां कि जनता वर्तमान आधुनिक सभ्यता से कोई फायदा नहीं उठा पाती है, वहां की समस्याओं पर इस माननीय सदन को गौर करना चाहिये ताकि वहां की जनता के दुख का निवारण हो सके।

मैं देखता हूं कि हमारे देश में काश्मीर का कुछ पर्वतीय प्रदेश व हिमांचल प्रदेश का पर्वतीय हिस्सा है। वहां केन्द्रीय सरकार की ओर से काम किये जा रहे हैं। वहां की आबादी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट]

२८ लाख है और उसके लिये एक मिनिस्ट्री कायम की गई है जिसमें ७ मिनिस्टर्स हैं, दो स्टेट मिनिस्टर्स हैं। वहां एक तहसील के लिये एक-एक मिनिस्टर रक्खा गया है और केन्द्रीय सरकार उस हिस्से के लिये कई करोड़ रुपया बहा रही है। वहां एम० ए० तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो क्या कारण है कि प्रदेश के जो ५ पर्वतीय जिले हैं देहरादून, टेहरी, गढ़वाल-अल्मोड़ा व नैनीताल और जहां की आबादी २८ लाख है उसके मुकाबले में १० वां हिस्सा भी खर्च न किया जाय। ऐसे ही हिमांचल प्रदेश भी सेंट्रली गवर्न्ड स्टेट है। वहां भी सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। तो क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश जो देश का इतना विशाल सूबा हो वह और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हमारी रक्षा न कर सकें। यह एक बड़ी अनोखी विडम्बना है और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में हरिजन वेलफेयर विभाग खोला गया है, सोशल वेलफेयर विभाग खोला गया है उसी प्रकार हिल रीजन के लिये एक वेलफेयर विभाग अलग खोल देना चाहिये ताकि वहां की समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा सके और इस प्रकार वहां की आर्थिक व सामाजिक समस्याओं को हल किया जा सके।

अगर वहां एक स्कूल या अस्पताल खोल दिया गया, एक मोटर सड़क बना दी गई तो इससे पहाड़ की समस्या हल नहीं हो जाती। वह एक डेफिसिट एरिया है जहां न धनोपार्जन के साधन हैं, क्योंकि वहां न कोई व्यापार है, न कोई इंडस्ट्री है और न वहां इतना अन्न उपजता है जिससे वहां की जनता को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके। इन समस्याओं को हल करने के लिये एक बड़ी योजना वहां के लिये बनानी पड़ेगी। अगर अनाज भेज कर आप वहां अन्न की पूर्ति करते रहेंगे तो चेरिटी में वहां की जनता हमेशा नहीं रह सकती। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वहां के लिये एक अलग विभाग होना चाहिये जिसका नाम हिल रीजन वेलफेयर डिपार्टमेंट होना चाहिये, जो २८ लाख निर्धन गरीब पिछड़ी हुई जनता वहां है, उसके दुःख का निवारण कर सके। वहां की जनता दुखी व दरिद्र दिखाई देती है। यह इसलिये कि वहां की जनता मेटीरियल प्रास्पेरटी की तरफ ध्यान न दे कर आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अपनी प्रवृत्ति रखती थी। नतीजा यह आ कि जनता वहां की संतोषी रही और दुख व दरिद्रता में पलती रही, लेकिन अब समय आ गया है जब सर्वोन्मुखी विकास की योजनायें चल रही हैं, वेलफेयर स्टेट बन रही है, सोशलिस्टिक पेटर्न का नारा दिया जाता है तो यह आवश्यक है कि हमारे प्रान्त का पहाड़ी इलाका जो सब से अधिक पिछड़ा हुआ है उसकी ओर सर्व प्रथम ध्यान देना चाहिये और कोई योजना कार्यान्वित की जानी चाहिये।

मुझे कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन सारांश में ही दो तीन बातें कहना चाहता हूं, खास कर तराई भावर में जो कि टनकपुर से हरद्वार तक एक बेल्ट का इलाका है, उसमें पहाड़ की जनता को बसा दिया जाय और वहां खेती करा दी जाय और जैसे पीलीभीत में एक कालोनाइजेशन की स्कीम चालू है जिसमें १०,००० एकड़ में आबादी की जायगी, तो ऐसे ही अगर इस बेल्ट में भी आबादी की जाय, पहाड़ की जनता को बसा दिया जाय तो वह समस्या कुछ हल हो सकती है।

पहले अंग्रेजों के जमाने में पर्वतीय प्रदेश से बहुत रेक्रूटिंग हुआ करता था, वह से मिलिटरी में बहुत लोग लिये जाते थे। अब वह चीज बन्द हो जाने से वहां की रोजी का कोई जरिया न रहने से, बहुत ज्यादा गरीबी फैल गयी है। इसलिये सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित किया जाय ताकि वहां से आर्मी में काफी परसोनेल लिये जा सकें।

पर्वतीय प्रदेश के कई हिस्सों में कई छोटे-छोटे जिले बने हुए हैं, इनमें रिआर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे नैनीताल जिले में ढाई लाख की आबादी है,

गढ़वाल मे साढ़े छः लाख और अल्मोड़ा में साढ़े सात लाख है। बड़े अनईल्डी से जिले हैं, न आयात-निर्यात के साधन हैं, न प्लानिंग की व्यवस्था, न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ठीक तरह से फंक्शन कर रहे हैं। तो इस इलाके के जिलों का रिआर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। साथ ही जितना रुपया प्लेन्स में दिया जाता है, उतना ही हिल डिस्ट्रिक्ट में दिया जाता है। पिथौरागढ़ में जो प्लानिंग का काम चल रहा है, उसके लिए १५,००० रुपया दिया जाता है। इतने रुपये से क्या बन सकता है। इतना रुपया तो ओवरहेड चार्जेज में खर्च हो जाता है, विकास की कोई योजना कार्यान्वित नहीं हो सकती।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मेरी समझ में प्रस्तुत बजट बड़ा महत्वपूर्ण बजट है। वह इसलिये कि द्वितीय निर्वाचन के बाद हमारे प्रदेश में जो सरकार बनी, उसका यह सर्वप्रथम बजट है, दूसरी पंच वर्षीय योजना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं भी प्रदेश की करोड़ों जनता की भांति बड़ी आशा और उम्मीद के साथ इस बजट का इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। शासक दल ने अभी चन्द महीनें पहले जनता के सामने कुछ वादे किये थे जैसे आम जनता की जिन्दगी को ऊंचा उठाने का, प्रदेश में एक समाजवादी प्रकार के समाज की व्यवस्था करने का, शासन में फैले हुए भ्रष्टाचार को दूर करने का और जनता के ऊपर टैक्सों के बढ़ते हुये बोझ को कम करने का। मैंने समझा था कि उसकी तरफ कदम आगे बढ़ेंगे। आम जनता की जिन्दगी के मियार को उठाने के लिए, साधारण जन-जीवन का स्तर ऊंचा उठाने के लिये, यह सरकार इस बजट में कुछ व्यवस्था करेगी, लेकिन मुझे घोर निराशा हुई।

समाजवादी प्रकार के समाज की रचना का नाम लेकर के, इसको समाजवादी बजट कह कर के बचा नहीं जा सकता। मेरी समझ में यह बजट एक रोज़ी पिक्चर (गुलाबी तस्वीर) जनता के सामने पेश करता है,। इसको अगर मैं डिसेक्टिव बजट कहूं, धोखा देने वाला बजट, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बजट में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन पर बड़ा गर्व किया गया है। हरिजनों के लिये कहा गया है कि हरिजन और पिछड़े वर्ग के जो टी० बी० के मरीज होंगे उनके लिये २३,००० रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है। कितनी मजाक और मखौल की बात है कि २३,००० में तो टी० बी० के २३ मरीजों की दवा भी नहीं हो सकती है और महज कानपुर जैसे शहर में जाने कितने २,३०० मरीज इस वर्ग के होंगे।

हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये ९५,००,००० रुपये की व्यवस्था की गयी है। हरिजन, जो इस प्रदेश का एक अभागा और बदनसीब तबका है और सब से बड़ा वर्ग है, उसकी क्या हालत है? लखनऊ विश्वविद्यालय के जे० के० इंस्टीट्यूट द्वारा एक सर्वे लखनऊ, कानपुर और मेरठ में किया गया है, मैं उसके आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। उनसे विदित हो जायगा कि इस तबके की क्या स्थिति है। आज भी हरिजनों के पांच व्यक्तियों वाले परिवार में लखनऊ में १.२ एकड़ भूमि है, मेरठ के अन्दर ०.३ एकड़ भूमि है और इस वर्ग के कर्जे की हालत यह है कि कर्जे स तबाह है। इस सर्वे से पता चलता है कि आज भी हरिजनों के अन्दर लखनऊ में ७३.३, मेरठ में ९३.३ और लखनऊ कानपुर नगरों में ७५ प्रतिशत लोग कर्जे से लदे हुए हैं और वह क्रमशः २२, २५ और १८ प्रतिशत की दर से सूद अदा करते हैं। आज भी हरिजन परिवार की ऐवरेज इनकम जो है वह ३२.७ है, लखनऊ में ५१.६ है, मेरठ में ७१.९ रुपये प्रति परिवार पड़ती है जब कानपुर तथा लखनऊ शहरों में आप दावा करते हैं कि आपने प्रति व्यक्ति आय २७६ रुपये कर दिया है।

श्रीमन्, किसानों के लिये इस बजट में बहुत ज्यादा कहा गया है और यह कहा गया है कि उनके लिये बड़ी व्यवस्था की गई है, उनके लिये बड़ी भारी मेहरबानी की गई है और हमारे प्रदेश में अन्य प्रान्तों की अपेक्षा कम टैक्स हैं। यही तो मैं कहता हूं कि इस बजट में धोखा देने की बात कही गई है, जब कि किसानों से हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा लगान वसूल किया जाता है। इसके आंकड़े टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ने प्रस्तुत किये है वह इस प्रकार हैं कि वेस्ट

[श्री चन्द्रजीत यादव]

बंगाल में ०.८३, बम्बई में १.८६, पंजाब में १.६७, मैसूर में ०.९८, बिहार में ०.७७, और यू० पी० २.८९ है। इससे साफ जाहिर है कि सब से ज्यादा टैक्स हमारे प्रदेश में पड़ता है। फिर भी इस बात के लिये सीना ताना जाता है, सिर ऊंचा किया जाता है कि हमने जनता की जिन्दगी को ऊंचा उठाने के लिये ऐसा बजट पेश किया है जो समाजवाद के लक्ष्य की तरफ आगे ले जाने वाला है।

आप ने दर्जा ६ तक की शिक्षा बच्चों की मुफ्त की है। इस दर्जे तक शिक्षा पाने के लिये अगर किसी गरीब का बच्चा जायगा तो उसको शिक्षा मुफ्त मिलेगी और यदि अरबपति कमलापति सिंहानिया का लड़का भी जायगा तो उसको भी शिक्षा इस दर्जे तक मुफ्त मिलेगी। समाजवादी राज्य के अन्दर ऐसी चीज नहीं हुआ करती है। वहां तो तरीका यह होता है कि गरीबों के ऊपर टैक्स का भार कम पड़ता है और धनी वर्गों के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इस बात को गत अप्रैल में स्वीकार किया था कि इस कांग्रेसी सरकार के अन्दर गरीबों की गरीबी बढ़ी है और धनी लोगों का धन बढ़ा है। कुछ चन्द लोगों की मुट्ठी में धन सिकुड़ कर आ गया है। क्या यही आपकी समाजवाद की व्यवस्था है कि धनियों का धन ज्यादा बढ़े और गरीबों की गरीबी ज्यादा बढ़े?

अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करूं कि हमारे देश के अन्दर और विशेष कर हमारे प्रदेश के अन्दर जमींदारी टूटने के बाद से मध्यम वर्ग की दशा बिगड़ती चली जा रही है, चाहे नौकर पेशा लोग हों या किसानों के बीच में रहने वाले हों, लेकिन इन लोगों के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। उसका जिक्र तक नहीं किया गया है। आज बेकारी हमारे यहां मुंह बाये खड़ी है। हमारे यहां के नौजवान भटकते हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं? यूनिवर्सिटीज की तालीम हासिल कर के ठोकर खा रहे हैं। कहा जाता है कि पापुलेशन बढ़ रही है, हम क्या करें। हम रोजगार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जन संख्या बढ़ती जाती है। क्या आपने इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिये कोई व्यवस्था की? इस बजट में फेमिली प्लानिंग की कोई चर्चा तक नहीं है, इसकी तरफ कोई ठोस कदम उठाया जायगा, इसका संकेत तक नहीं है। इस तरह की बातों को कह कर बहुत दिनों तक जनता को धोखे में नहीं रखा जा सकता। चाहे आप कागजी आंकड़ों के अम्बार लगा दें, लेकिन जनता की आंख पर पट्टी बांध नहीं सकते हैं, जनता सब समझ जाती है। इस बजट की एक ही कसौटी है और वह यह कि अगर जनता खुशहाल है तो आप का बजट अच्छा है और अगर जनता की मुसीबत बढ़ी है, परेशानी बढ़ी है, तो आप का बजट चाहे उसकी कितनी ही प्रशंसा कर लें, लेकिन वह किसी काम का नहीं है।

माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई दी गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि उनको बधाई किस बात के लिये दी जाय। बधाई की पात्र तो वह जनता है जिसने पिछले चुनाव में आपको एक ठोकर मारी। उसका नतीजा यह हुआ कि आप संभले और आपने समाजवादी व्यवस्था का नाम लेना शुरू किया। वह दिन दूर नहीं है अगर आपने वास्तविकता स्वीकार नहीं की और हवा में बातें करते रहे तो जनता आपको जवाब देगी। वह समझती है कि किस तरह से सरकार को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। आपने दस साल से उसको आशा और विश्वास दिलाया है, लेकिन अब उसके धीरज का बांध टूट चुका है। मेरा तो सरकार पर यह चार्ज है कि जो वास्तविकता है उससे आप आंख मूदते हैं। पूर्वी जिलों में भुखमरी की स्थिति है भूख से मृत्यु होती है। आजमगढ़ में भूख की ज्वाला में तड़प-तड़प कर एक हरिजन बालक मर जाता है और सरकार के एक मंत्री जा कर वहां बयान देते है कि पूर्वी जिलों में अन्न की कोई कमी नहीं है। कमलाराय की मृत्यु पुलिस के मारने से हवालात में होती है और हमारे पुलिस मंत्री कहते हैं कि जुडिशियल इन्क्वायरी की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने आत्म हत्या कर ली है। गृह मंत्री ने कहा कि देवरिया में कम्युनिस्ट लूट मचाना चाहते थे

यद्यपि यह वास्तविकता नहीं है। परन्तु मैं कहता हूं कि अगर यही रवैया आपका रहा तो जनता लूटेगी और आपकी हुकूमत को उलट देगी। एक तरफ तो भुखमरी है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आप जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को, उसके खून की कमाई को मौज की जिन्दगी में उड़ा रहे हैं। आपके सरकारी कर्मचारी, चाहे वे इंजीनियर हों, चाहे पुलिस का कर्मचारी हो उनके ऐशो आराम के बंगलों को जाकर आप देखिये। मैं तो उस आजमगढ़ जिले से आता हूं जहां के किसानों की जमीनें छीनी गई और आज उन जमीनों पर ऐसे सुन्दर बंगले इरीगेशन डिपार्टमेंट के और विकास के बने हुये हैं, मालूम होता है कि नई दिल्ली और लखनऊ का एक कोना वहां उतर आया है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि वह वास्तविकता को देखे और अपनी आंख पर पड़े हुये पर्दे को उठाये और तब आगे बढ़े।

आज शिक्षा और यूनिवर्सिटियों की हालत क्या है? आज लखनऊ और इलाहाबाद की युनिवर्सिटियां पार्टीबाजी का अड्डा बन रही है, उनकी अटोनामी खतरे में है और इस सरकार से सम्बन्धित लोग बिला वजह उनमें हस्तक्षेप करके विद्यापीठ को दूषित बना रहे हैं। वहां उनके आदमी रखे जाते हैं और हास्पिटल बोर्ड के मेम्बर होते हुये भी ८७ लाख रुपये का हास्पिटल का ठेका लेते हैं, लेकिन कुल ६ लाख रुपया वसूल किया जाता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--प्वाइंट आफ आर्डर। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि विवाद के लिये अब केवल दो घंटे रह गये हैं और बोलने वाले सदस्य अधिक दिखाई पड़ते हैं और शायद मंत्री जी भी जबाव देने में एक घंटा ले लें। इसलिये बजाय १५ मिनट के अगर १० मिनट का समय कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री अधिष्ठाता--आपको मालूम होना चाहिये कि अब १० मिनट का ही भाषण हो रहा है, १५ का नहीं।

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--चेयरमैन साहब, तीन दिन से सन् १९५७-५८ के बजट पर इस सदन के सामने बहुत भाषण हुये, बहुत सी चर्चायें हुई और मेरा खयाल है कि कम से कम हमारे विरोधी भाइयों ने इस अवसर पर अपने-अपने दल के राजनीतिक दर्शन की व्याख्या करने में ज्यादा समय दिया। यह सही था कि अपने-अपने दल के राजनीतिक दर्शन की व्याख्या की जाती, लेकिन उसके साथ में मुझे सिर्फ एक चीज पर एतराज है। सोशलिस्ट भाई अपने चौखम्भा राज्य की बात करें, अपनी नौ मांगों को पढ़ कर सुनायें, हमारे कम्युनिस्ट भाई श्री झारखंडे जी और उनके साथी भाई उन बातों का जिक्र करें जिनको इस देश में सुनने की बहुत समय से हमको आदत है, बात करें नेशनलाइजेशन की बात करें भ्रष्टाचार करने वालों की, सदन के सामने, कौंसिल हाउस के सामने गोली मारने की, हमारे मित्र जिन्होंने अभी इस सदन के सामने भाषण दिया वे जिक्र करें कि लूट के बारे में उनकी धारणायें ऐसी हैं, गृह मंत्री जी ने जो उस सम्बन्ध में कहा उसका उन्होंने जिक्र किया, लेकिन वह इसको एक तरह से तसलीम करें और हमारे पी० एस० पी० वाले भाई, माननीय नेता विरोधी दल, यद्यपि मुझे इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि उनके पास अपनी कोई विशेष राजनीतिक वचारधारा नहीं है। गाँधी जी का नाम वे भी लेते हैं, हम भी लेते हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--हम ऐसी बात नहीं सुनना चाहते कि हमारे पास कोई विचारधारा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--आप कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं रेज कर रहे हैं? आचार्य जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि मेरा खयाल है कि यह सदन उनका अनुगृहीत होगा यदि वह कोई बात कहते परन्तु उन्होंने कोई इस प्रकार की कोशिश नहीं की कि कोई अलग विचारधारा इस सदन के सामने रखते। उन्होंने कुछ और बातों की चर्चा

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

की जिनका जिक्र इस परिमित समय में मैं करने की चेष्टा करूंगा, लेकिन मुझे यह एक निवेदन करना है कि एक बात के सम्बन्ध में मुझे एतराज है। हमारे ढंग के समाजवाद से आप क्यों इतना उलझना चाहते हैं। हमारा समाजवाद हमारे पास है। कृपा करके यह याद रखिये कि उस समाजवाद की बिना पर हम यहां चुन कर आये हैं। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उस समाजवाद के सम्बन्ध में हमारी जो धारणा थी वह दृढ़तर होती चली जा रही है। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस समाजवाद की हम चर्चा करते हैं वह मार्क्स का लिखा हुआ ८० वर्ष पुराना समाजवाद नहीं है, जिस समाजवाद की चर्चा हम करते हैं वह स्टालिन और लेनिन का समाजवाद नहीं है, हमारा वह समाजवाद नहीं है जिसके हाथ खून से रंगे जा चुके हैं। जो हमारा समाजवाद है वह हमारे अपने परीक्षण द्वारा और अपने अनुभव के आधार पर और संसार भर में जो समाजवाद के परीक्षण किये गये उनके आधार पर जो समाजवाद का परीक्षण हमने स्वयं बनाया है, वह समाजवाद है। हम समझते हैं कि उस समाजवाद से वर्गहीन समाज की स्थापना होनी चाहिये, हम समझते हैं कि उससे सम्पत्ति का धन बढ़ा कर उसके न्यायपूर्ण बटवारे की व्यवस्था होनी चाहिये। हम समझते हैं कि हमारे समाजवाद में हिंसा और गोली को स्थान नहीं दिया जाना चाहिये। हम समझते हैं कि हमारे समाजवाद में मिक्स्ड एकानामी को स्थान होना चाहिये और हम यह भी स्पष्ट समझते हैं कि जिस समाजवाद की चर्चा हमारे मित्र ने की उस पर इस देश ने बहुत विचार किया है और उसका बहुत अनुभव इस दुनिया ने किया है। श्रीमन्, मुझे बहुत स्पष्ट कहने दें कि उस समाजवाद से आज मानवता कराह रही है। उस समाजवाद से जिसके जरिये से हिंसा, ईर्ष्या और द्वेष का प्रसार हो, जिसके जरिये से मानव मनोवृत्ति, मानव संतुलन, मानव विचार परिपाटी की हत्या हुई हो, जिस समाजवाद को इस समाज ने ठुकरा दिया हो, हमने भी ठुकरा दिया है। इसलिये मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कृपा करके हमारे समाजवाद के लिये क्यों माथा पचाते हैं। आप उसे नहीं समझ सकेंगे क्योंकि आपके दिमाग पर तो उस प्रकार का समाजवाद चढ़ा है जिसने दुनिया को ऐटम बम दिया है, उस समाजवाद का जिसने दुनिया में हिंसा का प्रसार किया है और जिस समाजवाद के कारण आज मानवता कराह रही है। मेरा ख्याल है कि शायद मानवता के पास कोई दूसरा मार्ग नहीं रहा है सिवाय इसके कि इस बापू के समाजवाद के द्वारा अपने उत्थान के मार्ग को स्वीकार करें। इसलिये श्रीमन्, मैं बहुत विनयपूर्वक निवेदन करता हूं कि हमारे समाजवाद को हमारे पास रहने दीजिये। हां, चर्चा करें उस समाजवाद की जिसको हमने स्वीकार किया है और जो कुछ हम आज प्रत्यक्ष और व्यहारिक रूप से देश और इस प्रदेश को देना चाहते हैं कृपा कर के उसकी चर्चा कीजिये। यदि हमारी कोई गलतियां हैं तो उनको बताइये, लेकिन कृपया इस गरीब मुल्क की गरीबी को भी नजरंदाज करने की कोशिश न करें।

सन् १९२१ में इस देश की आबादी २१ करोड़ थी और सन् १९५१ में वह ३६ करोड़ हो गई। सेंसस रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा जाता है कि सन् ६१ में वह ४१ करोड़ हो जायगी। सिर्फ ८३ करोड़ एकड़ भूमि है जिस पर इस देश के इन्सान रहते हैं। करीब २ एकड़ भूमि हिस्से में आती है। इसके अलावा साधनों की कमी है, कपड़ों के व्यापार को चौपट किये जाने की ब्रिटिश हुकूमत की योजना है जिसके जरिये से सारा बोझ खेती पर पड़ा है और जिसके जरिये से आज देश के इन्सान की हालत यह हो गयी है कि ३६ करोड़ में महज १४ करोड़ राष्ट्रीय सम्पत्ति के कामों को कर सकें। उन ३६ करोड़ आदमियों में से महज ६ लाख आदमी ऐसे इस देश में हैं जो ४,२०० से ज्यादा आमदनी पर इन्कमटैक्स देते हैं। ४,२०० और १० हजार के बीच की आमदनी पर ७७ फीसदी आदमी जिनको इस देश में इन्कमटैक्स देने का मौक़ा मिलता हो और इस प्रकार से इस गरीब मुल्क के बारे में मेरे मित्र जब चर्चा करते हैं तो मैं बहुत अदब से यह कहना चाहता हूं कि मुझे दुःख होता है। मेरे मित्र आज ही चाहते हैं कि वह सारी चीजें हो जायं। वह सारी चीजें तो यूटोपिया में भी मिलने की गुंजाइश नहीं

है । अपने गरीब मुल्क से गरीबी दूर करने का आज हमने व्रत लिया है कि हम अपने देश से गरीबी दूर करेंगे। आप उसको किस प्रकार करेंगे। मैं पोलैन्ड की बात जानता हूं, स्वीडन की बात जानता हूं। पूर्वी यूरोप और अन्य देशों की वार्ता भी जानता हूं जिन्होंने अपने खेती के बजाय बड़ी इंडस्ट्री पर हाथ डाला है और आज वह दुखी हैं और व्यग्र हैं। उनके सामने चारा नहीं है। आज उनके सामने सवाल यही है कि दोबारा खेती की तरफ जांय।

हमारे देश की सारी इकोनामी और सारी अर्थव्यवस्था खेती के ऊपर आधारित है और खेती के आंकड़े प्रस्तुत करने की यदि मुझमें क्षमता है तो इतना ही कह सकता हूं कि १९४७ म जब कि यहां से अंग्रेज गये तो ३६ करोड़ आदमियों को १७ १ २ करोड़ एकड़ भूमि पर छोड़ गए जिसपर खेती होती है। आज सारी समस्या और कठिनाई इस बजट के सम्बन्ध में जो है उस पर आप के जरिये मैं उनसे कहने की जुर्रत करता हूं कि वह कृपाकर विचार करें। कोई एक प्लानिंग का स्वरूप मानकर किसी जनतंत्री देश के जरिये से स्वीकार नहीं किया गया। कभी भी फ्रान्स, यू० के० और यूनाइटेड स्टेट्स में प्लानिंग की पिक्चर मंजूर नहीं की गई । रूज़-वेल्ट के जमाने में अमेरिका पर आपत्ति आयी तो उन्होंने अपने यहां एक विशेष आयोग और एक विशेष कानून बनाया, लेकिन वह केवल थोड़े से दायरे में रख कर उन्होंने प्लानिंग करने की कोशिश की। इसी प्रकार से यू० के० में प्लानिंग कभी आज तक नहीं हुई । सोशल सर्विसेज़ की प्लानिंग करने की कोशिश की । रूस ने भी कुछ दूसरी प्लानिंग स्वीकार की और चीन ने भी कुछ स्वीकार की। हमने भी एक प्लानिंग की तस्वीर को स्वीकार किया। मुझे अपने मित्र की बातों पर हंसी आयी और आश्चर्य हुआ। एक मित्र ने कहा मैं उनकी बात की क़दर करता हूं कि उनका यह ख्याल है और उन्होंने ईमान्दारी के साथ यह कहा कि हम अपना ढांचा तैयार करते हैं पुरानी नीव पर। यदि मैं उनके शब्दों को दोहराऊं तो उसका मतलब यह है कि पुरानी तस्वीर हम तैयार करते हैं नए चौखटे में। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारी चौखट वह है जो कभी किसी देश में बनायी नहीं गयी। जिस चीज़ को हमने डेमोक्रेटिक सेट-अप में स्वीकार किया है वह पुरानी नीव कहां है। इसके लिये क्या हमारे देश का अधिकार नहीं है? मेरे मित्र आखिर टीका टिप्पणी करें और दूसरी बातें करें, मेरे मित्र कलेक्टिव फार्मिग की बातें करें और मेरे मित्र कुछ भी बातें करें। इसी सम्बन्ध में मैं वह भूला नहीं हूं कि एक मित्र यह शिकायत करें और उनको कोई पार्लियामेंटरी शब्दों से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, वर्ना वह गाली भी दे सकते हैं। तो वह तो इस प्रकार की बातें करें और हमारी सही बात भी उनको सही नजर नहीं आती। हमने डेमोक्रेटिक सेट-अप में प्लानिंग को स्वीकार किया है, इसके सम्बन्ध में हमारी लिमिटेशन्स हैं और हमारी सीमायें हैं।

आज इस बजट के सम्बन्ध में बहुत चर्चा हुई है और किसी भाई ने कहा कि आज इसके सम्बन्ध में यह नहीं है और वह नहीं है। मैं केवल एक चीज़ की इस परिमित समय में चर्चा करूंगा। मैं टैक्सेशन के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि जो यह घाटे का बजट है उसके सम्बन्ध में ज़िक्र करूंगा, लेकिन मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक सेट-अप में हमने यह प्लानिंग स्वीकार की है और उसके लिये हमारे पास हमारी सीमायें हैं। मैं यह भी कहूं कि हमारा यह बजट केवल प्लानिंग का बजट है, हमारा बजट दूसरी पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये एक कदम है। इस प्लान के लक्ष्य को पूरा करने के सिवाय इधर-उधर हमारा बजट जा नहीं सकता। आज हम यह नहीं कर सकते कि प्लानिंग के लक्ष्य को पूरा न कर के यह कहें कि सारा का सारा रुपया किसी और एक स्थान पर खर्च कर दिया जाय। प्लानिंग की निर्धारित योजनायें हैं, ऐसी योजनाओं के अन्दर हमें काम करना है। उन योजनाओं में हमें २५३ करोड़ रुपया खर्च करना है, उसको कहीं से पाना है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को हमने पूरा किया । उससे कितना लाभ देश को हुआ, अगर इस सदन में कभी समय मिला तो उसको मैं बतलाऊंगा ।

मेरे मित्रों ने घाटे के बजट का ज़िक्र किया तथा टैक्सेशन का ज़िक्र किया। घाटे का बजट है, यह मैं मानता हूं। यह भी सही है कि हमें ४२ करोड़ रुपये के लगभग देना

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

है उसके लिये हमने सिंकिंग फण्ड कायम किया है। यह घाटे का बजट हमारी जैसी अर्थ-व्यवस्था है, उसको ठीक करने का एक बड़ा भारी साधन है।

मेरे मित्र ने ज़िक्र किया सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्सेज़ का। उन्होंने (Taxation Enquiry Committee) के ८० सफे का ज़िक्र कर दिया। मैं उस को पढ़ देना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र नेता विरोधी दल ने ज़िक्र किया कि जो टैक्सेज़ लगाये गये हैं उनका गांवों के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। उन टैक्सेज़ में उन्होंने लैंड रेवेन्यू का भी ज़िक्र किया।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--मैंने नहीं किया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सदन में आपने नहीं कहा कि लैंड रेवेन्यू भी टैक्स है तो सदन में किसी दूसरे माननीय सदस्य ने ऐसा कहा था।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अधिष्ठाता महोदय, मैं देख रहा हूं कि माननीय मित्र को १५ मिनट हो चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता--चूंकि आप गवर्नमेंट की ख्वाहिश से बोलने के लिये खड़े हुये थे इसलिये उनको ५ मिनट ज्यादा दे दिये। मैं अब आचार्य जी से दरख्वास्त करूंग कि वे जल्द खत्म करने की कोशिश करें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यदि आप चाहें तो अभी खत्म कर दूं, लेकिन अगर एक मिनट का वक्त और दे दें तो अच्छा हो।

तो मैं यह कह रहा था कि ८० सफे का ज़िक्र किया। मैं आप के सामने ३९ पैराग्राफ की तीन पंक्तियों को पढ़ देना चाहता हूं। उससे जो टैक्सेज़ इस देश और प्रदेश में चालू हैं और उनका जो प्रभाव इस देश और प्रदेश में हो रहा है उसका थोड़ा सा ज्ञान उससे हो सकता है--

"Thus taking into account the increases in total tax revenue under important taxes like land revenue, income-tax, central excise, sales tax and import duties, and the relative incidence of these taxes on the rural and urban sectors, it would seem that the total burden of taxation has increased in the urban sector as compared to the pre-war period."

मैं हिन्दी में इतना ही कहूंगा कि सारे टैक्स जो केन्द्र की ओर से लगाये जाते हैं उनका यह असर पड़ा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले में शहरी क्षेत्रों में टैक्स का बोझ ज्यादा बढ़ा है।

अब बस मैं इतना ही कह कर समाप्त करूंगा कि हमारा यह देश जब आजाद हुआ तो हम सब सदन के सदस्य उस वक्त मौजूद थे। अब हमारी जिन्दगी में ही हमें यह भी मौक़ा मिला है कि हम इस देश को बनते देखें। उसको बनने में सहायता देने की मैं अपने सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात के लिये धन्यवाद देना है कि कम से कम २५, ३० दफा उठने बैठने के बाद आखिर मुझे १० मिनट मिल ही गये। मैं माननीय उप मंत्री जी के भाषण को सुनने के साथ-साथ उनकी हरकतें भी देख कर बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि किस जोश के साथ वे अपने हाथों को भी हिलाते जा रहे थे। मालूम नहीं कि उनका मस्तिष्क भी काम कर रहा था या नहीं काम कर रहा था। उन्होंने अपने समाजवाद की तारीफ करने में बहुत समय लगाया, लेकिन मैं उनके समाजवाद को समझाने में दो-तीन मिनट ही लूंगा। उनका समाजवाद तो यह है कि बड़ी-बड़ी मोटरें छोड़ कर

अब वे छोटी पर उतर आये, उनका समाजवाद तो यह है कि १,२०० रुपये की तनख्वाह से हट कर अब १,१०० रु० पर चले आये, उनका समाजवाद तो यह है कि अदालतों में जो भ्रष्टाचार भरा हुआ है उसमें कमी करने के लिये उसकी तरफ अंगुली तक नहीं उठा सके, उनका समाजवाद तो यह है कि ग्रामीणों में जो निर्धनता फैली हुई है उसके लिये सिवा आंकड़ों में बात करने के आप कोई दूसरी बात ही नहीं उठा सकें, उनका समाजवाद तो यह है कि गांधी जी की कही हुई सब बातों को भुला कर अपनी ही बात को कहते रहें। क्या गांधी जी ने नहीं कहा था कि हमारे गवर्नर झोपड़ियों में रहने वाले हों, हमारे मंत्री लोग किसानों के प्रतिनिधि हों? क्या उनका समाजवाद यही है कि लखनऊ से नैनीताल में जा कर वहां ऐश आराम की जिन्दगी व्यतीत करें? उनका समाजवाद तो सिर्फ लफ्जों में है। मैं पूछता हूं कि क्या यह उचित है कि जिस सरकार की तरफ से बजट पेश हो उसी तरफ के सदस्य लोग उसी के पिष्टपोषण में खड़े होकर सदन का समय बरबाद करें। यह तो गरीब और देहातों की अपढ़ जनता के धन का अपव्यय करना है। जनता के प्रतिनिधि तो बिलकुल सरल स्वभाव के तथा साधारण वषभूषा वाले होने चाहिये, लेकिन आप तो बिलकुल इसके खिलाफ मालूम होते हैं। मुझे तो श्रीमन्, बहुत सी बातों का जवाब देना था, लेकिन मैं अपना समय उन में न लगा कर दो चार विशेष बातों में लगाना चाहता हूं। जिस ट्रेजरी बेंच की तरफ से बजट पेश हुआ है उसी की तरफ के अनेक सदस्य खड़े हो कर उसकी तारीफ करते हैं। आप ने बजट पेश किया और.....

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य को मैं बतला दूं कि मैंने बजट नहीं पेश किया है। आप मुझको ऐड्रेस कर के गवर्नमेंट के लिये कहें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आप को ही ऐड्रेस कर रहा हूं। बार-बार मैं श्रीमन् नहीं कह पाता हूं। तो मैं कह रहा था इस तरह से बार-बार ट्रेजरी बेंच के लोगों को मौका दे कर इस तरह से तो सदन के समय का दुरुपयोग करना है। उसको तो बड़े गौर से विरोधी दल की बातों को सुनना चाहिये, जो उनकी कमियां बतला सकें, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिनको कि अधिष्ठाता महोदय नहीं हटा सकते हैं।

मैं तो अपने विरोधी दल के नेता और विरोधी दल के सदस्यों के सम्बन्ध में ही कुछ कहना चाहता हूं कि वे सही माने में अपने तर्कना और बहस से ही केवल गवर्नमेंट को नहीं समझा सकते हैं।

(इस समय ३ बज कर १८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

बहस व तर्कना के साथ-साथ कुछ ठोस कार्य भी करना होगा। यहां भी कहा गया कि विरोधी दल द्वारा तो भाषण ऐसे होते हैं जो ड्रेनेज इंसपेक्टर की रिपोर्ट जैसे होते हैं या और भी इस तरह की बातें कही गयीं। ऐसी-ऐसी बातें सुनने के लिये हम यहां नहीं आते हैं। मैं विरोधी दल के नेता तथा विरोधी दल के सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि अगर केवल बहस तर्कना से ही काम होने को होता तो ये सीटें जो आज मेरे पीछे खाली दिखलाई देती हैं वे खाली नहीं रहतीं। तर्कना से ही समस्या का हल नहीं होता है। केवल तर्कना से ही कोई चीज फलवती नहीं होती। इसके लिये ऐक्शन की जरूरत होती है। जिस तरह से सोशलिस्ट पार्टी ने कुछ चीजों के लिये क्रियात्मक कदम उठाया है उसी तरह का कदम आपको भी उठाना चाहिये। मुझे अफसोस है कि इतना बड़ा सत्याग्रह सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से किया गया जिसमें हमारे चार हजार से अधिक भाई जेलों में गये, लेकिन विरोधी दल के माननीय नेता ने अपने ढाई घंटे के भाषण में उस सत्याग्रह के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा। मैं जानता हूं कि वे बुद्धिमान हैं, लेकिन उनके भाषण में उसका कुछ भी जिक्र नहीं हुआ। यह बड़े ही दुख और शर्म की बात है। हमारे अन्य सदस्य तथा साथी जो हमारे बीच में बैठे हैं, वे तो हमारे साथ हैं, लेकिन हम अपने इस ओर के नेताओं के लिये क्या कहें। हम यह आशा अवश्य करते हैं कि हम आपस में मिल कर चलें। अगर हम आपस में डिवाइड रहेंगे

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

तो सरकार को हम नहीं समझा सकेंगे और अपनी बात नहीं मनवा सकेंगे। उधर से खड़े होकर कहा जाता है कि हमारी तरफ से मर्ज तो बताया जाता है, लेकिन उस का कोई इलाज नहीं बताया जाता और दूसरे माननीय सदस्य उधर से यह भी कहते हैं कि जब तक हम जिन्दा हैं तब तक भ्रष्टाचार रहेगा। अगर ऐसी बात है तो क्या मैं कहूं कि ईश्वर करे कि वह अब जिन्दा न रहें।

मैं अध्यापक वर्ग से आता हूं और शिक्षा से मेरा सम्बन्ध रहा है इसलिये उसके विषय में मैं थोड़ी सी बात कहूंगा। कहा जाता है कि इस बार ६० प्रतिशत विद्यार्थी इसलिये फेल हो गये, क्योंकि ये लड़के दर्जा ३ से एक दम ६ में कर दिये गये थे। मैं समझता हूं यह बात बिलकुल गलत है। मैं अध्यापक रहा हूं, मैं इसका कारण जानता हूं। मैंने विद्यार्थियों को पढ़ाया है और उनकी दिक्कत और कमजोरी का मुझे पूरा ज्ञान है। इसका कारण यह है कि उन विद्यार्थियों पर अंग्रेजी का बोझ इतना डाला गया है और यह एक बड़ा भारी पाप उन पर लादा गया जिससे उनकी मुक्ति नहीं हो पाई है। आपको यह मालूम होगा कि ७ और ८ साल की उम्र से ही बच्चों के ऊपर यह अंग्रेजी का बोझ डाल दिया जाता है और उनको सी० ए० टी० —कैट और डी० ओ० जी०—डाग माने बिल्ली और कुत्ता सिखाया जाता है, रटाया जाता है, वह मजबूर होते हैं और रट रट मरते हैं, लेकिन फिर भी उनको अंग्रेजी नहीं आती। मैं चेलेंज करता हूं और दावा करता हूं कि अगर आप आज पाठ्यक्रम से अंग्रेजी हटा दें तो यह जो ६० प्रतिशत लड़के फेल होते हैं वह न हों और ८५ फीसदी पास होने लगें और इस तरह से ४० प्रतिशत नतीजा न रहे। जब तक हम अंग्रेजी नहीं हटाते, हमारे बच्चों का और शिक्षा का उद्धार नहीं हो सकता। यह अंग्रेजी अब हमारे बच्चों के जीवन मरण का सवाल हो चुकी है। मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि अगर आप कल इसको हटा दें तो परसों ही हमारा नतीजा ८५ प्रतिशत हो जायगा और इस तरह की मखौल और खिलवाड़ बच्चों के साथ न करें। अब गुलामी का जमाना नहीं रहा आज हालत यह है कि बड़े-बड़े ग्रेजुएट भी और बड़े-बड़े एम० ए० भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख बोल सकते, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे पड़े हैं। बड़ी-बड़ी जो सरकार की रिपोर्टें आती हैं वह अंग्रेजी में आती हैं। राशनेलाइजेशन की रिपोर्ट अंग्रेजी में आई और बिना अंग्रेजी के आज आप का काम ही नहीं चलता, बिना अंग्रेजी की रिपोर्ट पढ़े और समझे आप का काम ही नहीं चलता। मैं सरकार से कहूंगा कि इस तरह के अंग्रेजी के प्रोत्साहन को छोड़कर अब वह मातृभाषा की ओर देश को उस विदेशी भाषा के पाप से बचावे।

इसी तरह से पी० डब्ल्यू० डी० विभाग का हाल है। वहां पर प्लन्डर विथआउट डेंजर की बात बिलकुल लागू होती है। होता यह है कि एक्जीक्युटिव इन्जीनियर से लेकर नीचे के ओवरसियर और क्लर्क तक का सब का परसेंटेज बंधा हुआ है और सब ठेकेदारों से बाकायदा वसूल किया जाता है और किसी ठेकेदार को इतनी हिम्मत नहीं है कि वह उन का हिस्सा न दे। अगर कोई नहीं देता है तो वह इस विभाग में काम ही नहीं कर सकता और ठहर नहीं सकता। सरकार को इस चीज की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

इसी तरह से अदालतों की हालत है जिस की तरफ मैं सरकार का ध्यान आप के द्वारा दिलाना चाहता हूं। आप को एक माननीय सदस्य ने १०९ और ११० की तो बहुत सी कहानियां सुनायीं, लेकिन मैं आप को १०७/११७ की कहानी सुनाता हूं। यह दफा एक तमाशा सी बन गयी है, इन मामलों में आठ-आठ महीने तक मैजिस्ट्रेटों के यहां मामले पड़े रहते हैं। अगर जरा कोई दो चार औरतें ही लड़ने लगीं तो उनका चालान १५१ या १०७/११७ में कर दिया जाता है। इस तरह से कानून का बड़ा दुरुपयोग किया जाता है। इस तरह से लोगों को दबाया जाता है और तरह तरह से दमन नीति अपनायी जाती है। मैं तो आप से आशा करूंगा और कहूंगा कि आप इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे ४,००० भाई जेल में बन्द हैं, उनकी ओर सरकार ध्यान दे। मैं सरकार को मजबूर करना चाहता हूं कि उनकी तरफ वह आंख घुमायें। उन्होंने एक ऐक्शन किया और सरकार ने उसको मान लिया। सरकार ने

मूर्तियां हटायीं। सरकार अपनी हार मानने को तैयार न हो, लेकिन अब खाली कल्पना से काम नहीं चलेगा। वह समाजवाद की बात करते हैं और बार-बार चुनौती देकर कहते हैं कि हमारा समाजवाद यह है, लेकिन उन के चेहरों से पता चलता है कि उनका समाजवाद उनके जेब में है। उनकी जेबों में १२ सौ रुपये जाते हैं, चेहरे पर रौनक है और जनता की चिन्ता नहीं जो भूखों मर रही है, जिसके पास पैसा नहीं।

श्री बंशीधर शुक्ल---एक मिनट हमें बोल लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---किस विषय पर?

श्री बंशीधर शुक्ल---एक मिनट में आप से पूछना यह है कि अगर हमें बोलने का मौका न दिया करें तो हमें असेम्बली में बुलाते किस लिए हैं? सत्ता पार्टी की ओर से तानाभरी बातें सुनने के लिए हम लोग असेम्बली में नहीं आते हैं। हम यह आप से कहते हैं कि अगर हमें मौका न दें, तो हमारे पास और भी काम हैं।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप शांत रहेंगे या नहीं?

मैं किसी को बोलने के लिए नहीं बुलाता। जो माननीय सदस्य यहां आते हैं, जिस पर मेरी निगाह पड़ जाती है मैं बुला लेता हूं। इस किस्म की धृष्टता मेहरबानी करके अब न करें। आज मैंने रियायत कर दी। चेयर के लिए इस तरह से लांछन देना मुनासिब नहीं है। मैं आशा करता हूं, आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं इस बजट पर कहने से पेश्तर अपने वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं कि यह पेश करदा बजट नये टैक्सों के बोझ के बावजूद भी एक बड़ा संतुलित बजट है। यह एक सच्चा समाजवादी बजट है जिस में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टरों की तरक्की का पूरा-पूरा ख्याल रखा गया है।

यह ठीक है कि कुछ टैक्स कीमतों के बढ़ जाने की हकीकत का कारण हो सकते हैं, मगर इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी हालत में यह टैक्स इस से कम नहीं किये जा सकते थे। जब तक हमारी नयी दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूलचूल परिवर्तन न किया जा सकता.....

श्री उपाध्यक्ष---सदन में शांति होनी चाहिए। मैं देखता हूं शोर गुल हो रहा है।

श्री एस० जी० दत्त---यह बजट सोशलिस्ट पैटर्न का बजट है। जिसे हमारे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भाई पूंजीवाद का बजट कह कर पुकारते हैं और पूंजीवादी इस बजट को घोर कम्युनिस्ट बजट कह कर पुकारते हैं। हकीकत यह है कि यह एक सच्चा समाजवादी बजट है। उस सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी की तरफ इस समाजवादी बजट का पहला कदम है। यह बजट दो उसूलों पर मबनी है। पहला यह कि इस सूबे के रहन-सहन को ऊंचा करना और दूसरा दौलत की तकसीम ऐसी हो जो ऊंच नीच के फर्क को हमवार करे। इसके अलावा जनता को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट के मुलाजिमीन को रियायतें देने के लिए इस बजट में खास ख्याल रखा गया है। सरकार की तरफ से सरकारी मुलाजमीन को तालीम में रियायत दी गयी है। वह जिनको तनख्वाह १०० रुपये से कम या १०० रुपये तक है, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए नवें क्लास तक हाफ़ फ्रीशिप दी गयी है और उम्मीद है कि अगले साल भी इसी तरह से बजट में टेंथ क्लास में फ्रीशिप होगी। उसके साथ ही साथ आम जनता जिस में कि अमीर और गरीब का फर्क नहीं रखा गया छठी क्लास तक सरकार ने मुफ्त तालीम देने को कहा है। यह एक बड़ी चेंज है, हकीकत है। इसका अगर विरोधी दल वाले महज इस लिए विरोध करें कि यह सरकार की तरफ से आयी है तो मैं समझता हूं कि यह उनका गलत रवैया है। कम से कम विरोधी दल में से किसी ने भी इसकी तारीफ नहीं की जो जनता के फायदे की चीजें

[श्री एस० जी० दत्त]

हैं। वह गरीब जो अपने बच्चों को प्राइमरी तक तालीम नहीं दे सकता था, आज छठी क्लास तक मुफ्त तालीम दे सकता है और वह वक्त भी आयेगा, हथेली पर सरसों नहीं जमायी जा सकती, जब टेन्थ क्लास तक फ्री तालीम होगी। यह मेरा विश्वास है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे सज्जन जो किसानों के खैरख्वाह नजर आते हैं वही हैं जो कल तक राजा, जमींदार थे, किसानों का खून चूसा करते थे। आज वह सोशलिस्ट बने हैं। अगर आपका नजरिया सोशलिस्ट पैटर्न का है तो मैं तो यह कहूंगा कि यही एक सबूत है सोशलिस्ट पैटर्न का कि ऐसे लोगों की जहनियत चेंज हो गयी। उसके बावजूद मिनिस्टरों के ऊपर और दूसरे कांग्रेसमेन के ऊपर आप यह दोष लगाते हैं कि मोटरों में घूमते हैं, बंगलों में रहते हैं, महात्मा गांधी ने यह कहा था, वगैरह वगैरह। मैं ऐसे लोगों से यह कहता हूं भाई तुम तो अभी महलों में रह रहे हो। काश वह जगह किसानों के लिए अस्पताल ही बना दी होती। वह भाई जो अभी जनसंघ के टिकट पर आये हैं, दावा करते हैं समाजवादी हैं और चुनाव में मजहब के नाम पर वोट लेकर आये। यह तो समाजवादी हैं और यह उनकी जहनियत है तो फिर उसकी जवाब देही क्या की जा सकती है।

मुझे यह कहना है कि सरकार नें जो बूढ़े आदमियों के लिए पेंशन की व्यवस्था की है, अगर आध फी सदी भी उन की पापुलेशन इस में रख लें तो ६ करोड़ के ऊपर आप अन्दाज लगा लीजिये कि कितने बूढ़े होंगे जिनको यह पेंशन मिलेगी और उनकी गुजर होगी। उसके बावजूद विरोधी कहते हैं नहीं साहब यह तो मिनिस्टरों की ही इतनी जिन्दगी हो सकती है औरों की नहीं हो सकती। मालूम होता है खुदा ने इन्हीं की जिन्दगी इतनी लिखी है और किसी की नहीं।

इसी तरह से बिजली में भी २० से २५ फी सदी तक कमी की गयी है, जिससे हमारी इन्डस्ट्रीज को फायदा होगा। ऐसे-ऐसे रिलीफ इस बजट में हैं जो सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ कदम जाहिर करते हैं।

मैं सरकार की तवज्जह अपने रिफ्युजी भाइयों की तरफ दिलाना चाहता हूं और बेशक ये लोग जब आये तो सरकार के ऊपर बहुत सारा बोझ पड़ा और सरकार ने उसको उठाया, रुपये पैसे से मदद की और दूसरे तरीके से मदद की। तालीम के लिहाज से उन के बच्चों की मदद की जो कि अब नहीं है। मैं सरकार से खासकर कानपुर के लिए प्रार्थना करूंगा कि वहां पर दूकानें और उन के लिए मकान वह मुहय्या करें। अगर सरकार के पास कोई ऐसे साधन नहीं हैं तो कम से कम उन को जमीन दे और कर्जा दे जिस से वे अपने मकान बना सकें। कर्जे जो दो हजार तक में हों सरकार उन को माफ कर दे और जो कर्जे हैं उन की बाबत सरकार इतना जरूर करे कि उनकी किस्तें आहिस्ता-आहिस्ता ले और यह भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार रिफ्युजी डिपार्टमेंट को अब बन्द कर दे, क्योंकि जब तक यह रिफ्युजी डिपार्टमेन्ट रहेगा, तब तक रिफ्युजी प्राबलम कभी हल नहीं हो सकता। कर्जे वगैरह की वसूली म्युनिसिपल और डेवेलप्मेंट बोर्डों के जरिये से कराये। आखीर में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं फिर वित्त मन्त्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं और समाप्त करता हूं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आप को बधाई दूं कि आपने इस सदन में और इस बजट के ऊपर मुझे बोलने के लिए मौका दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारे कांग्रेसी वक्ता महोदय बोल रहे थे उनकी विरोधियों से यह खासतौर से शिकायत थी कि किसी भी विरोधी ने माननीय वित्त मन्त्री जी को बधाई नहीं दी। तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्या इस बजट पर बधाई देने के लिए ही सब से आशा की जाती है। बधाई देने के लिए तो कांग्रेस की ओर से काफी व्यक्ति हैं और मैं समझता हूं कि जो भी व्यक्ति खड़ा होता है वह पहले और अन्त में केवल बधाई ही देता है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी जो सदस्य महोदय ने हम विरोधियों और खास तरीके से राजाओं पर जो विरोधियों की ओर बैठे हैं उन पर कटाक्ष किया है। जन संघ के लिए कहा है कि वह मजहब पर

वोट लेकर यहां आये हैं, तो मैं कहता हूं कि क्या जनसंघ भी कोई मजहब है ? क्या कोई राजनीतिक पार्टी भी मजहब होती है । यह मेरी समझ में नहीं आया कि यह बात उन्होंने कैसे इस सदन के सामने प्रस्तुत की ? एक बात जो उन्होंने राजाओं के सम्बन्ध में कही तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो आज सत्तारूढ़ बनी है, तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं मैं समझता हूं कि समस्त भारत वर्ष में उसने चुनाव में जीतने के लिए राजाओं के पल्ले पकड़े हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इन बातों पर न जाकर बजट के विषय में कुछ कहूंगा । श्रीमन्, इस बजट में जो कहा गया है कि यह बजट समानता लाने के लिए प्रस्तुत किया गया है, तो यदि इसको सामानता का नहीं असमानता का द्योतक समझा जाय तो ज्यादा ठीक होगा । इस बजट में गरीबों की गरीबी और अमीरों के अमीरी बढ़ी है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो गरीब किसान इस देश में अधिकतर देहातों में रहता है, जो प्रकृति से ही सताया हुआ है, आज देश स्वतंत्र हुये दस साल हो गये , परन्तु उस की ओर जितना ध्यान गया है वह तो दुनिया जानती है । किसान के ऊपर आज कितनी मुसीबत है, जब कि शहर वाले या ये धनवान व्यक्ति जो कोठियों में आराम करते हैं, धूप में बिजली के पंखों के नीचे रहते हैं और किसान दोपहर की उन जलती हुई लपटों में अपने खेतों में काम करता है और हम सब के लिये गल्ला पैदा करने का प्रयास करता है वह देवता किसान अगर अपना कार्य करना छोड़ दे तो सम्भव है यह ऊंची-ऊंची अट्टालिकायें रौनक विहीन हो जायं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहूंगा कि उस गरीब किसान के लिये कितना अधिक धन रखा गया है इस बजट में ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं देखता हूं कि वह किसान जो सन् ४७ में मुसीबत भोगता था आज भी वह मुसीबत भोगता है । अगर इस बात को ठीक तरह से आंका जायगा तो कितने देहात हैं जहां अस्पताल खोले गये, कितने स्कूल खोले गये और कितनी सड़कों का निर्माण हुआ और जानवरों के लिये कितने हास्पिटल बनाये गये ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पता चलेगा कि जहां गरीब व पिछड़ा हुआ वर्ग रहता है उस के लिये कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

नदियों के किनारे प्रकृति के मारे जो व्यक्ति रहते हैं, उदाहरण के लिये इटावे में जमुना व चम्बल के बीच का जो क्षेत्र है , जहां सड़कों पर तो क्या आदमी बैलगाड़ियों पर भी नहीं चल सकते, जहां साइकिल भी नहीं चल सकतीं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । दस साल स्वतंत्रता प्राप्त किये हुये हो गये लेकिन आज तक वहां एक भी ट्यूब वैल नहीं बना, सड़क का निर्माण नहीं हुआ । वहां सिंचाई के लिये कोई साधन नहीं । न प्रथम पंचवर्षीय योजना में और न द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अभी तक वहां कुछ हुआ । उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं इतना पिछड़ा हुआ यह क्षेत्र है कि जहां एक हाई स्कूल अभी तक नहीं है और वहां कोई ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई कि वहां पर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को ठीक तौर पर से पढ़ा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर चिकित्सा की ओर ध्यान दिया जाय तो उस क्षेत्र में न अस्पतालों की व्यवस्था है न कोई जच्चा बच्चा गृह के लिये ही व्यवस्था है और न ही जानवरों के लिये अस्पताल बनाये गये हैं । अगर दुर्भाग्य या सौभाग्य से एक आध अस्पताल है तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह पायेंगे कि वहां डाक्टर नहीं पहुंचता । इटावा जिले में सहसों स्थान पर एक अस्पताल है । मैंने सिविल सर्जन महोदय से पूछा कि वहां डाक्टर की नियुक्ति क्यों नहीं हुई और कब से नहीं हुई तो जवाब मिला कि वहां कोई डाक्टर जाना चाहता ही नहीं । केवल कम्पाउंडर ही वहां पहुंचता है वह भी इनागिना, वर्ना डाक्टर और कम्पाउंडर विहीन वहां का अस्पताल रहता है । तो ऐसे स्थान पर जहां कि नौकरशाही के आदमी चिकित्सा के लिये भेजे जाते हैं और वे वहां जाना पसन्द नहीं करते तो वहां के ग्रामीण लोग जो हमेशा से वहां रहते हैं कैसे अपना जीवन बिताते होंगे ?

निर्माण की ओर देखा जाय तो उपाध्यक्ष महोदय, बरसात में कोई साधन नहीं जिस से वहां कोई अपना मार्ग तय कर सके । एक भी पुल वहां नहीं बना और अगर कोई सफर भी करता है तो अपने स्थान पर पहुंच ने के लिये तीन दिन का समय उसे लगता है । यह है डेमोक्रेसी, स्वतंत्र भारत की परिभाषा ।

[भुवनेशभूषण शर्मा]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई मुकदमा होता है तो चूंकि बरसात में आर पार जाने के लिये केवल एक ही नाव एक दिन में डाली जाती है तो अपनी तारीख पर पहुंचने के लिये एक दिन पहले व्यवस्था करनी पड़ती है। बिचार करने की बात है कैसी विडम्बना है कि एक ही स्थान पर दो तरह का व्यवहार। आपको रुपये के दोनों पलुओं को देखना होगा। यदि एक भी ओर रुपया खोटा है तो उसे खोटा माना जायगा। इस बजट में अगर इन पिछड़े हुये स्थानों के लिये या पिछड़ी हुई जातियों के लिये व्यवस्था की गई होती तो मैं ही नहीं सभी ओर से इस का स्वागत होता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार पिछड़ी हुई जातियों से या पिछड़े हुये क्षेत्र से टैक्स वसूल नहीं करती? क्या सेल्स टैक्स नहीं लेती? क्या भूमि टैक्स नहीं लेती, या पंचायत टैक्स नहीं लेती? जो टैक्स लेने की व्यवस्था है, टैक्स लिया जाता है। फिर क्या वजह है कि दस-दस साल हो जाते हैं और कोई भी व्यवस्था वहां उन गरीबों के लिये नहीं की गयी।

*श्री मुहम्मद सुलेमान अधमी (जिला बस्ती)---जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस मौके पर, जब कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने सन् ५७-५८ के बजट को पेश किया है, और उस की हर एक बात पर गौर करने के बाद और यह देखने के बाद कि इस में आम जनता की खास तौर से भलाई है, उन को मुबारकबाद देता हूं, और खासतौर से इसलिये मुबारकबाद देता हूं कि हमारे उस तरफ़ के भाइयों में से चन्द ने तो खड़े होकर यह भी कह दिया कि इधर से कोई मुबारकबाद, उनका कहने का मतलब यह था, उनको नहीं दी जायगी किसी प्वांइंट पर। तो हम भी यह कहते हैं कि---"तुम अपनी ख् न छोड़ोगे हम अपनी रविश क्यों बदलें"। हम तो मुबारकबाद देंगे ही। हम समझते हैं कि उनका बजट अच्छा है, वह सोशलिस्टिक पैटर्न का बजट है, इसलिये वह इस काबिल है कि हम उन को मुबारकबाद दें।

दूसरी बात हम को यह कहनी है कि इस डिमाक्रेसी के जमाने में हम ट्रांजीशनल पीरियड से चल रहे हैं और उस में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को लेकर के चल रहे हैं, अगर्चे कुछ लोगों ने यह कहा है कि ---

"For forms of Government let fools contest, for what is governed best, is best."

अगर्चे यह ठीक है, लेकिन हमारा जो बजट है, जो इस वक्त पेश है वह दरसल सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का बजट है और इस में दो राय नहीं हो सकती हैं। मुझे अफसोस है कि हमारे उस तरफ के भाई ने किसी ने भी इंसाफ से काम नहीं लिया और मैं इस में अपने विरोधी दल के नेता श्री त्रिलोकीसिंह से भी अर्ज करूंगा कि उन्होंने इंसाफ से काम क्यों नहीं लिया? वह एक कल्चर्ड आदमी हैं। आखिर कुछ चीजें तो इस बजट में अच्छी होंगी, एक ही सही, दो ही सही। बुड्ढे आदमियों के मुतल्लिक है, फीस माफ करने के मुतल्लिक है, लेकिन क्या यह इन्साफ का तकाजा नहीं था कि आप उस की कुछ तारीफ करते? हम आप से ऐसी उम्मीद करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ",दुनिया ने हर हकीकत अफसाना बना दी, हम ने हकीकतों को भी अफसाना कर दिया।"

श्री चन्द्रजीत यादव---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। आप ने यह कहा है कि श्री त्रिलोकी सिंह एक कल्चर्ड आदमी हैं और हम उन से यह उम्मीद करते थे जो पूरी नहीं हुई, तो इस का मतलब यह है कि वह अनकल्चर्ड आदमी हैं, और यह अनपार्लियामेंटरी है।

श्री उपाध्यक्ष---वह तो यह तसलीम करते हैं कि वह कल्चर्ड आदमी हैं, लेकिन जितनी वह उम्मीद उन से करते थे वह पूरी नहीं हुई। इस में कोई ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा माननीय त्रिलोकीसिंह को कोई ऐतराज नहीं है, इस लिये कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुहम्मद सुलेमान अधमी--हां, तो श्री त्रिलोकीसिंह का जिक्र था, तो मैं उन्हीं पर एक बात और अर्ज करूंगा कि मैं उन की एक राय से इत्तफाक नहीं करता हूं, यानी उन्होंने अपनी तकरीर में कुछ अपने मुताल्लिक भी कहा था और यह कहा था कि हिन्दुस्तान की शायद इकोनोमिक कंडिशन ऐसी नहीं है कि वह अपनी शादी कर सकें ।

श्री त्रिलोकीसिंह--मेरे पास शादी का पैग़ाम लेकर कोई नहीं आया इसलिये कि मुफ़लिसी का आलम रहा ।

श्री मुहम्मद सुलेमान अधमी--मैं समझता हूं कि जो लोग पैगाम लेकर नहीं गये तो यह उनकी गलती थी, क्योंकि ऐसे सज्जन आदमी की शादी जरूर होनी चाहिए थी।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि व्यक्तिगत बातें न उठायें । इससे कटुता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आप बजट के ऊपर ही कहें ।

श्री मुहम्मद सुलेमान अधमी--जनाबवाला, बजट के सम्बन्ध में ही है। अगर आप की शादी हो जाती, तो जितना रुपया आपने इलेक्शन्स में खर्च किया उसको आप अपनी फेमिली पर ही खर्च करते तो उससे नेशनल वेल्थ तैयार होती, क्योंकि आप बहुत ही कल्चर्ड फेमिली के हैं ।

मैं एक बात अपने कम्युनिस्ट भाइयों से अर्ज करूंगा, क्योंकि उनको किसानों से बड़ी हमदर्दी है। मैं अपने भाई झारखंडे राय जी से कहूंगा कि वह अपनी सेना, हमारे यहां की जो कांस्टीटयुएंसी बस्ती में है, उसका मुलाहिजा करें। मेरे जाती तजुर्बे की बात है। मैं अर्ज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह तवज्जुह देंगे । हमारी कांस्टीट्युएंसी नैपाल से मिली है और वहां के लोग बहुत ही बैकवर्ड हैं । आप के जो साथी हैं, उन्होंने वहां यह हरकत शुरू कर दी है कि जो किसान अच्छे खाते-पीते होते हैं, वे वहां पहुंच जाते हैं और उनसे २५, ३०, ४० और ५० रुपये देने को कहते हैं । अगर वे नहीं देते हैं तो ५०० आदमियों की फौज कुदाल और फावड़ा लेकर वहां पहुंच जाती है और खोदना शुरू कर देती है । (आवाजें शेम शेम) मैं कहता हूं कि आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखा दूंगा और लोगों के नाम बता दूंगा जो इस तरह की हरकत करते हैं । वहां तीन थाने हैं--(१) लोटन, (२) चिल्हिया और (३) उसकाबाजार । वहां के सब-इन्स्पेक्टर्स किसानों का अच्छा चरागाह समझते हैं और जानते हैं कि बैकवर्ड लोग हैं, इन से ज्यादा पैसा मिल जायगा । इसलिए वे वहां रहना पसन्द करते हैं और इन भाइयों की इन जबरदस्तियों पर परदा डालते हैं। मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि इन थानों का इन्तजाम होना चाहिए और आप से अर्ज करूंगा कि मेहरबानी करके तशरीफ लायें और हालत को दुरुस्त करें। अगर आपकी किसानों से हमदर्दी है तो उनको बचायें।

दूसरी बात यह है कि बहुत से भाइयों ने यह कहा कि जो डी० ए० में ५ रुपये बढ़ाये गये हैं, वह ज्यादा होने चाहिए थे । मैं कहता हूं कि १५-२० रुपये बढ़ा दिये जायं । इसमें करोड़ों रुपया खर्च हो जायगा । तो इसके माने यह हैं कि टेक्सेशन हो, जिस से आप घबराते हैं, हालांकि सिसरो ने कहा है कि "taxations are the sinews of a Nation" यानी टैक्सेशन जरूरी है। अगर टैक्स न लगायें तो दूसरी चीज यह होगी कि गवर्नमेंट के कामों में कमी कर दी जाय। अगर यह भी न हो तो रुपया या नोट्स बढ़ा दिये जायं, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जायगा। रफ्ता रफ्ता हमारे साधन बढ़ेंगे तो हम बढ़ा देंगे। मैं अर्ज करूंगा कि अगर पैसा कम होगा तो डेवेलपमेंट में सर्फ नहीं कर सकेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

श्री तेजबहादुरसिंह (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में सन् १९५७-५८ के लिए १०८ करोड़ ३० लाख रुपये का बजट पेश किया गया है। उस पर बहुत सी चर्चायें की गयीं। उनको मैं गौर से सुनता रहा। खर्चे के लिए जो धनराशि

[श्री तेजबहादुरसिंह]

मांगी गयी है वह इसलिए कि कांग्रेस सरकार की ओर से समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना की जायगी। समाजवादी ढंग के समाज की परिभाषा भी बहुत लोगों ने की। बहुत लोगों की परिभाषायें तो मेरे दिमाग में नहीं उतरीं मगर आचार्य लक्ष्मीरमण जी ने जो परिभाषा की वह मेरे दिमाग में उतरी। उन्होंने बापू की तसवीर की ओर हाथ उठा कर बहुत सी बातें कहीं। उस पर मुझको एक देहात का किस्सा याद आ गया। एक बुढ़िया बीमार पड़ी। उसका लड़का डाक्टर के पास गया। डाक्टर ने एक मिक्सचर दिया और लड़के से कहा कि जरा इस दवा को हिला के पिलाना। बेचारा लड़का बहुत समझदार नहीं था। उसने बजाय शीशी को हिलाने के बुढ़िया को कई बार हिलाया जिसका नतीजा यह हुआ कि बुढ़िया मर गयी। वही हालत इस सरकार की है। बापू ने तो समाजवादी ढंग के समाज का नुस्खा दिया। यह सरकार उसको कार्यान्वित करने में उतनी समझदारी नहीं बरत सकी और समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना की जो बात कही गयी वह केवल भुलावा है। आचार्य जी ने जो पहली परिभाषा दी, उसमें कहा कि हमारा तो समाजवाद है वर्गविहीन और जातिविहीन समाज की स्थापना करना। मैं जरा उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कैसे वर्गविहीन और जातिविहीन समाज की स्थापना कर सकेंगे जब एलेक्शन के लिए टिकट भी आप जाति के नाम पर देते हैं। मुझको तो इसमें सन्देह है चाहे माननीय पालीवाल जी और त्रिलोकी सिंह जी को हो या न हो। उन्होंने और कई बातें बतायीं। उनकी एक बात मुझे जरूर पसन्द आयी जो मैं अर्ज कर दूं और अगर वह चाहें तो मैं उन्हें उसके लिए बधाई भी देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि हमारा जो बजट है वह पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह बात सही है। आप इतनी धनराशि खर्च करने की मांग करते हैं, ठीक है, लीजिये। मगर आप की हालत तो उस गाड़ीवान की सी है जिसके बैल सड़क पर चले जा रहे हैं और वह सोया हुआ है। वह यह नहीं देखता कि बैल किधर जा रहे हैं, चाहे वे पेड़ से लड़ कर मरें, चाहे किसी मोटर गाड़ी से लड़ कर मरें। सरकार की भी ठीक वही हालत है। वह लम्बी धनराशि चाहती है। हम मंजूरी देने के लिए तैयार हैं मगर आप यह तो देखें कि यह खर्चा कैसे होता है। रुपया पानी की तरह बहाया जाता है, मगर उन के कान पर जूं नहीं रेंगती।

आचार्य जी ने महात्मा गांधी की तस्वीर की ओर रुख करके एक बात और कही कि हमारा समाजवाद महात्मा गांधी के बताये हुए ढंग का है। महात्मा गांधी ने जब कभी भी चर्चा की तो विकेन्द्रीयकरण की चर्चा की। मगर पांच वर्षों से तो मैं स्वयं देख रहा हूं कि सरकार के जितने काम होते हैं उनमें वह अपने अफसरान के हाथ मजबूत करती है। अपने हाथों में अधिकार लेना चाहते हैं, किन्तु मैंने यह नहीं देखा कि जनता के हाथों में भी अधिकार देना चाहते हों। उधर से यह कहा जा सकता है कि पंचायतों का संगठन किया है, लेकिन आप पंचायत राज्य एक्ट को देखें, कोआपरेटिव ऐक्ट को देखें या जिलाधीशों को जो अधिकार दिये गये हैं उन को देखें तो पता चलेगा कि आपका विकेन्द्रीयकरण कैसा है। कलेक्टरों के अख्तियारात इतने बढ़ाये गये हैं कि वे हिटलर और मसोलिनी की तरह हैं। मिनिस्टर साहबान जब दौरों पर जाते हैं तो उनको भी यह देखकर अच्छा लगता है कि उनकी एक बगल में कलेक्टर है और दूसरी तरफ सुपरिन्टेंडेंट बैठता है जिनको आप सारे अधिकार दे बैठे हैं। जिला कमेटी का प्रेसिडेंट बैठ जाय तो उनको उतनी प्रसन्नता नहीं होती। कोआपरेटिव ऐक्ट को देख लीजिये। सरकार ने रजिस्ट्रार को हिटलर बना दिया है और सारे कोआपरेटिव के अख्तियारात उनको दे डाले हैं। आप कहते हैं कि नान-आफिशियल आन्दोलन होना चाहिए, मगर रजिस्ट्रार हर जगह पर दखल देने के लिए खड़ा कर दिया गया है। आप जो भी ऐक्ट मंजूर कराते हैं उनको गौर से देख लें तो आप को पता चलेगा कि आप विकेन्द्रीयकरण नहीं बल्कि केन्द्रीयकरण कर रहे हैं। यह तो आपके समाजवाद की बात हुई।

जरा आप देहात की ओर चलिये। मैं तो बहुत आंकड़ों के जाल में नहीं पड़ता, मगर आप देहात में जाकर देखिये तो आपको मालूम हो जायगा कि जो गरीब था वह और अधिक गरीब

हो गया है। सारा धन शहरों में खिसकता चला आ रहा है। शहरों के आदमी मोटे हो रहे हैं और किसान जो खेतों में १२, १४ और १८ घंटे काम करता है उसकी हड्डियां दिखायी देती हैं, उसके शरीर पर मांस नहीं है चाहे हमारे शरीर पर मांस बढ़ जाय। इस बात को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी स्वीकार किया है कि उनके राज्य में गरीब अधिक गरीब हुआ है और धनिक अधिक धनी। उन्होंने यह पिछले अप्रैल में राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में स्वीकार किया था। यह तो है ही कि शहर के लोग अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन जब वह गरीब शहरों में आता है तो वहां उसको वकील लूटते हैं, महाजन लूटते हैं और मुकदमों के फैसले में और तरीके से भी लूटे जाते हैं। इसको हमारी सरकार के सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं।

चाहे हिम्मत न हो कहने की, लेकिन सब जानते हैं कि घूसखोरी बढ़ गयी है और इतनी जितनी की अंग्रेजी राज्य में उसकी चर्चा नहीं की जाती थी। आज हर व्यक्ति उसकी चर्चा करता है और ज्यादातर लोग इसके शिकार हैं। हमें दुःख है कि बहुत से ऐसे विभाग थे, जिसमें उम्मीद नहीं की जाती थी कि वहां भी पर घूस चलती होगी, लेकिन अभी दो तीन दिन की बात है कि ट्रेजरी में मैंने स्वयं एक कर्मचारी को अपने सामने घूस लेते हुए देखा। मैंने जो आदमी घूस देता था उसको डांटा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, हम लोग यहां खड़े हैं, लेकिन तुम घूस देकर और लेकर यह सिद्ध करना चाहते हो कि हम तुम से कहते हैं कि दो। वह किसी तरह से भागा। तो ट्रेजरी में जहां कुछ नहीं करना है जहां कतई ओब्लाइज नहीं करना है वहां घूस चलती है तो औरों की बात तो जाने दीजिये।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)––माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में बजट के ऊपर बहस होते हुए यह चौथा दिन है और माननीय हाफिज जी द्वारा इस १९५७–५८ के वार्षिक आय-व्ययक का ब्योरा लेखा सदन में प्रस्तुत किया गया है, उस पर सभी ने बहुत ही विचार से सुझाव और अपने अपने मत व्यक्त किये। मैं सारे विवाद को सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि समय का बहुत ही कम सदुपयोग किया गया है। बहुत से माननीय सदस्यों ने समाजवाद के ढांचे की व्याख्या करने में अपने भाषणों में समय बहुत सा लगा दिया है और इस प्रकार से वे सब जो स्पष्ट सुझाव देना चाहते थे, समय के अभाव के कारण वंचित रह गये। यहां पर जैसा कि न्यायालय में वाद-विवाद यानी डिफेंस और आफेंस के लिए विवाद का तरीका होता है उसी तरह से दोनों दलों की तरफ से एक ढंग अपनाया गया है। इधर के भाई जो कि प्रशंसक के रूप में कहे जा सकते हैं और विरोधी दल के भाई जो आलोचक कहे जा सकते हैं, दोनों इस सीमा का उल्लंघन करके अपने विचारों से बहुत दूर हो गये हैं। हमारा फर्ज यह नहीं होना चाहिए। यहां पर वह स्थान है जहां पर हम दोनों दलों को एक जगह मिलकर देश के हित के लिए जो अच्छे सुझाव और अच्छी बातें होनी चाहियें, भेदभाव को मिटाकर स्पष्ट हृदय से, व्यक्त कर सकते हैं।

मैं जैसा कि यहां पर बजट का समय निर्धारित है उसको सोचते हुए अपने विचार इस बजट के सम्बन्ध में व्यक्त करना चाहती हूं। माननीय हाफिज जी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पिछली पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए अपना बजट पेश किया है। यह गौरव की बात है कि उनको यह अवसर मिला। उनका यह एक और भी सराहनीय कार्य है कि उन्होंने बजट में एक विशेष कदम कटौती करके उठाया है जिसके लिए मैं सोचती हूं कि एक अच्छी मिसाल हम लोगों के सामने है। बहुत से भाइयों ने यह भी सुझाव दिया कि जो यहां पर नौकर लोग हैं, सरकारी पदों पर कार्यकर्त्ता हैं, उनको भी यहां अपने वेतन से १० प्रतिशत कटवाना चाहिए और अपना योग देना चाहिए। तो मेरा भी सुझाव यह है कि जितने भी माननीय सदस्य हैं, हम लोगों को भी इसमें अपना योग देने से वंचित नहीं रहना चाहिए। मन्त्री महोदय का एक और बड़ा सराहनीय कार्य यह है कि उन्होंने देश की शिक्षा के लिए एक निःशुल्क व्यवस्था करने का कदम उठाया है। यह देश को प्रगतिशील बनायेगा, लेकिन मैं इसमें अपने दृष्टिकोण से यह निवेदन करना चाहती हूं कि यहां पर उन्होंने जैसा कि अपनी बजट स्पीच में व्यक्त किया है कि जो १०० रुपये तनख्वाह पाने वाले

[श्रीमती चन्द्रावती]

हैं उनके बच्चों की ९वीं क्लास तक आधी फीस कर दी जायगी और जो पिछड़ी जाति के हैं और जो हरिजन भाई हैं उनके लिए यह कदम पूरी तरह से लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से यह सोच पायी हूं कि जब यह दोनों श्रेणी के आदमियों को हटा देते हैं तो फिर हमारे सामने मध्यवर्गीय तबका आता है जिसके लिए थोड़ी-सी और कमी करके अगर व्यवस्था कर देते तो उन भाइयों के लिए भी कुछ फायदा हो जाता। छठी कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा घोषित कर ही दी है। इस प्रकार यह और भी अच्छा होगा कि सार्वजनिक हित सोचते हुए प्रदेशीय सरकार की ओर से १०वीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क दी जाय। मुझे यह कहने में संकोच नहीं होता कि केवल १०० रुपया तनख्वाह पाने वालों के बच्चों को आपने पढ़ने की कुछ सहायता दी है वह अधिक लाभदायक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी को दूसरे वर्गों का खास कर कृषि में काम करने वाले लोगों का भी, जिनकी आय १०० रुपये तक है, उनका भी जिक्र करना चाहिये था। कृषि वर्ग में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी १०० से कम है। यदि यही लाभ उनको भी दे दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। मंत्री जी को और ध्यान देना चाहिये कि अगर १०वीं कक्षा तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय तो अच्छा होगा। इससे एक उचित लाभ देश की गरीब जनता को मिल सकेगा। हमें कैटेगरीवाइज इस पर विचार नहीं करना चाहिये, बल्कि इस प्रकार से करना चाहिये कि हमारे देश की सारी गरीब जनता को उसका लाभ मिल सके। यदि आपको करना हो तो इस प्रकार से करें कि जिनकी १०० रुपया माहवार से कम की आय है उनको यह सहूलियत दी जाती है वरना देश की गरीब जनता शिक्षा से वंचित रह जायगी।

अब मैं दूसरा सुझाव समाज कल्याण विभाग की व्यवस्था के बारे में देना चाहती हूं। हमारे बजट में जो समाज कल्याण विभाग की व्यवस्था के लिये ६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है मैं उसका विरोध नहीं करना चाहती, परन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहती हूं कि दो विभाग ऐसे हैं जिनका संबंध महिलाओं के उत्थान कार्य से है। एक ही काम के लिये दो स्थानों से पैसा खर्च होता है। एक तो नारी मंगल योजना सरकार के द्वारा चलायी जाती है और दूसरा समाज कल्याण विभाग है जिसके लिये ५० प्रतिशत रुपया केन्द्र से मिलता है, २५ प्रतिशत का सरकार भार वहन करती है। राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कार्यालय का जो खर्चा है उसका भी सरकार ५० प्रतिशत व्यय उठाती है। इस प्रकार से दो रास्ते खर्च करने के हो गये। काम वही है महिलाओं का उत्थान करना। मेरी समझ में नहीं आता कि जब जिले की संयोजिका को समाज कल्याण विभाग में गाड़ी की व्यवस्था है मगर नारी मंगल योजना की जो आर्गेनाइजर हैं उसके लिये गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। उसको प्लानिंग आफिसर के मातहत काम करना पड़ता है। उसको कड़ी धूप में पैदल अथवा बस आदि के जरिये से भ्रमण करना पड़ता है। इसमें जो मुख्य सेविकायें होती हैं उनको १५० रुपया प्रतिमास तनख्वाह मिलती है जो कि आर्गेनाइजर को समाज कल्याण विभाग से मिलती है। इसलिये अगर आप दोनों को एक कर दें तो आप का यह डुप्लीकेट खर्चा बच सकता है। माननीय मंत्री जी का भी यही खयाल है कि जो भी साधन बचत के हो सकते हैं उनको हमें अपनाना चाहिये। इससे सरकार का काम भी सुचारु रूप से चल सकता है और इसमें रुपये की भी बचत हो जायगी।

मेरी तीसरी बात शिक्षा के बारे में है। महिलाओं के बारे में जो शिक्षा का कार्य है वह पूरा नहीं हुआ। मैं यह चाहती हूं कि प्राइमरी स्कूल तक यह अनिवार्य कर दिया जाय कि वहां तक की शिक्षा का भार महिलाओं पर रहे। बच्चे के ५ साल का समय ऐसा समय होता है जब कि उसका चरित्र बनता है। उस समय की उसकी शिक्षा का भार महिलाओं पर होगा तो अधिक अच्छा होगा और छात्रों का चरित्र बनाने में हमें बड़ी भारी सहायता मिलेगी। इस ओर अगर सरकार कुछ कदम उठाये तो महिला वर्ग भी उसका विशेष आभारी होगा।

अब थोड़े से सुझाव मैं जन-चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य के ऊपर देना चाहती हूं। यह कोई छिपाने की बात नहीं है कि गत पांच वर्षों में, पंचवर्षीय योजना में, प्रगति नहीं हुई है। सरकार हर साल हर तरह से यह कोशिश करती रही है कि इस बीच में अस्पतालों और दवाइयों

का प्रबन्ध हो। यहां पर मैं थोड़ा-सा विरोध करते हुये इस पर ज्यादा जोर देना चाहती हूं कि अपने देश की गरीबी को देखते हुये हमारी जो एलोपैथिक इलाज की परिपाटी है वह बहुत महंगी पड़ती है। उसके लिये सरकार को एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहिये जो अपने देश के लिये सस्ता और अच्छा रास्ता हो। आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथिक और प्राकृतिक जल चिकित्सा पद्धतियां भी हमारे यहां मौजूद हैं जिनमें से आयुर्वेदिक ने तो काफी प्रगति की है, लेकिन प्राकृतिक जल-चिकित्सा पद्धति अभी बहुत पिछड़ी हुई है। प्राकृतिक जल-चिकित्सा का सहारा बापू ने भी लिया और अपनी जिन्दगी में इसको महत्व देते रहे। यदि हम जिलावाइज एक-एक प्राकृतिक चिकित्सालय खोल दें तो हम लोगों का बहुत-सा रुपया जो दवाइयों के खरीदने में विदेशों को चला जाता है उसकी बचत हो सकती है। मेरे ख्याल से, मैं तो यहां तक कह सकती हूं कि हमारे देश में जो विदेशी दवाइयां आती हैं, उनके इम्पोर्ट में यदि हर साल कटौती करते चले जाय तो यह हमारे देश के लिये बहुत लाभ प्रद होगा और हमारी जनता का स्वास्थ्य जो गिरता जा रहा है तथा अनेक नये-नये असाध्य रोग दिखलाई पड़ते हैं, जैसे कि इंफ्लूंजा का एपीडेमिक जो हमारे प्रदेश क्या सारे देश में फैला हुआ है, यह सब एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का ही फल है। इसका दूसरा कोई कारण नहीं है।

अब मैं यहां पर थोड़ा सा जिक्र इस बात का करूंगी कि हमारे बजट में गर्भवती स्त्रियों के लिये दूध देने की योजना भी रखी गयी है। यहां और बहस में न जाकर मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि इससे शहर के बाशिन्दों को ही फायदा हो सकता है। यदि देहाती क्षेत्रों में यूनिट बनाकर सबसिडी के तौर पर गरीब औरतों को जो वाकई डिजर्व करती हैं, उनको रुपया ही बांट दिया जाता तो ऐसी अवस्था में लोगों का ज्यादा फायदा होता और यह अधिक उचित भी होता। मैं समझती हूं कि ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली महिलायें इस बात को जान भी नहीं सकती हैं कि सरकार हमारे लिये उनके कल्याण का कोई काम कर रही है। यदि हम उन्हें कहते हैं कि सरकार आपकी भलाई के लिये इस तरह का कार्य कर रही है तो वे इस प्रकार का भाव प्रदर्शन करती हैं जैसे उनको सरकार से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का प्रबंध करने के लिये उचित व्यवस्था सरकार करे तो ज्यादा लाभ होगा। यहां पर मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सरकार ने गर्भवती स्त्रियों को दूध पिलाने की व्यवस्था तो की है, लेकिन फेमिली प्लानिंग की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है। मेरे ख्याल से जब हमारा देश हर तरह से उन्नति की ओर बढ़ रहा है, तो ५ वर्ष से मैं देख रही हूं कि फेमिली प्लानिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना कि देना चाहिये। इस प्रदेश में इस स्कीम को बहुत ही महत्ता देकर अगर हम यह कार्य कर सकते हैं तो मैं समझती हूं कि हमारे सामने जो खाद्य उत्पादन का संकट पड़ जाता है उससे बहुत ज्यादा बचाव हो सकता है। हमारे देश का यह आंकड़ा है कि एक मिनट में ८० बच्चे पैदा होते हैं। इसको कम करने के लिये फेमली प्लानिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता है। सरकार को चाहिये कि वह इसके लिये उचित उपाय करे।

श्री उपाध्यक्ष--मुझे खेद है और मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने कुछ गलत सूचना अभी सदन को दे दी। जिस समय माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने यह प्रश्न उठाया था कि कांग्रेस और अपोजिशन की बेंचेज से कितने सदस्य बोले हैं और कितना कितना समय लिया है उस समय मैं कुछ गलत बता गया था। इस समय तक कांग्रेस बेंचेज के २६ वक्ताओं ने भाग लिया है और अपोजीशन से १९ वक्ताओं ने और कांग्रेस बेंचेज के लोगों ने ६ १/४ घंटे का समय लिया है और अपोजीशन ने ७ घंटे २० मिनट और इस तरह से कुल १३ घंटे ३५ मिनट भाषण हुये हैं।

१९५७-५८ के कतिपय अनुदानों पर मतदान का कार्यक्रम

श्री उपाध्यक्ष--दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि ग्रान्ट्स के बारे में अभी कोई अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है कि कौन सी ग्रांट कब ली जायगी लेकिन ३० और ३१ जुलाई के बारे में तय हो गया है कि उस दिन कौन सी ग्रांन्ट्स ली जांयगी। ३० व ३१ तारीख को जो ग्रान्ट्स चलेंगी वह है : ग्रांट न० १४--गांव सभायें और पंचायतें--माननीय स्वशासन मंत्री,

[श्री उपाध्यक्ष]

ग्रांट न० ३४--नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान--स्वशासन मंत्री, ग्रांट न० ३६--विविध व्यय--माननीय स्वशासन मंत्री, ग्रांट न० ६--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य--माननीय सिंचाई मंत्री, ग्रांट न० १०--सिंचाई स्थापना पर व्यय-माननीय सिंचाई मंत्री, ग्रांट न० ४४--राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन-माननीय सिंचाई मंत्री। इन अनुदानों के अतिरिक्त आशा है कि बाकी सूचना सदन को कल तक दे दी जायगी।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की ओर से वक्ताओं ने जो समय लिया है क्या उस में माननीय वित्त मंत्री जी का भी समय जोड़ा गया है और क्या बिरोधी दल के बोलने वाले वक्ताओं के समय में नेता विरोधी दल का समय भी जोड़ा गया है ?

श्री उपाध्यक्ष--जो ४ बजे तक की स्थिति थी वह मैंने सदन को बता दी और माननीय वित्त मंत्री जी ने तो अभी भाषण ही नहीं दिया है इसलिये उनके समय के जोड़े जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--बजट पेश होने के समय जो स्पीच हुई थी क्या वह समय भी जोड़ा गया है ?

श्री उपाध्यक्ष--क्या नेता बिरोधीदल द्वारा लिया गया समय क्या समय नहीं है, वह जोड़ा गया है। जो समय माननीय वित्त मंत्री जी लेंगे उसकी भी गिनती होगी, लेकिन आखिर में आप देखेंगे कि दोनों ओर का समय करीब-करीब बराबर ही रहेगा। ४ बजे तक की स्थिति मैं ने बता दी। इस समय में माननीय विरोधी दल के नेता जो भाषण दे चुके हैं, उनका समय भी शामिल है।

१६५७-५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

चौधरी रघुराजसिंह (जिला बुलन्दशहर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस कशमकश में हूं कि किस तरह इस बजट का स्वागत करूं और किन अल्फाज से माननीय मन्त्री जी को मुबारकबाद दूं। मैं यहां के लिए एक संदेश देहात से लाया हूं, वही मैं इस स्वागत और मुबारकबाद में पेश करता हूं, वह यूं है :

"आप के हिन्दोस्तां के जिस्म पर बोटी नहीं,
तन पे एक धज्जी नहीं है पेट को रोटी नहीं।
भूख की मारी हुई मखलूक का लीजे सलाम।"

मेरे पास इन्तहाई यही अल्फाज थे कि जिनसे मैं स्वागत कर सकता था और मुबारकबाद पेश करता। इस ऐवान में जो बजट पेश किया गया है, हमको बताया है कि उसमें ६६ करोड़ का खर्चा है और ११ करोड़ का डेफिसिट है।

डेफिसिट बजट बनाने का तो एक रिवाज सा हो गया है और जब डेफिसिट बजट हो तो उसके क्या नतायज होते हैं वह बड़े मुफस्सिल तौर से लीडर आफ अपोजीशन और दीगर मुखालिफ पार्टीज के लीडरान और विरोधी दल के बहुत से मेम्बरान ने काफी तौर पर बताया है। वक्त की कमी की वजह से मैं तो मुख्तसर में यही कहूंगा कि जब गवर्नमेंट डेफिसिट बजट बनाती है तो उसको पूरा करने के लिए कहीं न कहीं से रुपया तलाश करती है। उसके चन्द ही जरिये हैं। कर्ज लीजिये, टैक्स लगाइये या रिजर्व फन्ड पर हमला कीजिये। इसके अलावा कोई शक्ल मुझे तो नहीं मालूम होती। अगर यही हाल रहा कि सालहा साल हमारे सामने डेफिसिट बजट आते रहे जैसा कि एक रिवाज कायम हो गया है तो वह दिन दूर नहीं है जब कि हम बिलकुल दिवालिया हो जायं। मुमकिन है कि इसमें लोगों को शक हो, लेकिन मुझे तो जरा भी शक नहीं। हमारे नेता जब देहात में जाते हैं तो कहते हैं कि बड़ी गरीबी है, हम दूर करेंगे, लेकिन जब इस भवन में बैठ कर बजट पेश करते हैं और टैक्सों की योजनायें बनाते हैं तो वही गरीब

किसान और मजदूर बड़े मालदार और फारगुलबाल हो जाते हैं। जितने टैक्स इस वक्त तक मौजूद हैं वही नाकाबिले बर्दाश्त थे, लेकिन इस बजट में और भी कई टैक्सों में इजाफा कर दिया गया है। अगर हम इसको ऐनालाइज करें कि इन टैक्स का ज्यादा बोझा किस पर है तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वह अमीरों पर नहीं है, वह गरीब किसानों और मजदूर पर है। यह एक हिसाब की बात है और चूंकि वक्त बहुत ही कम है, मैं तफसील दे कर आंकड़ों के साथ बताने से मजबूर हूं, वर्ना मैं भी आंकड़ों से साबित करता कि इन टैक्सों ने किसान और मजदूर की कमर तोड़ दी है। हमारे श्री नारायणदत्त जी ने इस बजट के आंकड़ों को ले कर इस बात को साबित कर दिया और रोजे रोशन की तरह से हर एक पर अयां कर दिया कि यह बजट दिवालिया है। मैं बड़े इश्तियाक के साथ उनकी उस तफसील और आंकड़ों को लेकर दलीलों का जवाब सुनने का गवर्नमेंट की तरफ से मुन्तजिर रहूंगा। लीडर आफ अपोजीशन ने इस बजट की एक बहुत ही मुकम्मिल तस्वीर इस भवन के सामने रखकर हर पहलू को दिखलाया। जहां तक किफायतशारी का सवाल आता है वहां हम क्या देखते हैं––"वर्ग सब्जस्त तोहफ़ये दुर्वेश" कह कर हमारे वजीरों ने अपनी तनख्वाह में सौ-सौ रुपये माहवार की कमी की है, ऐसे दुर्वेश सिवाय इस भवन के दूसरी जगह नहीं मिलते।

यह सब तरीके प्रोपेगेन्डा के हैं। जब लोग अखबार में पढ़ेंगे कि हमारे वजीरों ने तनख्वाह में कमी कर दी, तो त्याग की दाद देंगे, लेकिन जब देखेंगे कितनी कमी? सौ रुपये! कितने से? बारह सौ में तो क्या कहेंगे, सोचिये? क्या इसी पर आप सब इक्तफा करते हैं? और बारह सौ तनख्वाह लेते हैं। सारा देश जानता है कि यह तो बराय नाम है। आपके भत्ते, आला किस्म के मकान और कीमती फर्नीचर, कटलरी, क्राकरी, यहां तक कि जरूफ नुकरा व तिलाई और शाने रियासत कायम रखने के लिए वजीरों को यह सब चीजें दरकार हैं, यह आप की दलील है। जरा फरमायें इन में से आपने क्या कमी की?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)––मैं थोड़ी सी एक बात दरियाफ्त करना चाहता हूं। यह तिलाई और नुकरा जरूफ की खबर आप को कहां से मिली?

चौधरी रघुराजसिंह––खबर मिलने के कई जरिये हैं। अगर तहकीक के साथ जवाब चाहते हैं तो जैसे आप नोटिस और मौका चाहा करते हैं, मुझको भी मौका दीजिये। एक बहुत बड़ा खर्चा और परेशानी यह कि आये दिन कभी मिनिस्टर साहब, कभी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी तो कभी डिप्टी मिनिस्टर आते ही रहते हैं। रोजाना की मेहमाननवाजी का बार आखिर किस पर पड़ता है, भत्ते वगैरह कहां से दिये जाते हैं? सब जनता के टैक्स के खजाने से। एक देहाती मसल है––"मेहमान मारा घर और चिलमों मारा चूल्हा कभी नहीं पनपता।" किफायत के लिए यही बहुत बड़ी मद है। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि इन दौरों को कम करें, बड़े-बड़े महल जिनमें आला किस्म के फर्नीचर लगे हुए हैं उनमें यहीं आराम करें अगर वाकई आप चाहते हैं कि हमारी स्टेट के अन्दर किफायतशारी हो। मैंने यह भी पढ़ा कि इस बजट के बाद हर महकमे की एक कमेटी बनायी जायगी और उसका काम यह होगा कि वह अपने-अपने महकमे में देखे कि कहां-कहां किफायत हो सकती है। मैं तो समझता हूं कि यह कमेटियां तो उनको बहुत पहले मुकर्रर कर देनी चाहिए थीं ताकि उन की कार्यवाही मुकम्मिल होकर हमारे सामने इस बजट में शामिल हो कर आ जाती कि इतनी किफायत किस तरह की गयी और बाकी के लिए आगे यह तजवीज है। टैक्सों का क्या हाल अर्ज करूं। हम और आप सभी चुनाव लड़ कर आये हैं। देहात में किसानों और मजदूरों से दू बरदू बातें हुई हैं। उनकी हालत को देखा है, उनसे बातचीत हुई है। क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि वे इन सब टैक्सों से तड़प नहीं उठे? मुझे तो यकीन है कि आज जो हमने यहां सुना और देखा वह कागजी बागबानी है जब कि दूसरी तरफ हकीकत कुछ और है। वह हमारी और आपकी आंखों ने देखा है। अगर यह कहा जाय कि नहीं उसी जनता ने हम को वोट देकर भेजा है तो मैं जनता के अखलाक व वजेदारी की दाद देता हूं कि बावजूद

[चौधरी रघुराजसिंह]

इन परेशानियों के जनता ने एक मौका आपको और दिया है, लेकिन काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है। मैं आप से क्या अर्ज करूं सिर्फ एक बात कहकर अपने दस मिनट के वक्त की पाबन्दी करूंगा।

"इस कदर सदमे उठाये दोस्तों के हाथ से,
कि दुश्मनों की अदावत का गिला जाता रहा।"

दस मिनट में क्या-क्या कहूं। यह बजट हमारे मंत्रिमण्डल की काबलियत और देशभक्ति का एक नमूना है कि इस बजट में किसान, मजदूर को कोई सहूलियत नहीं, उनकी सेहत, तालीम, इन्साफ, कर्जा और जरूरियात, जिन्दगी का कहीं हल नहीं है।

"नौजवां बफरे हुए हैं, भूख से दिल तंग है,
जर्रे जर्रे से अयां आसार हरबोजंग है।
चौंकिये जल्दी हवाये तुन्द गरमाने को है,
जर्रा जर्रा खाक में तब्दील हो जाने को है।"

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उपाध्यक्ष महोदय, मैं ४ रोज से इस सदन के अन्दर उस बजट पर जो इस साल पेश किया गया, बहस सुनता आ रहा हूं। मगर मुझ को एक ऐसा अन्दाजा हुआ कि इस दौरान में इस सदन के अन्दर एक गैर मामूली टेंशन रही। मैं उसको दूर करना चाहता हूं।

मैं उस टेंशन और खिचावट को दूर करना चाहता हूं। बजट की निस्बत जो कुछ मेम्बरान ने इरशाद फरमाया मैं उसका मशकूर हूं इसलिए कि मैं अपने नजदीक समझता यह हूं कि जिन साहबान ने भी जो कुछ भी इरशाद फरमाया वह मुझको अपने नजदीक एक अच्छा सबक देने के लिए इरशाद फरमाया। यह बात जरूर काबिले शुक्रिया है। बजट की निस्बत यह बहस रही कि यह किस प्रकार का बजट है? सोशलिस्ट बजट है कि नहीं है। मैं ने इस पर बहुत कुछ सुना इस सदन के मुअज्जिज मेम्बरों से और मैं इस नतीजे पर पहुंचा जितनी बातें मैंने सुनीं उन से कि वें एक बड़ी गलत फहमी में मुब्तिला हैं जिसको कि मैं अपनी इस समय की गुजारिश में दूर किया चाहता हूं। कुछ मैंने यह भी समझा कि शायद बजट को, कम से कम यह अर्ज करूंगा, उतना तो नहीं पढ़ा गया जितना कि उसको पढ़ना जाना चाहिए था। मगर इस से पहले मैं एक बात अर्ज किया चाहता हूं। वह इसी वक्त मेरे दिमाग में आ गयी। शायद मेरे एक मुअज्जिज भाई उधर से तकरीर फरमा रहे थे बजट पर। उन्होंने यह इरशाद फरमाया कहते-कहते कि और नहीं तो तुम यहां से उठो और हम को यहां बैठने दो। तो मैं हुजूर वाला, उनको दावत देता हूं। एक शायर का शेर है--

"इधर आ बैठना आकर उधर से। मिला है घर मेरा दुश्मन के घर से।।"

ऐसा मौका है कि आप जिस वक्त चाहें यहां तशरीफ लाके बैठ सकते हैं और यहां बैठने से जिस किस्म का आदमी बन जाता है उस किस्म का आदमी बनने की अगर तमन्ना हो तो आ सकते हैं। मैं, जनाबवाला, यह अर्ज कर रहा था कि बजट के कैरेक्टर की निस्बत बहुत कुछ गुफ्तगू रही और मैंने यह अर्ज किया कि वह एक गलतफहमी के मातहत थी। मैं ने अपनी बजट स्पीच में यह अर्ज किया कि यह मौजूदा सरकार जो है इसकी नीति वह रिजोल्यूशन है, जो कांग्रेस ने अवाडी में पास किया और जिस में यह कहा कि हिन्दुस्तान के अन्दर एक सोशलिस्ट समाज बनाया जाय। सोशलिस्ट पैटर्न का समाज बनाया जाय और उस के बनाने के लिए मीन्स आफ प्रोडक्शन जो हैं, वह गवर्नमेंट के कब्जे में हों। उसी में यह भी कहा कि दौलत की जो तकसीम हो, वह एक न्यायसंगत तकसीम हो और उसी के साथ यह बात भी अर्ज की, जो हमेशा याद रखने के काबिल है और जिसको मेरे एक मुअज्जिज भाई ने बहुत अच्छे तरीके से सुनाया है कि हमारा ढंग तरक्की का जो है वह डेमोक्रेटिक हो, जनतांत्रिक हो। जम्हूरियत के जो तरीके हैं, उन तरीकों से समाज को बनाया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह मैंने अपने बजट में अर्ज किया। अब सब से पहले उस गलत फहमी को रफा करने से पहले मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं और बिला तशखीस इस बात के कि मेम्बर इधर के हैं या उधर के हैं या और कोई शख्स है उनके ईमान व इन्साफ पर छोड़ता हूं कि वे अपने दिल में गौर कर के सोच लें कि जो बात मैं कहता हूं वह ठीक है या गलत है और आज वे चीजें ऐसी हैं या नहीं हैं जो उस वक्त मौजूद नहीं थीं और आज मौजूद हैं। सूरज सामने हो तो अक्ल जिस के पास न हो वह तो भले ही कहे कि रोशनी सामने नहीं पड़ रही है, लेकिन जिसके पास अक्ल होगी, वह इन्कार नहीं कर सकता कि सूरज हमारे सामने है और उसकी रोशनी सामने पड़ रही है। मैं नहीं जानता कि वह सोशलिस्टिक समाज जिसका इस हाउस में जिक्र किया गया क्या वह कभी ऐसा हो सकता है जिस में किसी जगह पर कोई सड़क न हो, आबपाशी के लिए नहर न निकाली जाय, उसमें ट्यूबवेल्स न लगाये जायं, उसमें शफाखाने न बनाये जायं, उसमें मदरसे न खोले जायं, और उसमें इन्डस्ट्रीज को तरक्की देने का काम न किया जाय? अगर इस बजट में ये चीजें हैं और हैं यकीनन और वह शख्स जिसने उसे पूरे तौर से पढ़ा है तो मैं कह सकता हूं कि ये सब बातें उसके अन्दर उसको मिलेंगी। तो इस बजट को और क्या कहा जायगा?

मैं कुछ फर्क की बात भी कहूंगा जो किसी के दिमाग में होगी, लेकिन पहले मैं यह बतला रहा हूं कि जो चीज भी इस बजट में है वह सोशलिस्ट समाज को बनाने वाली है, वह इस मुल्क की तरक्की करने वाली है। हमारा नस्बुलऐन है, हम पर फर्ज आयद है कि हम इस देश और प्रदेश के रहने वालों की जिन्दगी के मयार को, जीवन स्तर को, स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को ऊंचा करेंगे। क्या मतलब है इसका? उसको ऊंचा करने का मतलब यह नहीं है कि हम इसको रूस का सोशलिज्म देंगे या चायना का सोशलिज्म देंगे। इसका मतलब यह है कि यहां यह हालत कायम की जायगी कि दौलत की तकसीम आज जो है वह नहीं होनी चाहिए, दौलत की तकसीम वह हो जिसके अन्दर हर शख्स को इतना पहुंचे कि वह आराम की जिन्दगी बसर कर सके। उसके लिए दौलत पैदा करना है। लेकिन यहां उत्तर प्रदेश के इस लेजिस्लेचर के मेम्बरान को यह जानना चाहिए कि इस हिन्दुस्तान का संविधान क्या है। यह स्टेट क्या कर सकती है। बगैर सेन्टर की इम्दाद के यह स्टेट सोशलिस्ट समाज नहीं बना सकती। सेन्टर व स्टेट दोनों मिल कर काम करेंगे तभी सोशलिस्ट समाज बन सकता है। क्या सेन्टर ने इन्कम टैक्स के ऊपर सुपर टैक्स नहीं लगाया? वहां एक्सपेंडीचर टैक्स लगा या नहीं? वहां कैपिटल टैक्स लगा या नहीं? वह क्या-क्या टैक्स हैं जो दुनिया के सामने आ चुके हैं, वह क्या हैं? अगर उसे यह कहते हैं कि वह दौलत की तकसीम करने के लिए, ठीक करने वाले नहीं हैं, तो मैं कहता हूं कि गलत कहते हो। मैं दावे से कहता हूं कि उनके जरिये से दौलत की तकसीम होगी। अब यह मुझे बतायें कि वह कौन से टैक्स हैं जिनको फाइनेंस मिनिस्टर लगादे जिस से दौलत की तकसीम ठीक हो जायगी? वह तो सब उस लिस्ट में दिया हुआ है जो संविधान के अन्दर है कि वह सब सेन्टर के कब्जे में हैं और सेन्टर उस काम को कर रहा है। उसके होते हुए, इस बात को जानते हुए मेम्बरान को जनाना चाहिए कि कानून को ठुकराना मेरे नजदीक फर्ज हो जाय, तो दूसरी बात है, लेकिन मैं तो कानून की रेस्पेक्ट करता हूं। मैं हिन्दुस्तानियों को कानून की रिस्पेक्ट सिखाना चाहता हूं। उन को अपने अमल से यह तालीम देना चाहता हूं कि वह यहां के बने हुए कानून की रेस्पेक्ट करें।

उसको देखते हुए जो यह स्टेट कर सकती हो, उसकी रोशनी में देखना चाहिए कि यहां के बजट में क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। वह चीजें जो यहां नहीं हो सकती हैं, जिन से किसी को नजर में आता हो कि सोशलिस्ट समाज बनता है तो उसका क्या जिक्र? यहां तो सोशलिस्ट समाज उतना ही बनेगा जितना कि यहां की स्टेट बना सकती है।

इस बजट के अन्दर मुलाजिमों की तनख्वाहों में जो फर्क हैं उन फर्कों को कम करने का दावा इस बजट में नहीं है, या इससे पहले नहीं हुआ? पहले हो चुका है और फिर हुआ है और आगे को होगा, उसका रास्ता बन्द नहीं हुआ। अल्लादीन का चिराग नहीं है यहां कि उसको यहां हिलाया जायगा और दुनियां बदल जायगी और आदमी कहीं से कहीं पहुंच जायगा। यहां

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

तो आर्डर्ड प्रोग्रेस होगी, एक तरीके से चला जायगा, काम होते होते होगा। उस मुल्क में जिसमें कि काम करने के जरिये मोजूद न हों, कहां से लाऊं ? दूसरे मुल्कों से जा जा करके चीजें लायी जाती हैं जिनके जरिये से यह काम होते हैं। उन के लाने में भी वक्त लगेगा, पैसा खर्च होगा और उधर यह तवक्को की जाती हो कि हाफिज इब्राहीम ने यहां ठोकर मार कर लखनऊ के फलां मुहल्ले में बिजली क्यों नहीं निकाल दी, तो मैं वह तमाशा नहीं कर सकता। मैं तो पावर हाउस बना सकता हूं, जहां कि टरबाइन्स दूसरे मुल्कों से आकर लगते हैं और जहां पर ट्रांस्मिशन लाइन्स चलती हैं, जिनका सामान दूसरे मुल्कों से आता है। उन के लाने में वक्त खर्च होता है, जमाना खर्च होता है, पैसा उस के ऊपर खर्च करना पड़ता है। तो यहां वह हुजूर वाला, काम होगा और यकीनन होगा। सोशलिस्ट समाज बनेगा, बन के रहेगा, और उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से कि इनसान बना सकते हैं। उस तरीके से नहीं बनेगा कि जहां बनाने वाला इन्सान न हो, कुछ और हो, फरिश्ता हो। हम से वह नहीं होगा।

मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेरे लिमिटेशन्स को देखो और फिर देखो कि क्या काम हुए तो उस से अन्दाजा इस बात का ठीक तौर से हो सकता है। खैर, अब उसमें शिकायत कर सकता है कोई ? मेरे एक लीडर, जनसंघ के, उन्होंने हिसाब फरमाया कि लैन्ड रेवेन्यू तो टैक्स है ही। मैंने बदकिस्मती से अपनी स्पीच में लिखा था . . .

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--सुनाई कुछ नहीं देता।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मेरी आदत बीच में जवाब देने की नहीं है, लिहाजा मेरी तरफ इस गरज से न बोलें कि मैं कोई जवाब दूंगा।

श्री त्रिलोकीसिंह--इस तरफ के लोगों का हक है कि आप की बात को सुन सकें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बिलकुल ठीक है, मैं बहुत मशकूर हूं। मैं अर्ज करता हूं कि मैंने अपनी स्पीच में यह कहा था कि जो टैक्सेज यू० पी० में हैं उसमें अगर लैंड रेवेन्यू को शामिल न किया जाय तो आप यह जानते होंगे और इकोनोमिक्स के जानने वाले जानते होंगे कि दो तरह के स्कूल आफ थाट्स हैं कि लैंड रेवेन्यू टैक्स है या नहीं। मैं वह हूं जो लोग यह करार देते हैं कि लैंड रेवेन्यू टैक्स नहीं है। बड़े-बड़े लोग हैं और उन्होंने इस मजमून पर बड़ी-बड़ी किताबें लिखी हैं। इसीलिये मैं ऐसा कहता हूं कि जो चीज किसी चीज के बदले में दी जाती है वह टैक्स नहीं है। काश्तकारों को मैं पानी देता हूं और उसके एवज में उनसे इर्रीगेशन रेट वसूल करता हूं तो वह टैक्स नहीं है। जमीन गवर्नमेंट की है और वह वैस्ट करती है स्टेट में और किसी एक इंडिविजुअल की मिलकियत नहीं है। जब उसको इस्तेमाल के वास्ते दी जायगी, वह अपनी जात के लिये उससे फायदा उठायगा तो उससे कुछ लिया जायगा। इसलिये लैंड रेवेन्यू मुआवजे में ली जाती है, जमीन के इस्तेमाल के लिये। जो जमीन को इस्तेमाल करता है, अनाज पैदा करता है और उससे खाता है तो वह मालगुजारी अदा करता है, वह टैक्स नहीं है बल्कि एक मुआवजा है एक चीज का जो वह गवर्नमेंट से लेता है। यह एक थौट का कहना है। मैं यही राय रखता हूं। इसलिये मैंने अर्ज किया था। उसको बड़े जोर से तरदीद हुई थी। मैंने तो नहीं कहा था, लेकिन उनको शुबहा हुआ कि मैंने कुछ कह दिया। मैंने कुछ नहीं कहा था, खैर इस को छोड़िये।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जितनी इस बजट में चीजें रखी हुई हैं पुराने किस्म की वह सब सोशलिस्टिक समाज में होती हैं और सोशलिस्टिक बजट की जुज हैं और इसके अलावा अर्ज किया कि नौकरों की तनख्वाह में कमी करना, तालीम मुफ्त करना और गरीब लोगों की जो मुहताज हैं, मदद करना वगैरा। ऐसी ५-६ चीजें हैं जिन को मैंने अलग करके रखा था जिससे उनके माने लोग समझें कि क्या हैं ? इसका सिगनीफिकेन्स जानें की क्या है ? मेरे नजदीक तो यह सोशलिस्टिक पैटर्न का बजट है और कम से कम उसका जिस का मैं कायल हूं।

अगर कोई और किसी तरह के सोशलिज्म का कायल हो तो यह उसके नजदीक न हो, । मेरे नजदीक है और मैं उसका–सा नहीं ला सकता ।

हुजूरवाला, जनाब के जरिया से मैं अर्ज करूं कि रूस में १९१७ में रिवल्यूशन हुआ था । आज तक वहां काम पूरा नहीं हुआ । इस रूस के अन्दर अब भी प्लान बन रहे हैं । चीन में क्या हो रहा है ? तब फिर मैं क्या एक आदमी नहीं हूं ? यहां के लेजिस्लेटर्स के निस्बत और कारकुनों के निस्बत यह कहा गया और इन कम्बख्तों के लिये यह इल्जाम था कि तुम कुछ नहीं करते हो, तुमने कुछ नहीं किया है । मैं अर्ज करूं कि इस बजट पर चार रोज से डिस्कशन हो रहा है । उस का खुलासा यह है कि जिन साहबान ने तकरीरें कीं उन्होंने कोई सूरत नहीं बतलाई, अपने कंस्ट्रक्टिव सजेशन्स नहीं दिये कि इस तरह से करो या यह तरीका अखतियार करो, निकालो उनकी तकरीरों को, यह नहीं बताया कि तुम्हारा तरीका गलत है और सच्चा तरीका यह है । तुम्हारे बजट के अन्दर वह स्कीम गलत है , उसको नहीं होना चाहिये । किसी ने इसका कोई जिक्र नहीं किया ।

श्री त्रिलोकीसिंह––मैंने किया था ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––जिस किसी ने कहा वह मेरे पास मौजूद है । कानों से सुना है कलम से लिखा है ।

श्री त्रिलोकीसिंह––सिर्फ़ भूल गये हैं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––भूल नहीं गया साहब, लिखा हुआ मौजूद है । जो साहब यह फरमा रहे हैं कि मैं भूल गया हूं वह असल में , माफ़ फ़रमायेंगे, मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं । फिर किसी ने यह नहीं बतलाया कि वह सोशलिज्म है क्या । मैंने तो किसी से नहीं सुना । अल्लाह जाने, किसी ने दिल में रख छोड़ा हो या आपस में कानों में एक दूसरे से कहा हो , लेकिन इस हाउस के मेम्बरों को यह फ़ायदा नहीं पहुंचा । हम तो वैसे ही बीटिंग एबाउट दि बुश करते हैं ।

सबसे पहली बात जो मैंने सुनी इस बजट के मुताल्लिक वह यह कि यह स्टेट डेफ़िसिट फ़िनैन्सिग कर रही है । तो मैं समझा उस वक्त यह कि यह गलतफ़हमी इस के मुताल्लिक है कि डेफ़िसिट बजट जो बना है वह डेफ़िसिट फ़िनैन्सिग है । मैं जनाब के ज़रिये से इस हाउस के मेम्बरान के सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि डेफ़िसिट फ़िनैन्सिग बिलकुल दूसरी चीज है और डेफ़िसिट बजेटिंग बिलकुल दूसरी चीज है । एक किताब है जिसका नाम है "थ्योरी ऐंड वर्किंग आफ़ दि यूनियन फ़िनैन्स इन इंडिया "जो आर० एन० भार्गव साहब की लिखी हुई है । वक्त की कमी है नहीं तो मैं पढ़ देता ।

श्री त्रिलोकीसिंह––बजाय ६ के ७ तक का वक्त करा दिया जाय ? हम आपको पूरे तौर से सुनना चाहते हैं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––जी नहीं, मुझे शौक बोलने का है नहीं । तो उन्होंने १८० सफ़े पर डेफ़िसिट फ़िनैन्सिग और डेफ़िसिट बजेटिंग दोनों पर लिखा है । जो यहां इन्फ्लेशन की बात कही गयी कि इससे इन्फ़्लेशन होगा तो वह डेफ़िसिट फ़िनैन्सिग के मुताल्लिक है डेफ़िसिट बजेटिंग के मुताल्लिक नहीं है ।

अब मैं कुछ वह बातें अर्ज किया चाहता हूं जो कुछ मेम्बर साहबान ने अपनी तकरीरों में फ़रमाई हैं । उनके मुताल्लिक मुझे जो कुछ कहना है वह मैं अर्ज कर रहा हूं मगर उसमें से जो कुछ मिनिस्टरों के मुताल्लिक फरमाया गया है उन के मुताल्लिक मैं इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता इसलिये कि मुझे यकीन पूरा है कि जिस वक्त बजट उस सिलसिले का आयेगा तब पूरा मौका होगा उस वक्त जवाब दे दूंगा । इस वक्त वक्त बचाना चाहता हूं, लेकिन यह न समझा

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

जाय कि मेरे पास जवाब उसका नहीं है,जवाब है, लेकिन जब मौका होगा दूंगा, बाकी और बातें अर्ज करता हूं ।

मैंने अपनी बजट स्पीच में दिखलाया था कि यू० पी० के मुकाबले में बम्बई और बंगाल में टैक्स बहुत ज्यादा हैं । उसकी निस्बत यह बात कही गयी कि वहां पर इंडस्ट्रियल पापुलेशन ज्यादा है और यहां इंडस्ट्रियल पापुलेशन कम है और ऐग्रीकल्चरल पापुलेशन ज्यादा है । इससे यह बात होती है कि वहां टैक्स ज्यादा हो और यहां टैक्स कम हों । लेकिन मैं उस चीज को आबादी के किस्म की रोशनी में इस बात को देखना नहीं चाहता बल्कि एक अटल बात, जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता है उसकी विना पर इस को देखना चाहता हूं और वह यह है कि वहां पर कैपिटा इनकम क्या है और यहां पर पर कैपिटा इन्कम क्या है । बदकिस्मती से बंगाल के आंकड़े तो नहीं मिले , लेकिन बम्बई के तीन साल के पर कैपिटा इन्कम के आंकड़े मेरे पास है । बम्बई में सन् १९४८–४९ की पर कैपिटा इन्कम २४९.२ है और उस साल की यू० पी० की २४१.९ है । सन् १९४९-५० की बम्बई की २४५.३ है और यू० पी ० की उस साल २४५.४ है । सन् १९५०-५१ की बम्बई की २५७.१ है और यू० पी० की २५३.१ है । इस तरह से आप देखें कि यू० पी० और बम्बई की आमदनी करीब-करीब एक सी है उस में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन टैक्सेज उसी आमदनी पर बम्बई में १० है तो यू० पी० में ५ है । इससे आप अन्दाज लगा लीजिये । इससे ज्यादा इस पर कहने की जरूरत नहीं है ।

कास्ट आफ़ लिविंग इन्डेक्स की शिकायत की गई । उसकी बाबत में यहां पहले ही कह दूं कि वह कानपुर शहर के जो वर्कर्स हैं उनका निकाला जाता है वह है । वह कोट की गयी है कि कास्ट आफ़ लिविंग इंडेक्स पहले इतना था और अब वह इतना बढ़ गया है । मैं उसकी निस्बत अर्ज करूं कि सन् १९४६ में कानपुर का इन्डेक्स ३३० रुपये था और जून सन् १९५७ में वह ४४६ हो गया , लेकिन इस के साथ मेरी गुजारिश यह भी तो है कि जरा वेजेज का जो रेट बढ़ा वह भी तो आप मुलाहिजा फरमायें । सन् १९४६ में वेजेज का रेट २९६ था और सन् १९५७ में वह ४९४ हो गया । इससे हर आदमी अन्दाजा लगा सकता है कि असल पोजीशन क्या है और उस से क्या नतीजा निकलता है । मैं इसके मुताल्लिक अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता ।

एक बात यह कही गयी कि १९४६-४७ में यहां जितना टैक्स था उससे अब टैक्स बहुत ज्यादा है । मैं अर्ज करता हूं कि यह सही है और मेरे पास उसके फीगर हैं । सन् १९४६-४७ में डेवलपमेंट का खर्चा १५ करोड़ और कुछ लाख रुपये था और अब यह जो बजट है इस में अगर उसका मुलाहिजा फरमाया जावे तो अब वह खर्चा ७५ करोड़ है । उस वक्त के मुकाबले में अब पांच गुना खर्चा हमारी स्टेट का है । यह रुपया रेवन्यू एकाउन्ट का है । तब भी रेवेन्यू एकाउन्ट का था और यह ७५ करोड़ भी रेवेन्यू का खर्चा है ।

ऐग्रीकल्चर के बारे में कहा गया कि यहां पर प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है । मैं यह अर्ज करूं कि यह जो स्टेट है इसमें एक लाख और कुछ हजार गांव हैं और ६ करोड़ २९ लाख की यहां पर आबादी है । इसमें जो खेती बोते हैं, उसमें कितनी बोते हैं ? उसमें से २६–२७ फीसदी बोई जाती है और बाकी बेकार रहती है, जिसको हम दूसरी पंचवर्षीय योजना में बढ़ा रहे हैं । यह मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि आज कल मेजोरिटी पोर्शन खेती का ऐसा है जिसमें आबपाशी नहीं होती है इस वजह से कि अभी तक आबपाशी हम इतनी नहीं बढ़ा पाये हैं कि हर एक खेत तक पानी पहुंच सके । इस बात को सामने रख कर हमें यह सोचना है कि अगर कोई खास मुसीबत आ जाय––जैसे बारिश न हो वक्त के ऊपर या जिस तरह से सैलाब आते हैं वे आ जायं––तो हर शख्स जो ईमान से कहेगा वह यही कहेगा कि पैदावार कम होगी और पैदावार बढ़ती हुई, जो इनकामों की वजह से होनी चाहिये, वह नजर नहीं आयेगी । १९५६–५७ का साल एक ऐसा साल आया कि बलिया से लेकर

सहारनपुर तक का इलाका सैलाबजद हो गया और जितनी पैदावार थी वह सब तबाह हो गयी और जो प्रोडक्शन होना था वह आधा ही रह गया। अब मैं अर्ज करता हूं कि अगर आप इंसाफ ही करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों पर जरूर सोचना होगा। कंट्रोल से बाहर जो सरकमस्टेन्सेज हैं उनको भी डिफरेंशियेट करना होगा। मैं यह तस्लीम करता हूं कि मैंने गज भर काम किया है, लेकिन १०० गज करना चाहता हूं। उम्मीद है जब कि पूरी तस्वीर सामने आ जायगी, पूरी आबपाशी हो जायगी तो उस दिन के फिगर्स दूसरे ही होंगे।

मैंने कोशिश इस बात की कि जिस हिस्से में आबपाशी हुई है उस हिस्से की पैदावार अलहैदा मालूम हो जाय, लेकिन मालूम हुआ कि उसके फिगर अलहैदा तैयार नहीं किये जाते हैं, फिर भी मैं बढ़ता हुआ देखता हूं। इसलिये आप ५६–५७ के दलदल में न फंसें अब मैं आपको फिगर्स बताता हूं। सन् ५० में गेहूं की पैदावार हुई ८.५४ मन फी एकड़, और ५४–५५ में हो गयी ९.६४ मन फी एकड़। पैडी की पैदावार १९५० में ५.८ मन फी एकड़ हुई और ५४–५५ में हो गयी ८.६२ मन फी एकड़। इसी तरह से पैदावार में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन ५६–५७ में जो मुसीबत आयी उससे पैदावार पर असर पड़ा और वह घट गयी। कोई परसनल बात करनी नहीं चाहिये, लेकिन मुझे एक साहब से एक बात सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि चैनल, नहरें तो निकलती जाती हैं, लेकिन नहरों का पानी नहीं बढ़ता। मैं उस वक्त सोचता रहा कि या अल्लाह ये साहब यहां से चल कर कभी कानपुर की तरफ गये हैं या नहीं गये हैं? यहां से कानपुर के लिये मोटर में चलिये और रास्ते में जो नहर पड़ती है उसको देखिये कि उस नहर को दुगुना कर दिया गया है। जितनी बड़ी नहर थी उसको इसलिये डबल कर दिया गया है कि उसमें डबल पानी चले। इसी तरह से रायबरेली तशरीफ ले जाइये तो उस तरफ उतरठिया गांव जो कैन्टूनमेंट के आगे पड़ता है उसके करीब जो नहर है वहां की सड़क टूटी पड़ी है। वह इसलिये कि नहर को चौड़ा किया गया है और नयी सड़क दूसरी जगह हट कर बन रही है। इसलिये कि उस नहर में ज्यादा पानी चले।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)––वे उस तरफ भी नहीं गये हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि लखनऊ में रहते हुए अगर एक शख्स को इतना भी मालूम न हो कि इसके आसपास क्या हो रहा है तो यह तो वही कहावत जो मशहूर है हुई कि "चिराग तले अन्धेरा"। हुजूरवाला, सन् ५१ से लेकर इस वक्त तक १० हजार क्यूजेक्स पानी बढ़ाया जा चुका है। बुन्देलखंड में डैम्स बनाये गये हैं, जहां तहां रिजर्वायर्स बनाये गये हैं। यह सब इन्तजाम सरकार ने पानी को बढ़ाने के लिये ही किया है। गंगा के पानी को बढ़ाने का इन्तजाम किया गया है। इस तरह से आज तक १० हजार क्यूजेक्स पानी उन्हीं नहरों से निकाला गया है। तो मुझे तो ताज्जुब हुआ कि कोई साहब कैसे यह बात कहते हैं कि नहरें तो निकल रही हैं, लेकिन पानी नहीं बढ़ा रहे हैं। मगर असल बात यह है कि जब कोई आदमी किसी के ऊपर गुस्से में होता है तो उस समय उसे मालूम नहीं होता कि असली पोजीशन क्या है।

अब मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात पहले कह दूं। ट्यूबवेल्स का जहां तक सम्बन्ध है।

श्री गेंदासिंह––इसको मैंने देखा है इसी में इम्तिहान है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––मेरी आंखों से देखिये तब मालूम होगा। अपनी आंखों से कहां तक देख सकते हैं। सारी बदकिस्मती मेरी यह है कि चीज जब और नजर से देखी जाती है तो वह नजर ही नहीं आती। वह तो आपको नजर आये तब जब आप उस नजर से उसको देखें।

श्री त्रिलोकी सिंह---टचूबवेल्स तो हैं, लेकिन पानी नहीं देते ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बात यह है कि गोरखपुर में पावर हाउस बनाया गया और उसके ऊपर जितनी बिजली बनती थी उससे ज्यादा के टचूबवेल्स लगाये गये थे। बात वह सही है, लेकिन समझ का फेर है, सिर्फ समझ का फेर है और कुछ नहीं है। और हुजूरवाला, यह जो पावर हाउस वहां पर बना वह इंटरिम था। एक थर्मल पावर हाउस १५ हजार किलोवाट का वहां बनाने का विचार था। तब तक के लिये जब तक कि वह पावर हाउस तैयार हो, एक डीजल आयल से टचूबवेल्स को चलाने का इन्तजाम किया गया कि आठ-आठ घंटे तक उनसे काम लिया जाय और जितनी जमीन को उनसे पानी मिल सके, मिले। ऐसा न करके इस बात के इन्तजार में बैठा रहा जाय कि जब २४ घंटे तक चलाने का इन्तजाम होगा तभी चलायेंगे तो अब इसके लिये क्या कहा जाय? इस साल के अक्तूबर में वह काम पूरा हो जायगा और वह बन कर तैयार हो जायगा और उसके बाद टचूबवेल २४ घंटे काम करेगा। हमने तो रोस्टर बना कर डीजल इंजिन से काम लिया और आठ-आठ घंटे बारी-बारी से चला कर पानी का एक इन्टरिम इंतजाम किया। हमने इसलिये इस काम को किया कि पूरा तैयार होने में अभी देर थी, लोगों को कुछ पानी इन महीनों में भी मिल जाय। इसकी हकीकत सिर्फ इतनी सी थी।

एक सवाल यह हुआ कि यह जो डियरनेस एलाउन्स बढ़ाया गया है वह कुल ५ रुपया ही बढ़ाया गया है। मैं आपसे सच्ची बात अर्ज करूं यह ५ रुपया बढ़ाते हुये मैं खुद बहुत शरमाता था और मैं दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे ऐसी ताकत दे, इस काबिल करें कि मैं १५ रुपए बढ़ा दूं, मैं ईमान से कहता हूं कि मैं इसको कभी काफी नहीं समझता और हुजूर के जरिये से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं चाहता था और मेरा दिल चाहता था कि उनके लिये मैं कुछ ज्यादा बढ़ा दूं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि इन ५ रुपये के बढ़ने से बजट पर यह असर पड़ा है कि ३ १/२ करोड़ रुपया साल बजट में खर्च बढ़ गया। हमारी ख्वाहिश उनके लिये सिर्फ कहने की ही नहीं है बल्कि हमेशा करने की भी है। दुनिया का उसूल है कि कहना तो आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। दुनिया इस बात को जानती है और मसल मशहूर है, लेकिन हम वाकई इस काम को करना चाहते हैं कि छोटों की तनख्वाहों के फर्क को घटा कर उस दर्जे पर ले जायं जिस दर्जे पर उनकी तनख्वाहें पहुंच जानी चाहिये। यह वाकया है कि हमारी केन्द्रीय सरकार के जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह ज्यादा है और हमारी जो पे कमेटी सन् ४७ में बैठी थी उसने भी इस बात की सिफारिश की थी और उसके मुताबिक पिछले बजट में हमने कुछ रुपया रख कर उनके वेतन बढ़ाये भी थे। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती हैं और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि फलां-फलां काम नहीं किये जाते हैं जैसे शफाखाने भी लाओ, मदरसे भी लाओ, यह भी लाओ वह भी बढ़ाओ और खाद का भी अच्छा इन्तजाम हो, सिंचाई का भी हो और जब इस सब के लिये टैक्स लाया जाय तो कहा जाता है कि निकल जाओ हम यहां आकर बैठेंगे। इसलिए जितना मुमकिन है वह हम कर रहे हैं।

मोटरों के ऊपर जो टैक्स बढ़ा है उसके बारे में भी कहा गया। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे इस टैक्स का मदरास से मुकाबिला कर लो। बस इसका जवाब इतना ही मेरे पास है और वह काफी है। राजस्थान से भी आप मुकाबला चाहें तो करलें।

एक और बात को सुन कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, 'बासी कढ़ी में उबाल आया सदियों के बाद।' कितने ही बरसों से यहां पर कोर्ट फीस लगती है लेकिन मुझ पर टूट पड़े कि तुमने.....

(आवाजें---माइक पर बोलिये न)

हुजूरवाला, मेरे लिये तो वह (माइक) मंगवा दीजिये जो यहां लटकी रहती है, मैं वह लटका लिया करूंगा। मुझे हर दफा मुसीबत आती है। खैर, कोर्ट फीस लगायी हुई है। यहां

ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में जो मुकदमा दायर करता है उसके ऊपर कोर्टफीस लगती है और कोई दरख्वास्त देता है तो टिकट लगाता है। उसके ऊपर भी ऐतराज हुआ। मुझ बेचारे ने उसमें कुछ नहीं किया। जैसा पहले से चला आया है, वैसा का वैसा है। मैंने नहीं छुआ, उसको कतन। अंग्रेज का गुस्सा मुझ पर उतर गया। लगा गया कम्बख्त और, मेरी मुसीबत हो गयी। लगा रखा है सारे मुल्क ने। तमाम हिन्दुस्तान ने लगा रखा है। एक बात। दूसरी यह कि कोर्ट फीस तो लगी हुई है। सच बात कहूं आपसे! कोर्ट फीस लगी हुई है। कोर्ट फीस देने की लोगों को आदत पड़ चुकी है, और अगर उसकी जगह मौकूफ करके नया टैक्स लगाऊं तो हुजूर क्या करूंगा, कहां रहूंगा मैं, फिर मैं निकलूंगा यहां से। इसका नतीजा इसके सिवा क्या है? तो मैं बेवकूफ हूं जो कोर्ट फीस बढ़ाता हूं। मेरे जिम्मे यह इल्जाम भी है जो इल्जाम लगाया गया।

मिलें, मिल का लफ्ज जो है जब वह लफ्ज कहा जाय तो आदमी के दिमाग में बड़ाई आती है। छोटी-छोटी वह मिलें कहलाती हैं। बड़ी छोटी छोटी। कहा गया कि वह नौ डिस्कंटीन्यू हो गयीं, यू० पी० के अन्दर। दुनिया में रोज आदमी मरते और पैदा होते हैं। दुनिया में जाकर देखिये रोज कोई इंडस्ट्री तबाह हो रही होगी, कोई फ्लरिश कर रही होगी। हर रोज खत्म होंगी और बनेंगी। जो पुरानी थीं उनको कह दिया चली गयीं। फैक्ट फाइंडिग कमेटी की रिपोर्ट से और जो रीजन लिखा था वह छूट गया। उन्होंने लिखा कि वह अनइकोनामिक यूनिट्स थीं। यह रिपोर्ट मेरे पास है। इसमें लिखा हुआ है।

श्री त्रिलोकीसिंह--पढ़िए कहां लिखा हुआ है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--हां, लिखा हुआ है। वह सफा बतलाये देता हूं। मैंने खुद ही पढ़ा है। उन्होंने लिखा अनइकोनामिक वह थीं। खुद सरकार की कायम की हुई नहीं थीं, प्राइवेट थीं। अपनी जिन्दगी मुश्किल से गुजार रही थीं। वह खत्म हो गयीं, मर गयीं। वह तो कह दिया। यह हुजूर, ३३ की मेरे पास लिस्ट है और भी कितनी जो यहां नयी डेवलप हो गयी हैं, मैंने अभी अपनी स्पीच में मुफस्सिल जिक्र किया कि इंडस्ट्री किस तरीके से डेवलप हुई हैं इन पिछले तीन सालों में। इस वक्त ३३ की फेहरिस्त मेरे पास मौजूद है, उनकी हालत आज मौके पर जाकर देखी जाय कि फ्लरिश कर रही है या नहीं। तो उसका भी जिक्र हो जाता। वह फारसी का एक फिकरा है मशहूर, जिसके मतलब हैं ऐब तो उसके बयान किये, कोई हुनर था तो वह भी बयान कर देते।

शुगर केन यू० पी० में और शुगर केन बम्बई में और साउथ में जमीन आसमान का फर्क। न मुझे जमीन बनाना आता है, न हवा बनाना आता है, न धूप बनानी आती है। इन चीजों में से किसी चीज को बना नहीं सकता। वहां बम्बई में और साउथ में जो जमीन है उसमें १८ महीने में जा करके गन्ना तैयार होता है और यहां यू० पी० में ९, १० महीने में। तब सोचिए कि ६, ७, ८ महीने के बाद जो गन्ना तैयार होगा कितना तो वह बड़ा होगा और कितना उसमें शुगर कन्टेंट ज्यादा होगा? वहां के गन्ने में शुगर कन्टेंट बमुकाबिले यू० पी० के गन्ने के ज्यादा होता है। अब मुझ पर इल्जाम यह कि यहां क्यों नहीं कर लिया, इतना ही शुगर कन्टेंट? अब खुदा के यहां दरख्वास्त भेजूं कि वहां जैसी क्लाइमेट यहां कर दे। तब तो हो सकता है वर्ना हो नहीं सकता। नवम्बर के महीने से जो सर्दी शुरू होती है तो ग्रोथ को स्टन्ट करती है, ग्रोथ को रोकती है और वहां की क्लाइमेट में सर्दी होती नहीं है, यहां से बिल्कुल दूसरे किस्म की है, इसलिये वहां गन्ना खूब फूलता है। तो मैं तो यह नहीं कर सकता।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

अब अगर साइंस के तरीके निकल आयें जिनसे हम बादल बना सकें, पानी बरसा सकें, तो मुमकिन है वहां ऐसी क्लाइमेट करके हम भी शुगर कन्टेंट बढ़ा लें। मगर इस वक्त तो मुमकिन नहीं है उसका करना।

कहा गया इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स यू० पी० में सबसे ज्यादा हैं। मैं यह अर्ज करूं कि पोजीशन यह है कि कहीं से ज्यादा हैं और कहीं से कम। और कितने ज्यादा हैं वह भी अभी मालूम हो जायंगे, बहुत थोड़े ज्यादा हैं और उसको पढ़ने से पहले यह और अर्ज कर दूं कि बावजूद इस बात के जो मैं कह रहा हूं, एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारे यहां है उसको मैंने यह क्वेश्चन रिफर किया, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत के बारे में। दैट बोर्ड इज सीज्ड आफ दैट क्वेश्चन। और उसने गवर्नमेंट आफ इंडिया के तीन ऐक्सपर्ट्स को मुकर्रर किया है कि यहां का जो प्राइस स्ट्रक्चर है उसको जांच करके और अपना रिजल्ट निकाल करके हमें बतायें ताकि उसकी रोशनी में जो कुछ कर सकते हैं वह करें हम और यह देखें कि कितनी कीमत यहां रहनी चाहिये। रेट्स मैं सुना दूं--

"The rates charged for industrial purposes are uniform. For large industries working approximately at an average of 18 hours per day for 300 days in the year the rate comes to 10.3 Pies per unit."

यह कम है उस रेट से जो पंजाब में है। वहां है ११.१ पाई पर यूनिट, आन्ध्र में है १६ पाई पर यूनिट, दिल्ली में है १२.२ पाई पर यूनिट, मद्रास में है १०.८५ पाई पर यूनिट, दामोदर वैली में १२.४५ पाई पर यूनिट। अच्छा, बाम्बे से ज्यादा है २ पाई, कलकत्ते से ज्यादा है २ पाई बस। इतने तो मुकाबिले मेरे पास हैं। इससे अन्दाजा हो सकता है कि यहां बिजली की कीमत क्या है और फिर जो मैंने अर्ज किया कि मैं इस फिक्र में हूं कि बिजली की कीमत और कुछ ठीक की जा सकती हो, वह की जाय। इसलिए उसको उस कमेटी को देकर के जो कार्यवाही हो सकती है वह कराई जा रही है। एक बात और कही गई। बड़ी साफ और खुली हुई बात है। कहा गया कि लाइसेंसी जो है वह कम कीमत पर हाइड्रिल से बिजली लेता है और कन्ज्यूमर से ज्यादा कीमत चार्ज करता है। जाहिर बात है कि लाइसेंसी हाइड्रिल से बिजली लेगा और फिर उस शहर के अन्दर अपने सारे तार बिछायेगा, खम्भे गाड़ेगा, तमाम इन्तजाम रोशनी का करेगा, उसके ऊपर भी वह खर्च करेगा। तो उस सब खर्च को मिला कर जो कीमत होगी वह कीमत वह लेगा। और कीमत की पोजीशन यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का ऐक्ट है जिसमें यह लिखा हुआ है, यह तय कर लिया गया है कि किसी लाइसेंसी का नफा ५ फीसदी से ज्यादा नहीं होगा। तो उसके एकाउंट ही हर साल चार्टर्ड एकाउटेंट के जरिये से जांच होती है कि आया उसका मुनाफा जो है वह बढ़ा तो नहीं है और अगर बढ़ा है तो फौरन उसका रेट जो है वह चेंज कर दिया जाता है। तो उसकी पोजीशन यह है जो मैंने अर्ज कर दी। अब उसमें एक बात और कही---शायद वैसे ही मुंह से निकल गई, इरादतन शायद नहीं कही कि साहब ६ आने से ज्यादा भी कहीं बिजली बिकती है? यह यू० पी० के शहर जो हैं उनकी फेहरिस्त है यह। पढ़ने को कहें तो पढ़ दूं। आठ आने भी हैं, नौ आने भी हैं बिजली। यह बात शायद इसलिए कही गई कि मैंने अपनी बजट स्पीच में यह अर्ज किया था कि हम ड्यूटी ५ फीसदी घटाते हैं इंडस्ट्री के लिए। २५ फीसदी के बजाय २० फीसदी कर रहे हैं। तो वह तो मैंने अर्ज किया इंडस्ट्री के लिए और जो लोग कन्ज्यूमर्स हैं, डोमेस्टिक कन्ज्यूमर्स उनके लिए यह किया गया है कि छः आने से कम जहां कीमत है पर यूनिट, वहां ड्यूटी नहीं लेंगे। अब जो लगी थी वह नौ आने पर लगी थी। नौ आने पर यूनिट अगर कीमत थी तो नहीं लेते थे। उसके सिलसिले में यह कहा गया कि ५, ६ आने से कम कीमत इस वक्त कितनी जगहों में है? वह उसकी फेहरिहत मौजूद है।

श्री गेंदासिंह—गोरखपुर में है और बिजनौर में है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—गोरखपुर और देवरिया का तो मैं बड़ा इश्त्याक हूं। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि मुझे उनसे बड़ी मुहब्बत है। मालूम नहीं क्यों? शायद जिसको कभी देखा न हो उसके लिये बहुत इश्त्याक होता है। मैं भी गोरखपुर और देवरिया को देखने का बहुत इश्त्याक था और जो मैंने उनकी हालत को जाकर के देखा तो मैंने यह सोचा कि इनको कुछ खिदमत की जरूरत है, वह खिदमत मैं भी करूं। चुनांचे बिजली मैंने वहां देवरिया में भी पहुंचायी और आगे को भी बढ़ाकर के पहुंचाने वाला हूं। मेरे पास तो पैसा होता है। वह माल मंत्री बैठे हैं, जितना मांगते हैं वहां के लिये जब जरूरत होती है, बड़े शौक से वह पूरा कर देता हूं। अल्लाताला, वहां के आदमियों को आराम दे, जो उनकी तकलीफ है वह दूर हो। वह भी तरक्की करें, फलें फूलें और ऐसे शहर हो जांय जैसे कि लन्दन और पेरिस। मैंने गलत कहा। उस समाजवाद में वह शहर नहीं आते पेरिस और लन्दन।

केवल दो तीन बातें कही गई हैं माल के मुताल्लिक। एक तो यह कहा गया कि जो रेकार्ड्स हैं उनमें बहुत शिकायतें हैं। सन् ३९ से लेकर सन् ५१ तक के जमाने में कुछ ऐसा गुजरा कि पटवारियों को जो रिकार्डस लिखते थे उनको उस काम को देखने का मौका नहीं मिला। उसमें बहुत सी गल्तियां हो गईं, लेकिन मैं अर्ज करूं कि माल मंत्री बैठे हैं, उनके सामने कहता हूं मुझको यह मालूम हुआ है कि उसको ठीक करा दिया गया है और उसमें ५ फीसदी बाकी हैं और ९५ फीसदी गलतियां सही हो चुकी हैं और जो गलत था उससे किसी को शिकायत नहीं थी। मौके पर मेरा कब्जा होना चाहिये था वह मेरा ही रहा, लेकिन कागज में मेरा नाम नहीं है।

दूसरी बात यह कही गई कि कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स का काम हो रहा है। उस के लिये यह बात कही गई कि जब तक बटवारे का हक न दिया जाय वह मामला ठीक नहीं बैठता। मुझे बतलाया गया कि बटवारे का हक दे दिया गया और कानून में अमेंडमेंट कर दिया गया है जिससे वह बटवारा हो सके और उस बटवारे के बाद कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स की कार्यवाही हो सके।

तीसरी बात यह कही गई टेस्ट वर्क्स पर जो मजदूरी दी जाती है ८ आना, ६ आना और ४ आना वह बहुत कम है। उसके मुकर्रर करने में एक बड़ा भारी उसूल है और वह यह है कि मजदूरी उस वक्त इतनी नहीं लगाई जायगी कि जिससे कोई गैर मोहताज आदमी आ कर वह मजदूरी ले ले और उस टेस्ट वर्क में शरीक हो जाय, लेकिन इस लेविल पर भी उसको रक्खा गया है जितने में वह पेट भी भर सके। १८ छटांक एक आदमी का रोजाना का खाना है, वह उसको उसमें मिल जाता है। उसके हिसाब से मजदूरी कम नहीं है और अक्लमन्दी यह है कि कोई नाजायज फायदा न उठा सके और वहां फ्राड न हो सके। अगर १२ आना, सवा रुपया मजदूरी मिलती है तो हम भी भूखे बन कर चले जायंगे, हालांकि भूखे नहीं हैं, लेकिन भूखे बनकर चले जायंगे।

श्री गेंदासिंह—लेकिन वह चार आना मजदूरी तीन हफ्ते तक भी न दी जाय इसमें भी कोई अक्लमन्दी है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जरूर वक्त पर मिलना चाहिये, लेकिन दुनिया में यह भी हमेशा मुमकिन है बावजूद हर रोज मिलने के कि कभी वक्त पर न मिल सके। कोई सर्कम-स्टैंसेज ऐसे भी होते हैं कि उस सूरत में न मिल सकें तो उसकी कोई शिकायत नहीं हो सकती और उसको यहां खड़े होकर रोया जाय।

एक बात यह कही गई कि जो बस वाले हैं उनको कोई एमेनिटीज नहीं मिलतीं। उसमें एक बात तो यही है कि बजट पढ़ा नहीं। यह जो शेड्यूल आफ़ न्यू डिमांडस हैं जिसकी अलग किताब है, उसे पढ़िये। उसमें रोडवेज के जो कंडक्टर्स हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिये

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]
रुपये रक्खे गये हैं और जो लोग गैर मुस्तकिल हैं उनको पर्मानेंट करने के लिये प्रोपोजल हैं। शिड्यूल आफ़ न्यू डिमांड में उनको परमानेंट करने का प्रोपोजल उसके अन्दर रखा गया है। बस स्टेशन बनाने के लिये रुपया रक्खा हुआ है। ये अमेनिटीज उनको दी जा रही हैं, किसी और को नहीं दी जा रही हैं।

एक साहब को सुनकर मुझे अफसोस हुआ। वह साहब शायद इस बुंदेलखंड में नहीं रहते। उन्होंने कल अपनी तकरीर में शिकायत की और इस लहजे में की कि मुझे महसूस हुआ कि उनके दिल में बड़ा दुख है, लेकिन वह बड़े भारी मुगालते में थे। उन्होंने कहा क्या? यह कि बुंदेलखंड कमबख्त में आजकल कुछ भी न हुआ और वहां हुआ क्या क्या? सन् ५२ में मैंने इर्रीगेशन छोड़ा, सन् ५२ तक मेरे पास था। ६ या ७ डैम्स बनवा करके मैंने छोड़ा है खुद, और उसके बाद बनवाने वाले वह बैठे हैं, जिन्होंने अब इर्रीगेशन छोड़ा है। उन्होंने शायद ८-९ या १० बना दिये हैं। जरा जाकर देखो तो कि कितने बड़े-बड़े हैं और हमने तो खुद भी बनते हुये दिखलाया। उनसे कई लाख एकड़ की आबपाशी वहां होने लगी जो नहीं होती थी। तो मैं सोचूं कि या अल्लाह, इस यू० पी० के अन्दर अगर कोई कांग्रेस गवर्नमेंट का मशकूर हो सकता था तो सबसे पहले बुन्देलखंड को होना चाहिये था। मगर वहां से जो निकली तो यह बात निकली कि साहब वहां कुछ हुआ ही नहीं। उल्टी शिकायतें हुई हैं।

इर्रीगेशन रेट्स की बाबत कहा गया। हमारे यहां के जो इर्रीगेशन रेट्स हैं उन की बाबत कहा गया कि वह तमाम स्टेट्स के मुकाबले में हाइयेस्ट हैं। उस वक्त मैं यह समझा कि शायद मेरे दोस्त लीडर आफ अपोजीशन कभी पढ़े हों, वरना मैंने नहीं पढ़ा। वह है गोरखधंधा मेरे यहां तो सीधा-साधा मामला है, वह यह कि हम पानी जितना देते हैं उस के ऊपर फिर हिसाब बैठाते हैं और जिन्स के ऊपर लगाते हैं। गेहूं, गन्ना, फलां चीज, सब पर पानी के हिसाब से लगाते हैं। मैं यह भी नहीं कह सकता कि जितने वह कम यहां हैं उतने कहीं नहीं, लेकिन उनको ज्यादा भी नहीं कह सकता। बाम्बे में, पंजाब में और कई जगह हैं, मुझे याद नहीं उनके रेट्स जो मैंने देखे तो वहां फ्लैट्स रेट्स हैं। वहां गन्ने के ऊपर १२० रुपया फी एकड़ है और हमारे यहां शायद २६ रु० फी एकड़ है। ऐसे ही और हैं। यह फर्क और उस का मुकाबला करना, वह मेरे नजदीक बिलकुल गलत है। उस कम्पेरीजन की बिना पर यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे रेट्स उनसे ज्यादा हो हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है।

श्री त्रिलोकीसिंह--पंजाब में ४५ रु० है।

श्री चरणसिंह--लेकिन हमारे यहां २६ रुपया ही है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--कार्मशियल अंडरटेकिंग्स को निस्बत एक साहब को दिखाई दिया बजट में कि यह सब नुक्सान में चल रहे हैं। अब बजट के पन्नों को पलट कर देखा जाय और एक एक गवर्नमेंट की कर्मशियल अंडरटेकिंग को देखा जाय। गवर्नमेंट की कर्मशियल अंडरटेकिंग्स में से एक कौंसा है, कहां उसमें नुक्सान है? कहीं नुक्सान उसमें मिला? इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी है, उसमें कहां नुक्सान है? रोडवेज हैं उनमें कहां नुक्सान है? हां, बिजली के मामले में हो सकता है जिसके बारे में मैं खुद कह रहा हूं। इसके पिछले बजट को देखिये कि यह जो पावर स्टेशन खटीमा बना है, उसमें काफी रुपया खर्च हुआ है। उस सबका अगर एकाउंटिंग कर लिया जाय तो नुक्सान हो सकता है, लेकिन वह ऐसी चीज है जिसको हम अपने आप बिजली की कीमत से पूरा कर सकते हैं।

इसी तरह से एक साहब ने कहा कि रिजर्व फंड बिल्कुल गायब ही है। यह तो जानी हुई बात है कि रिजर्व फंड दुनिया में कई दफा गायब होता है और जन्म लेता है। रिजर्व फंड में माना। हमने ६ करोड़ रुपया रखा है। अगर स्केअरसिटी हुई और रुपया सब खर्च हो गया तो वह खत्म हो जाता है। इस फंड के अन्दर तो रुपया

आता जाता रहता ही है । हमने रेवेन्यू रिजर्व फंड इसलिये थोड़ा ही बनाया कि इसे हाथ नहीं लगायंगे । अगर इसलिये फंड में रुपया रखना है तो मैं कहूंगा कि उस रुपये को रख कर जुल्म करना है और इलेक्टोरेट के ऊपर भी जुल्म करना है अगर रुपये को खर्च में न लाया जाय वरना रुपया तो खर्च करने के वास्ते रखा ही जाता है । रिजर्फ फंड तो अहतियात के लिये रखा जाता है । इसका नतीजा यह निकला कि इस स्टेट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेफ हो गई ।

मैंने अपनी स्पीच में कर्जे की पोजीशन को बिल्कुल साफ-साफ बयान कर दिया था जिससे लोग उसको समझ सकें । यह बात जरूर है कि जितना कर्जा हमने मांगा है उससे ज्यादा ही हमको मिला है । हमने एक दफा ८ करोड़ मांगा था तो हमको ८ करोड़ ८० लाख रुपया मिला । हमने दूसरी दफा दस करोड़ मांगा तो हमें उससे ज्यादा ही मिला । फिर भी यह कहा गया कि हमारी स्टेट दिवालिया बन गई । अगर कोई ऐसा बेवकूफ हो कि दिवालिया को भी कर्जा दे दे तब तो बात दूसरी है । मेरी साख ऐसी बनी हुई है कि इतना रुपया चाहिये, उतना ही मिल जाता है । अच्छी सरकार के कर्जे की हकीकत क्या है ? वह मैं आप से अर्ज करूं । बाजार का कर्जा ४२ करोड़ रुपया है । मैं एक बात आप से फाइनेन्स मिनिस्टर होने की हैसियत से कहूं कि रुपया न होने के वजह से किसी स्टेट को स्टार्व कराना जुल्म है, गुनाह है । रुपया फिनेन्स मिनिस्टर और उसका स्टाफ सब स्टेट के लिये है । इतने दिनों में आकर ४२ करोड़ रुपया हुआ और उसके साथ में मैंने अपनी बजट स्पीच में बता दिया है कि हर एक कर्जे की अदायगी के लिये फंड मुस्तकिल है । तो फिर वह कर्जा कायम कैसे रहेगा ? अगले साल एक कर्जे की बेबाकी का वक्त आ रहा है तो उसका मुस्तकिल फंड है । जो कर्जा गवर्नमेंट आफ इंडिया का है उसकी अदायगी का जो इन्तजाम है वह भी मैंने बयान कर दिया । जितना जितना रुपया उनका आता है उसकी भी किस्तें मुकर्रर होती हैं और वह हम बराबर अदा करते हैं, तो क्या इसलिये कि यह लेखा जोखा बराबर रहे ? आज मैं इस हाउस में हुजूर के सामने अर्ज करना चाहता हूं कि यू० पी० क्या, कोई राज्य हो, यह नहीं किया जायगा कि रुपये की कमी की वजह से उस राज्य की तरक्की न की जाय । जरूर रुपये का इन्तजाम होगा चाहे जिस तरीके से भी हो । हम स्माल सेविंग्स स्कीम चलाते हैं । पिछले साल से, पिछले साल १२ करोड़ रुपया हमने उससे पाया और पिछले साल ९ करोड़ रुपया पाया । वह रुपया असल में गवर्नमेंट आफ इंडिया का है, हमारा शेयर है उसमें । मगर मैं तो मिलने को कह रहा हूं । मैं यू० पी० के रहने वालों की तरफ से मायूस नहीं हूं, ये बड़े बाहिम्मत इन्सान हैं । ये कभी इसको गवारा नहीं करेंगे कि पैसे की वजह से स्टेट की तरक्की न हो ।

कहते हैं गांवों में कुछ नहीं हुआ । हैरत की बात है । शायद उस तरफ न हुआ हो मगर ट्यूबवेल तो हमने उधर भी बनाये हैं । उनको कौन इस्तेमाल करता है ? नहरों को कौन इस्तेमाल करता है ? गांवों में जो शफाखाने खुले हैं वे किसके लिये हैं ? जो सड़कें वगैरह वहां बनी हैं वे किसके लिये हैं ? क्या आज गांव वालों की हालत वही है जो कुछ साल पहले थी ? मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा नहीं है । मैं मुहम्मद इब्राहीम, नजीबाबाद कांस्टीटुएंसी का एम० एल० ए० भले ही यह कह दूं, लेकिन गांव वाला यह नहीं कहता है । वह जानता है कि वह तरक्की कर रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---अब आपके एक मिनट रह गये हैं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, बिल्कुल एक मिनट में खत्म करता हूं । केवल एक फिकरा और यह वह कि किसी काम के मुताल्लिक रोना-पीटना बहुत गलत बात है । यह बड़ी डिस्करेज करने वाली बात है । यहां तकरीरें करके बाहर पहुंचाना और जब लोगों पर पहुंचें तो उनकी तबियतों पर क्या असर होगा कि ये हमारे नुमाइन्दे हैं ।

[श्री हाफिज मुहम्मद इबाहीम]

अगर कोई हकीम हो और किसी को न भी बुखार हो और वह कह दे नब्ज देख कर कि तुमको बुखार है तो न जाने क्या हाल हो जायगा उसका, उसकी हिम्मत टूट जायगी, वह शुबहे में पड़ जायगा कि क्या न हो जाय। तो इस किस्म की बातें कहना नामुनासिब है। जो बातें सही हैं मैं उनको मानता हूं। हजारों गलतियां हमारे कामों में निकलेंगी। मैं इसका कायल नहीं हूं और मैं से मेरा मतलब डाक्टर सम्पूर्णानन्द की बनाई हुई इस गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश से है कि यह इसको कायल नही है कि वह ऐबों से पाक है और न हम में कोई खामियां हैं और न कमियां। हममें कमियां हैं उनको दूर करना है। जो हमारे काम हैं उनमें बीसों पचासों गलतियां पायी जायेंगी। सहारनपुर से लेकर बलिया तक इतना बड़ा हिस्सा हिन्दुस्तान का हो, एक एक जगह की एक एक गलती हो तो सारे सूबे को गिनकर ५० हो जायेंगी। तो उसे गिन सकते हैं, लेकिन लोगों के अन्दर इस किस्म की भावना नहीं पैदा करना चाहिये। उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिये और इस सदन के मेम्बरान याद रखें इस बात को कि यही वक्त है "नाऊ आर नेवर" अगर यू० पी० को बनाना है तो, और अगर हिन्दुस्तान को बनाना है तो यही वक्त है अब बनेगा वर्ना नहीं बनेगा।

(इसके बाद सदन ६ बज कर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२५ जुलाई, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२६ पर)

गेहूं, चना और जौ के ६ जुलाई, १६५७ ई० के तुलनात्मक भावों की तालिका

मंडी	गेहूं मूल्य	गेहूं अन्तर (+)या(-)	गेहूं प्रतिशत (+)या(-)	चना मूल्य	चना अन्तर (+)या(-)	चना प्रतिशत (+)या(-)	जौ मूल्य	जौ अन्तर (+)या(-)	जौ प्रतिशत (+)या(-)
मेरठ ..	१६.०६	(-) ०.०६	(-) ०.३७	११.७५	(+) ०.७५	(+) ६.४०	११.००	(+) १.५०	(+) १३.६३
वाराणसी ..	१६.००			१२.५०			१२.५०		
जालौन ..	१४.७५	(+) ४.२५	(+) २८.८	११.७५	(+) २.२५	(+) १६.१५	१०.७५	(+) ३.००	(+) २७.६०
गोरखपुर ..	१६.००			१४.००			१३.७५		
बरेली ..	१६.५०	(+) २.०	(+) १२.१२	१२.३०	(+) २.५०	(+) २०.०	११.२५	(+) २.२५	(+) २०.०
देवरिया ..	१८.५०			१५.००			१३.५०		

अमर उजाला

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३२ पर)

पट्टी चौगढ़, विश्जूला, चौमैसी व मल्लोरौ में जिला नियोजन विभाग, नैनीताल के अन्तर्गत सम्पादित विकास एवं निर्माण कार्यों की तालिका

क्रमांक	नाम योजना	नाम स्थान	अन्य विवरण
१	२	३	४
पट्टी नौगढ़—			
१	प्राइमरी पाठशाला भवन-निर्माण	ल्वाड़	यह कार्य लगभग पूर्ण होने को है इसके लिये १,००० रु० अनुदान स्वीकृत हुआ है।
२	बहुधन्धी भवन ..	डालकन्या	यह कार्य पूर्ण हो चुका है तथा स्वीकृत अनुदान का भुगतान किया जा चुका है।
३	मार्ग-निर्माण ..	गौनियां से ल्वाड़ तक	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत अनुदान का भुगतान किया जा चुका है।
४	पेय जल डिग्गी ..	चौड़ाजाला कुनडैल	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ३७३ रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
५	पेय जल नौला ..	सुवाकोट	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ३०० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
६	पेय जल नौला ..	कुमल्टा	कार्य लगभग पूर्ण होने को है। इस कार्य हेतु ३०० रु० का अनुदान स्वीकृत है।
७	पेय जल नौला ..	पोखरीमटैला	,, ,, ,,
८	प्राइमरी पाठशाला भवन का जीर्णोद्धार	कुमल्टा	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत १०० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
९	पेय जल डिग्गी ..	हत्यारी लाल	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत २०० रु० के अनुदान का भुगतान किया जा चुका है।
१०	मार्ग का जीर्णोद्धार ..	चामाः धरमपुर	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत १५० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
११	,, ,, ..	कुमल्टाः पतलोट	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत १०० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
१२	,, ,, ..	डालकन्याः अमजड़	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ३०० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
१३	प्राइमरी पाठशाला भवन-निर्माण	सुवाकोट पोखरी	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत १,१०० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
१४	पेय जल नौला-निर्माण	मेलचौड़	,, ,, ,, ३०० रु०

क्रमांक	नाम योजना	नाम स्थान	अन्य विवरण
१	२	३	४
१५	पेय जल नौला-निर्माण	कटौजिया	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत १७५ रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
१६	पेय जल योजना (नौला)	कुमल्टा (हरिजनों के लिये)	,, ,, ,, ५०० रु०
१७	सामूहिक उद्यान ..	हत्यारी लाल	,, ,, ,, ४०० रु०
१८	सड़क निर्माण ..	हत्यारीलाल बनौलिया	,, ,, ,, ५०० रु०
१९	प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण	ल्वाड़	कार्य पूर्ण होने को है तथा इस कार्य हेतु ५०० रु० का अनुदान स्वीकृत है।
२०	बहुधन्धो पुनः निर्माण	लूगढ़	कार्य हो गया है तथा स्वीकृत २,००० के अनुदान से १,५०० रु० का भुगतान किया जा चुका है परन्तु भवन निर्माण में कुछ कमियां दूर को जानो शेष हैं।
२१	मार्ग निर्माण ..	कोन्ताः भमूड़ीधार	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ५०० रु० का भुगतान किया जा चुका है।
२२	पेय जल गूल ..	झड़गांव	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ३०० रु० का अनुदान का भुगतान हो चुका है।
२३	पेय जल नौला ..	टांडा	,, ,, ,, २०० रु०
२४	मार्ग निर्माण ..	गलनी–कालाआगर	,, ,, ,, २०० रु०
२५	मार्ग निर्माण ..	कौन्ता: लुगढ़	,, ,, ,, २०० रु०
२६	प्राइमरी पाठशाला भवन	ककोड़	,, ,, ,, १,००० रु०
२७	पेय जल पाइप लाइन	गरगड़ी	,, ,, ,, १,००० रु०
२८	बहुधन्धी भवन निर्माण	गरगड़ी	,, ,, ,, ५०० रु०
२९	सामूहिक उद्यान ..	ककोड़	कार्य पूर्ण हो गया है स्वीकृत २,००० रु० से १,५०० रु० का भुगतान किया जा चुका है।
३०	सामूहिक उद्यान ..	गलनी	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत १,००० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
३१	पेय जल नौला ..	तल्ला झड़गांव	स्वीकृत ६०० रु० के अनुदान का भुगतान पूर्ण होकर हो चुका है।
३२	हाताबन्दी जू० हा० में	गलनी	कार्य चालू है इस हेतु ५०० रु० का अनुदान स्वीकृत है।
३३	पोलट्री डेवलपमेंट ..	श्री प्रेमपुरी गोस्वामी मौजा गलनी	कार्य पूर्ण होकर १५० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
३४	बन विकास ..	ल्वाड़	कार्य चालू है इस हेतु ३,००० रु० का अनुदान स्वीकृत है।

क्रमांक	नाम योजना	नाम स्थान	अन्य विवरण
१	२	३	४
३५	पाइप लाइन निर्माण. .	डालकन्या	कार्य चालू है स्वीकृत १५,००० रु० के अनुदान में लगभग ६,००० रु० अग्रिम धन के रूप में दिया जा चुका है।
३६	पाइप लाइन . .	मटेला	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ४,००० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
३७	पाइप लाइन (हरिजनों के लिये)	मटेला	,, ,, ,, ९०० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
३८	पेय जल गूल . .	अधौड़ा हुगरी	,, ,, ,, ९३३ रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
३९	पोखरी वन विकास . .	पोखरी	इस कार्य हेतु १,००० रु० स्वीकृत है परन्तु कार्य प्रारम्भ अभी नहीं हुआ है।
४०	पेय जल गूल . .	साल	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ४७० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
४१	पाइप लाइन . .	बड़ौन	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ७,००० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
४२	पेय जल नौला निर्माण	रोठा बड़ौन	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ५३३ रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
४३	पेय जल डिग्गी . .	तल्ला झड़गांव	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ८५० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
४४	पेय जल नौला . .	गरगड़ी	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ४५० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
४५	पेय जल नौला . .	साल	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ३५० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
४६	सामूहिक उद्यान . .	गरगड़ी	,, ,, ,, १,००० रु०
४७	बन विकास कार्य . .	ग्रामः गोजा	,, ,, ,, २,००० रु०
४८	बन विकास कार्य . .	चमोली	,, ,, ,, २,००० रु०
४९	बन विकास कार्य . .	लूगढ़	कायू चालू है, स्वीकृत ३,००० रु०
५०	पाइप लाइन	चमोली	कार्य चालू है, स्वीकृत अनुदान ८,००० रु० है।
५१	पाइप लाइन . .	टिम्मरकोन्ता	कार्य चालू है। इस योजना हेतु ८,००० रु० स्वीकृत है।
५२	पाइप लाइन . .	पटरानी	कार्य चालू है। । इस योजना हेतु २ ४०० स्वीकृत है।

क्रमांक	नाम योजना	नाम स्थान	अन्य विवरण
१	२	३	४
५३	पाइप लाइन ..	बुक्सौड़ी	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ६,१२० रु० का भुगतान हो चुका है ।
५४	पाइप लाइन ..	गरगड़ी (हरिजनों के लिये)	कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है । इस कार्य कार्य हेतु ६,००० रु० स्वीकृत है ।
५५	पेय जल डिग्गी ..	कालाआगर	कार्य चालू है । स्वीकृत अनुदान जो ७३४ रु० है में से अग्रिम धन कार्य चलाने हेतु दिया गया है ।
५६	पेय जल डिग्गी ..	मटेला	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ६०० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है ।
५७	लूगढ़–बड़ौन मार्ग	लूगढ़-बढ़ौन	कार्य पूर्ण हो गया है, परन्तु अभी पूर्ण भुगतान नहीं हुआ है ।
५८	मार्ग निर्माण ..	पतलोट–डालकन्या	कार्य प्रारम्भ है ।
५९	मार्ग निर्माण ..	अमजड़–दुर्गापीपल	यह मार्ग ३ मील लम्बा है । इसका सर्वे किया जाना है ।
६०	मार्ग निर्माण ..	साल	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ३०० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है ।
६१	पेय जल एवं सिंचाई योजना	लगढ़	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत २९,५०१ रु० १४ आ० के अनुदान का भुगतान किया जा चुका है ।

पट्टी विश्जूला

१	पेय जल डिग्गी ..	सुई	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ६०० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है ।
२	पेय जल डिग्गी ..	सिलड़ा	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ६०० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है ।
३	पाइप लाइन मरम्मत	ओखलकांडा	कार्य पूर्ण होकर ३०० रु० के स्वीकृत अनुदान का भुगतान हो चुका है ।
४	पेय जल नोला व होज	सुरंग	३०० रु०
५	पाइप लाइन निर्माण	न्यूरीगाड़	इस योजना हेतु ७५० रु० स्वीकृत था जिसमें से अग्रिम धन के रूप में दिया जा चुका है शेष भुगतान कार्य में कुछ कमियां होने से नहीं हुआ है ।
६	मार्ग निर्माण	खनस्यू	कार्य पूर्ण होकर २०० रु० के स्वीकृत अनुदान का भुगतान किया जा चुका है ।

क्रमांक	नाम योजना	नाम स्थान	अन्य विवरण
१	२	३	४
७	पेय जल नौला निर्माण	भनपोखरा	कार्य पूर्ण होकर १०० रु० के स्वीकृत अनुदान का भुगतान किया जा चुका है ।
८	हौज निर्माण ..	करायल	,, ,, ,, ७५ रु०
९	बहुधन्धी भवन ..	तषुराड़	,, ,, ,, १,००० रु०
१०	बहुधन्धी भवन ..	देवली	कार्य पूर्ण हो गया है तथा स्वीकृत १,००० रु० के अनुदान का भुगतान किया जा रहा है ।
११	पेय जल डिग्गी ..	ड़ोवा	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ४०० रु० के अनुदान का भुगतान किया जा चुका है ।
१२	,, ,, ..	लोटयाना	कार्य पूर्ण हो गया है तथा स्वीकृत ३२२ रु० के अनुदान का भुगतान किया जा रहा है ।
१३	प्राइमरी पाठशाला भवन	भनपोखरा	कार्य पूर्ण होकर १,००० रु० स्वीकृत अनुदान का भुगतान किया जा चुका है ।
१४	पेय जल डिग्गी ..	कोडार	कार्य पूर्ण होकर ६०० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है ।
१५	पेय जल नौला ..	कोटली	,, ,, ,, ३०० रु० के
१६	सामूहिक उद्यान ..	जू० हा० स्कूल, पैटना	,, ,, ,, ३०० रु० के
१७	सामूहिक उद्यान ..	तुषराड़	,, ,, ,, ५०० रु०
१८	गांधी चबूतरा ..	देवगुरू	,, ,, ,, ६० रु०
१९	मार्ग का जीर्णोद्धार ..	तुषराड़	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ३०० रु० के अनुदान का भुगतान किया जा चुका है ।
२०	मार्ग का जीर्णोद्धार ..	करायल	कार्य पूर्ण होकर १२५ रु० के स्वीकृत अनुदान का भुगतान किया जा चुका है ।
२१	मार्ग का जीर्णोद्धार ..	भद्रकोट	,, ,, ,, १२५ रु०
२२	सिंचाई की गूल ..	करायल	इस कार्य हेतु ३,००० रु० स्वीकृत है जिससे लगभग २,००० रु० हजार अग्रिम धन के रूप में दिया जा चुका है तथा शेष कार्य पूर्ण होने पर किया जावेगा ।
२३	सिंचाई की गूल ..	पुटपुड़ी	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत १,५०० रु० के अनुदान का भुगतान किया जा चुका है ।

क्रमांक	नाम योजना	नाम स्थान	अन्य विवरण
१	२	३	४
२४	बन विकास योजना . .	पनपोखरा	इस योजना हेतु १,००० रु० स्वीकृत है। काम चालू है।
२५	सामाजिक मिलन केन्द्र	तुषराड़	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ७०० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
२६	पेय जल गूल . .	पुटपुड़ी	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ७०० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
२७	बहुधन्धी भवन . .	ओखलकांड़ा	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ३,००० रु० के अनुदान का भुगतान किया जा चुका है।
२८	पेय जल नौला . .	रीखा कोट	,, ,, ,, ३,२० रु०
२९	पेय जल गूल . .	रीखाकोट	कार्यपूर्ण होकर ७०० रु० स्वीकृत अनुदान का भुगतान हो चुका है।
३०	भवन निर्माण . .	ओखलकांडा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	कार्य पूर्ण होकर १,५०० रु० स्वीकृत अनुदान के भुगतान किया जा चुका है।
३१	प्राइमरी पाठशाला भवन	कुलौरी	कार्य पूर्ण होकर ९०० रु० स्वीकृत अनुदान किया जा चुका है।
३२	प्रा० पाठशाला भवन	टांडा	१,५०० रु० स्वीकृत अनुदान किया जा चुका है।
३३	सिंचाई गूल व हौज निर्माण	रीखाकोट: सिहाली	,, ,, ,, ६४५ रु० के स्वीकृत अनुदान का भुगतान हो चुका है।
३४	पेय जल नौला . .	खन्स्यूं	,, ,, ,, २०० रु० के
३५	पेय जल डिग्गी . .	सुरंग	,, ,, ,, १०० रु० के
३६	सामूहिक उद्यान . .	ओखलकांडा उ० मा० विद्यालय	स्वीकृत अनुदान २,५०० रु० है तथा इसमें से आधे से अधिक की धनराशि दी जा चुकी है।
३७	पेय जल गूल . .	पुटपुड़ी	कार्य पूर्ण हो गया इस हेतु १,५०० रु० स्वीकृत है। जिसका अन्तिम भुगतान किया जा रहा है।
३८	पाइपलाइन . .	च्यूरी गाढ़	इस योजना हेतु ७५० रु० स्वीकृत है। कार्य चालू है।

पट्टी चौमेसी

१	पंचायत भवन . .	नाई	कार्य लगभग पूर्ण होने को है तथा इस हेतु १,००० रु० स्वीकृत है।

क्रमांक	नाम योजना	नाम स्थान	अन्य विवरण
१	२	३	४
२	प्राइमरी पाठशाला भवन	लिंगुरानी	कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है इस योजना के हेतु ५०० रु० अनुदान स्वीकृत है।
३	सामूहिक नरसरी ..	रतौड़ा : नाई	कार्य लगभग पूर्ण होने को है इस हेतु २५० रु० अनुदान स्वीकृत है ?
४	पेय जल नौला ..	छाता	कार्य चालू है इस हेतु २६२ रु० स्वीकृत है।
५	२ पेय जल नौले ..	थली	कार्य पूर्ण होकर ५७७ रु० के स्वीकृत अनुदान का भुगतान किया जा चुका है।
६	पेय जल डिग्गी ..	कोटला	कार्य चालू है। इस योजना हेतु ३७३ रु० स्वीकृत है।
७	प्राइमरी पाठशाला भवन	पतलिया	कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वीकृत अनुदान १,००० रु० अन्तिम भुगतान किया जा रहा है।
८	प्राइमरी पाठशाला भवन	नरतौला : नाई	इस हेतु २५० रु० स्वीकृत है कार्य चालू है।
९	प्राइमरी पाठशाला भवन	थली	स्वीकृत अनुदान ८०० रु० है तथा कार्य पूर्ण होने को है।
१०	प्रा० पाठशाला भवन का जीर्णोद्धार ..	नाई (नीलपहड़ी)	कार्य पूर्ण होने को है। इस हेतु ३०० रु० का अनुदान स्वीकृत है।
११	सामूहिक उद्यान पहाड़-पानी ..	पहाड़पानी	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत ७८ रु० के अनुदान का भुगतान किया जा चुका है।
१२	सामूहिक उद्यान पहाड़-पानी ..	नाई	इस हेतु २०० रु० स्वीकृत है जिसमें से ७५ रु० अग्रिम धन के रूप में दिये जा चुके हैं शेष का भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। कार्य समाप्त पर है।
१३	पेय जल डिग्गी ..	भुमका	कार्य प्रारम्भ है। इस हेतु ८०० रु० का अनुदान स्वीकृत है।
१४	पेय जल नौला निर्माण	सुनपातली	कार्य पूर्ण हो चुका है। इस हेतु २०० रु० स्वीकृत है। जिसका भुगतान किया जा रहा है।
१५	पहाड़पानी जोस्यूड़ा मार्ग ..	पहाड़पानी: जोस्यूड़ा	यह कार्य अभी चालू नहीं हुआ है।
१६	मार्ग निर्माण ..	दरमाने (गंगोलागाड़) नाई केड़ागांव	इस कार्य का सर्वे किया जाना है। तब कार्य प्रारम्भ होगा।

क्रमांक	नाम योजना	नाम स्थान	अन्य विवरण
१	२	३	४
१७	गांधी चबूतरा ..	नाई	कार्य पूर्ण हो कर ६० रु० के अनुदान का भुगतान किया जा चुका है।
१८	पेय जल डिग्गी ..	दरमाने	कार्य पूर्ण हो कर ६११ रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
१९	पाइप लाइन ..	महतौली	इस कार्य हेतु १०० रु० स्वीकृत था परन्तु कार्य प्रारम्भ न होने से रद्द किया गया।
२०	पेय जल नौला ..	मनाधेर	कार्य पूर्ण होकर ७०० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
२१	सामूहिक उद्यान ..	सेलालेख	कार्य पूर्ण हो कर ५०० रु० के स्वीकृत अनुदान का भुगतान हो चुका है।
२२	प्रा० पाठशाला भवन	भुमका	कार्य लगभग पूर्ण होने को है तथा स्वीकृत अनुदान ५०० रु० है।
२३	मार्ग निर्माण	चौरलेख : जो स्यूड़ा	कार्य पूर्ण होकर स्वीकृत अनुदान का भुगतान हो चुका है।
२४	मार्ग निर्माण ..	नाई कचिलाकोट	कार्य पूर्ण होने को है।
२५	वन विकास कार्य ..	मज्यूली	स्वीकृत अनुदान ५०० रु० है तथा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।
२६	,, ,, ,, ..	सेलालेख	,, ,, ,, ,, ,,
२७	,, ,, ,,	नोलपहाड़ी	स्वीकृत अनुदान १,००० रु० है परन्तु अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
२८	,, ,, ,, ..	थली	स्वीकृत अनुदान १,००० रु० है परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
२९	,, ,, ,, ..	लिंगुरानी	स्वीकृत अनुदान ७५० रु० है परन्तु कार्य प्रारम्भ है।
३०	पेय जल डिग्गी ..	अनर्पा	कार्य पूर्ण होकर ४०० रु० के स्वीकृत अनुदान का भुगतान हो चुका है।
३१	पेय जल डिग्गी ..	देवागांव	,, ,, ,, ३५२ रु०
३२	पेय जल डिग्गी ..	मनाधेर	,, ,, ,, ७७५ रु०
३३	पेय जल डिग्गी ..	घोड़ाइजर	कार्य पूर्ण होकर ७५४ रु० के स्वीकृत अनुदान का भुगतान हो चुका है।
३४	पेय जल गूल ..	भुमका	,, ,, ,, ,, ४०० रु०
		पट्टी मल्ली रौ	
१	पेय जल नौला ..	बलना	इस कार्य हेतु ५०० रु० स्वीकृत था परन्तु कार्य न प्रारम्भ होने से रद्द करना पड़ा।

क्रमांक	नाम योजना	नाम स्थान	अन्य विवरण
१	२	३	४
२	बहुधन्धी भवन ..	ढोलीगांव	कार्य पूर्ण होने को है। स्वीकृत अनुदान १,००० रु० का है।
३	पेय जल नौला ..	चमरच्यूड़ा	कार्य चालू है। स्वीकृत अनुदान २०० रु० है।
४	बहुधंधी भवन निर्माण	जोस्यूड़ा	स्वीकृत अनुदान ५०० रु० है परन्तु कार्य प्रारभ नहीं हुआ है।
५	टांडा पुल निर्माण ..	टांडा	,, ,, ,, ,, ,, ,,
६	पुल निर्माण ..	भौनरा	,, ,, ,, ,, ,, ,,
७	पेय जल नौला ..	सेमला ?	कार्य पूर्ण हो चुका है तथा स्वीकृत अनुदान २०० रु० है।
८	पेय जल गूल ..	मटियाल	कार्य पूर्ण हो कर २०० रु० के स्वीकृत अनुदान का भुगतान किया जा चुका है।
९	पेय जल गूल ..	भौनरा	,, ,, ,, १०० रु० ,,
१०	,, ,, ,, ..	जोस्यूड़ा	,, ,, ,, ५०० रु० ,,
११	,, ,, ,, ..	दिगोली	,, ,, ,, ४०० रु० ,,
१२	,, ,, ,, ..	तल्ला कांडा	,, ,, ,, ३०० रु० ,,
१३	मार्ग निर्माण ..	जोस्यूड़ा चिलाकोट	स्वीकृत अनुदान ३०० रु० है कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अनुदान का भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।
१४	पेय जल नौला निर्माण..	मजैना	कार्य पूर्ण हो कर स्वीकृत २०० रु० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
१५	पेय जल डिग्गी ..	मजैना	४०० रु० का स्वीकृत अनुदान का भुगतान कार्य पूर्ण होने पर किया जा चुका है।
१६	पाइप लाइन ..	कोटपाड़े	कर्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।
१७	ढोलीगांव में पेय जल डिग्गी ..	ढोलीगांव	४१० रु० का अनुदान स्वीकृत है परन्तु अभी कार्य चालू नहीं हुआ है।
१८	पाइप लाइन ..	महतोली	१०० रु० ,, ,, ,, ,,

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३३ पर)

आजमगढ़ जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में निम्नलिखित प्रमुख कार्य करने की योजना थी--

सिंचाई--१३ नलकूपों का लगाना, २२६ (मेसेनरी) कुओं का निर्माण, २०५ पक्के (मेसेनरी) कुओं की खुदाई (बोरिंग) और ६० परित्यक्त कुओं का सुधार।

कृषि--४ बीज गोदामों (सहकारी) की स्थापना, विभिन्न फसलों के ५४ हजार मन उन्नत बीजों (जिसमें से प्रमुख हैं--जौ १३.८ हजार मन, मटर १३.८ हजार मन और धान १७.६ हजार मन, तथा १०.८ हजार मन रासायनिक खादों (अमोनियम सल्फेट ६.६ हजार मन) का वितरण।

पशु पालन--लालगंज में एक नये पशु चिकित्सालय की स्थापना।

सहकारी आन्दोलन--अतिरिक्त ४०० ग्रामों में सहकारी समितियों के निर्माण के लिये सहकारी आन्दोलन का विस्तार तथा सहकारी समितियों द्वारा ४,७३,००० रु० के अल्पकाली और ५०,००० रु० के मध्यकालीन ऋणों का वितरण।

यातायात --१०.३ मील पक्की और १३८.५ मील कच्ची सड़कों का निर्माण तथा एक मील पक्की और १६८.८ मील कच्ची सड़कों का सुधार।

चिकित्सा और स्वास्थ्य--लालगंज में ४ नये मातृ तथा शिशु कल्याण केन्द्रों तथा मार्टिनगंज में एक नये अस्पताल की स्थापना: २९१ नये शुद्ध पेय जल के कुओं का निर्माण तथा ७६६ कुओं का सुधार।

शिक्षा--आजमगढ़ में एक नये ईट भट्टे की स्थापना, प्रतिवर्ष १० व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिये एक शिक्षण कक्षा योजना का आरम्भ , अविकसित तथा पिछड़े हुये क्षेत्रों के आद्योगिक विकास की योजना के अन्तर्गत ३ केन्द्रों का संगठन जिन में से प्रत्येक में १६ व्यक्ति प्रशिक्षित किये जा सकें।

परिगणित जातियों --तथा पिछड़े हुये वर्गों का कल्याण--१२ नये मकानों और नये पीने के कुओं का निर्माण और आर्थिक उत्थान के लिये २६ व्यक्तियों को अनुदान।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उतर पीछे पृष्ठ ३३९ पर)

विवरण "अ"

सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिए ऋण की राशियां जो राट्रीयप्रसार सेवा क्षेत्र केराना से सन् ५६–५७ में स्वीकृत की ग

क्रम-संख्या	ऋणपाने वाले का नाम	ऋण की राशि	कार्य जिस के लिये ऋण दिया गया
		रु० आ० पा०	
१	सर्वश्री सुल्तानसिंह पुत्र छज्जूसिंह निवासी भूरा	२५० ० ०	नये रहट के लिये
२	फरगूदीन पुत्र तुगंल निवासी गदराउ	२५० ० ०	,,
३	रीतसिंह पुत्र छज्जू सिंह निवासी एरठी ..	२०० ० ०	,,
४	मुखराम पुत्र वारुमल निवासी एरठी ..	२०० ० ०	,,
५	रामप्रसाद पुत्र न्यादर निवासी एरठी	२०० ० ०	,,
६	हरीराम पुत्र जहानसिंह निवासी टिटौली	२०० ० ०	,,
७	ईब्राहीम पुत्र नत्थवा निवासी तीतरवाड़ा	२०० ० ०	,,
८	झन्डूसिंह पुत्र हरनामसिंह निवासी तीतरवाड़ा	५०० ० ०	सिंचाई के पक्के कुए हेतु
९	धर्मसिंह पुत्र नत्थूसिंह निवासी टिटोली ..	५०० ० ०	,,
१०	हरवंस सिंह पुत्र मल्लूसिंह निवासी किशोरपुर	५०० ० ०	,,
११	अब्दुल्ला पुत्र सैनी निवासी किशोरपुर ..	५०० ० ०	,,
१२	तुगंल पुत्र राम निवासी अकबरपुर सुनेटी	५०० ० ०	,,
१३	टोनू पुत्र गंगाराम निवासी अकबरपुर सुनेटी	५०० ० ०	
१४	शेर जंग अलियास जगी पुत्र तेगू निवासी अकबरपुर सुनेटी	५०० ० ०	,,
	योग :	५,०००	

विवरण "ब"

राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र सेराना ।

२–१०–५६ से ३१–५–५७ तक दिये गये अनुदानों की सूची ।

क्रम संख्या	गांव का नाम	कार्य का व्यौरा	दिये गये अनुदान की राशि
१	भूरा ..	पंचायतघर स्कूल	अभी तक ३०० रु० दिये गये
२	जहानपुर ..	,,	अभी तक ९०० रु० दिये गये
३	पावंटीकलां	,,	२०० रु० दिये गये
४	मोहम्मदपुर राई ..	खड़ंजा पड़ंजा	८०० रु० दिये गये
५	कसेरवां कलां ..	,,	३१० रु० दिये गये
६	झाडखंडी ..	,,	३०० रु० दिये गये
७	एरठी ..	कूप निर्माण मरम्मत	२८१ रु० दिये गये
८	कसेरवां कलां ..	,,	१५४ रु० दिये गये
९	ऊचां गांव ..	खडंजा पड़ंजा ..	अभी तक २५० रु० दिये गये ।
१०	,,	,,	अभी तक २५० रु० दिये गये
११	छोटी मुडेंट ..	,,	४०० रु०

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४० पर)

तालिका

सघन विकास क्षेत्र पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर में वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के प्राविधान तथा व्यय का विवरण

क्रम-सं०	मद का नाम	प्राविधान	व्यय	शेष	शेष धनराशि का कारण	अन्य विवरण
		रु०	रु०	रु०		
१	खंड स्तर--					
	अधिकारियों का वेतन ..	५,०००	२,५३१ १५ ०	२,४६८ १ ०	प्रशिक्षित व्यक्तियों के	कुल शेष धन वर्ष
	कर्मचारियों का वेतन ..	३६,४००	१६,४६३ ११ ०	१९,९३६ ५ ०	अभाव के कारण कुछ	के अन्त में सर-
	भत्ता ..	१५,१००	१०,४३३ १५ ०	४,६६६ १ ०	स्थान रिक्त रखने पड़े	कार को समर्पित
	प्रासंगिक व्यय--				अथवा धनराशि वास्त-	कर दिया गया
	(क) आवर्तक ..	३,३००	२,९८८ ९ ०	३११ ७ ०	विक आवश्यकताओं से	
	(ख) अनावर्तक ..	८००	६५२ १५ ०	१४७ १ ०	अधिक सिद्ध हुई ।	
	योग ..	६०,६००	३३,०७१ १ ०	२७,५२८ १५ ०		
२	कृषि--					
	प्रासंगिक व्यय--					
	(क) आवर्तक ..	१,७००	२७९ १० ०	१,४२० ६ ०		
	(ख) अनावर्तक ..	८००	७९० १२ ०	९ ४ ०		
	अनुदान ..	१,५००	१,५०० ० ०	.. ..		
	योग ..	४,०००	२,५७० ६ ०	१,४२९ १० ०		

लोकसभा सभा

क्रम-संख्या	मद का नाम		प्राविधान	व्यय	शेष	शेष धनराशि का कारण	अन्य विवरण
३	पशुपालन—						
	कर्मचारियों का वेतन	..	५००	..	५०० ० ०		
	भत्ता	..	५००	..	५०० ० ०		
	प्रासंगिक व्यय—						
	(क) आवर्तक व्यय	..	२,१००	१,१७६ ८ ३	९२३ ७ ९	प्रशिक्षित व्यक्तियों के	
	(ख) अनावर्तक	..	१,२००	६३८ १ ३	५६१ १४ ९	अभाव के कारण कुछ	
	अनुदान	..	३००	३०० ० ०	..	स्थान रिक्त रखने पड़े।	
	योग	..	४,६००	२,११४ ९ ६	२,४८५ ६ ६		
४	सिंचाई—						
	अनुदान	..	५,०००	५,००० ० ०	..	इस वर्ष का प्राविधान पूरा खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग के गत वर्ष के डिपाजिट एकाउन्ट से ६६,९५९ रु० खर्च हुआ।	
	राजकीय सिंचाई-कार्य	..	१४०,०००	१४०,००० ० ०	..		
	योग	..	१४५,०००	१४५,००० ० ०	..		
५	जन स्वास्थ्य—						
	प्रसांगिक व्यय—						
	(क) आवर्त्तक	..	१,०००	९९८ ७ ३	१ ८ ९		

(ख) अनावर्त्तक	..	१,०००	९९९	५	०		०	११	०	धनराशि वास्तविक आव-	
अनुदान	..	४,०००	४,०००	०	०		..			श्यकताओं से अधिक सिद्ध हुई :	
योग	..	६,०००	५,९९७	१२	३		२	३	९		
६ मेडिकल—											
प्रासंगिक व्यय—											
(क) आवर्त्तक	..	१,०००	८८५	९	०		११४	७	०	,,	,,
(ख) अनावर्त्तक	..	१,५००	२९२	२	०		१,२०७	१४	०	,,	,,
योग	..	२,५००	१,१७७	११	०		१,३२२	५	०		
७ शिक्षा—											
कर्मचारियों का वेतन	..	५,५००	१,४३५	१२	०		४,०६४	४	०		
भत्ता	..	७,५००	१,६१८	७	०		५,८८१	९	०		
प्रासंगिक व्यय—											
(क) आवर्त्तक	..	१,५००	१,४२५	५	०		७४	११	०	धनराशि वास्तविक आव- श्यकताओं से अधिक सिद्ध हुई।	
(ख) अनावर्त्तक	..	१,०००	१,०००	०	०		..			,,	,,
अनुदान	..	३,०००	३,०००	०	०		..			,,	,,
योग	..	१८,५००	८,४७९	८	०		१०,०२०	८	०		

क्रम संख्या	मद का नाम		प्राविधान	व्यय	शेष	शेष धनराशि का कारण	अन्य विवरण
८	सामाजिक शिक्षा --						
	कर्मचारियों का वेतन	..	६००	७०६ १५ ०	१९३ १ ०	धनराशि वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक सिद्ध हुई	
	भत्ता	..	४००	३९६ १३ ०	३ ३ ०	,,	,,
	प्रासंगिक व्यय--					,,	,,
	(क) आवर्त्तक	..	६,०००	५,९९९ १३ ०	० ३ ०	,	,,
	(ख) अनावर्त्तक	..	५००	५०० ० ०	..	,,	,,
	योग	..	७,८००	७,६०३ ९ ०	१९६ ७ ०	,,	
९	यातायात--						
	प्रासंगिक व्यय--						
	(क) आवर्त्तक	..	२००	२०० ० ०	..		
	(ख) अनावर्त्तक	..	१,०००	..	१,००० ० ०		
	योग	..	१,२००	२०० ० ०	१,००० ० ०		
१०	कार्यालय तथा कर्मचारियों के भवन का निर्माण	..	२२,९००	२२,८७२ ० ०	२८ ० ०		

११	उद्योग धंधे--								
	कर्मचारियों का वेतन	..	६,१९२	४,९३०	०	०	१,२६२	०	०
	भत्ता	..	२,६४०	३,०२६	१४	०	३८६	१४	०
	प्रासंगिक व्यय--								
	(क) आवर्त्तक	..	१७,४४०	१५,२१६	३	३	२,२२३	१२	९
	(ख) अनावर्त्तक	..	..	..			..		
	अनुदान	..	५००	५००	०	०	..		
	योग	..	२६,७७२	२३,६७३	१	३	३,०९८	१४	९
१२	पीलोन--								
	(क) कृषि के लिए	..	१०,०००	१०,०००	०	०	..		
	(ख) पशुपालन के लिए	..	१०,०००	१०,०००	०	०	..		
	(ग) सिंचाई	..	१५,०००	११,१५०	०	०	३,८५०	०	०
	(घ) रिक्लेमेशन	..	५,०००	५,०००	०	०	..		
	(च) जन स्वास्थ्य	..	२,०००	..			२,०००	०	०
	(छ) उद्योग धंधे के लिए	..	२५,०००	१९,०००	०	०	६,०००	०	०
	योग	..	६७,०००	५५,१५०	०	०	११,८५०	०	०
	कुल योग	..	३,६६,८७२	३,०७,९०९	१०	०	५८,९६२	६	०

मांग न होने के कारण
,, ,,
,, ,,
,, ,,

नोट--यदि रु० ६६,९५९ जो सिंचाई विभाग द्वारा उनके गत वर्ष १९५५-५६ के डिपाजिट एकाउन्ट में से सिंचाई के कार्यों पर १९५६-५७ में व्यय हुए शामिल कर लिए जायं तो वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में कुल व्यय रु० ३,७४,८६८-१०-० हो जायगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४२ पर)

श्री राम सुन्दर पांडेय द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या ४१ से संबंधित सूची

वित्तीय वर्ष, १९५६–५७ में फीस माफी की पूर्ति के स्वीकृत धन का विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	स्वीकृत धन
		रु०
१	गाजीपुर	२,२५,०००
२	बस्ती	२,२५,०००
३	देवरिया	४,३६,०००
४	आजमगढ़	२,२५,०००
५	वाराणसी	२,७३,७६०
६	बलिया	२,००,०००
७	गोरखपुर	२,२७,००५
८	मेरठ	७५,०००
९	बुलन्दशहर	४५,०००
१०	मुजफ्फरनगर	३५,०००
११	सहारनपुर	३५,०००
१२	फर्रुखाबाद	४०,०००
१३	इलाहाबाद	२,०५,०००
१४	मिर्जापुर	५५,०००
१५	हमीरपुर	१५,०००
१६	बांदा	१५,०००
१७	अलीगढ़	१०,०००
१८	उन्नाव	३५,०००
	कुल योग ..	२३,७६,७६५

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४३ पर)

सूची

जिला नियोजन समिति द्वारा सड़कों के नव निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान की सूची:

१ ९५--

(क) (१) कप्तानगंज-महराजगंज रोड	२ मील	..	
(२) महनगर-कम्हारिया रोड	२ मील	३९,००० रु०	इस धन का आधा भाग Central Road fund (ordinary) Reserve व आधा प्रान्तीय सरकार की Self Help Grant से स्वीकृत हुआ है।
(३) मऊ-गोकुलपुरा रोड ..	२ मील		
(ख) (१) बरवरा रोड		३,५०० रु०	इन सड़कों के निर्माण के लिए अनुदान प्रान्तीय सकार की Self Help Grant से हुआ है।
(२) सुल्तानीपुर-गोकुलपुरा रोड		१,०८१ रु०	
(३) अहिरौला-बढ़हनपुर रोड		२०,००० रु०	

१९५५--

कोई सड़क नहीं बनी, न कोई धन स्वीकृत हुआ।

१९५६--

इस वर्ष निम्नलिखित सड़कों के निर्माण के लिए उनके आगे दिये गये अनुदान की स्वीकृति की गयी व उनके आगे लिखित धन का व्यय हुआ। यह अनुदान Sanctioned Works Grant से स्वीकृत हुआ।

क्रम संख्या	सड़क का नाम		धन जो जिला नियोजन समिति ने स्वीकृत किया	धन जो व्यय हुआ
			मील	रु०	रु०
१	फूलपुर दुर्वासा रोड ..	..	४	८,६००	५,००८
२	अम्बारी दिदारगंज रोड ..	..	६	१०,४००	..
३	खुरहट रानीपुर रोड ..	..	१	२,०००	..
४	सरसेना काझा रोड ..	..	३	७,२००	४,०००
५	कम्हरिया चन्डेसर रोड ..	..	३	७,२००	..
६	तरवा कम्हरिया रोड ..	..	४	६,६००	१,४००
७	मधुबन दुबारी रोड ..	..	२	४,८००	..
८	जीयनपुर बिलरिया रोड ..	..	६	१०,४००	३,०००
९	अजमतगढ़ अमिला रोड ..	..	४	६,६००	..
१०	लालगंज पल्हना रोड ..	..	५	१२,०००	इस सड़क का निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

१९५७--

कोई धन न स्वीकृत हुआ और न कोई सड़क बनी।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४९ पर)

श्री जगन्नाथ प्रसाद जी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६८ के उत्तर में वर्णित ग्रामों की सूची—

नाम ग्राम--

१--परसा
२--बरसोला
३--जंगल मटेरा
४--मडवा
५--पधनजहा
६--कबीरपुर
७--दुलामऊ
८--लुधौरी
९--चैहमलपुर
१०--ईसापुर
११--रायपुर मल्लापुर
१२--मंगापुर
१३--डुडको
१४--साधुवापुर
१५--जगदीशपुर
१६--सुजानपुर
१७--ओझपुरवा
१८--कैराकीपुरवा
१९--मिलिक
२०--रामलोक
२१--गैरही
२२--बैलागढ़ी
२३--दुरगापुर
२४--कौडारी रूप
२५--खनवापुर
२६--फतेपुर
२७--रोटिहा
२८--खडवामीतमऊ
२९--डाबर
३०--कुनहा
३१--सुजावलपुर
३२--गोपालापुर
३३--फूलपुर
३४--गंगोलिया
३५--छितुईपतीया
३६--मुन्डी
३७--गुलरिहा
३८--राजापुर मेमन
३९--जटपुरवा
४०--तहारा
४१--जोकरिहा
४२--गोपालापुर
४३--गुनहा
४४--रामनगर कलां
४५--बझेडा
४६--गौरा
४७--विवा
४८--जम्हौरा
४९--बेल्हा सिक्टिहा
५०--मूसपुर
५१--जंगल नं० ६
५२--जंगल नं० ७
५३--मझौरा
५४--शाहपुर
५५--मैनहा
५६--रोरिया
५७--बेल्होरा
५८--नोधन
५९--बेलवा
६०--पटना
६१--दुबेला
६२--मुडकुन्डा
६३--जमुनिया
६४--खानीपुर
६५--नौव्वापुर
६६--हिहुवाखुर्द
६७--रैहरिया कलां
६८--रैहरिया खुर्द

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५३ पर)

जिला बदायूं के बाढ़ पीड़ितों को दी हुई सहायता का विवरण

रु०

१--ग्रैचूयस रिलीफ २,६५५
२--तकावी ऐक्ट १२ .. .. .. ४७,३५५

निम्नांकित कपड़े सरकार की ओर से परगना रजपुरा में बाढ़ पीड़ितों को बांटे गये--

१--पाजामा ४४
२--ऊनी जरसी ४६
३--ऊनी कोट २२
४--दरी ४
५--ब्लाउज फौजी २६
६--ऊनी कमीज ३०७
७--कम्बल १०
८--कम्बल गांधी आश्रम ४०

इसके अतिरिक्त इस परगने में नाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें बाढ़ पीड़ितों को बांटी गयीं।

गुड़ ..	.. ..	४० मन १० सेर
नमक ..	.. ..	३४ मन २० सेर
मिट्टी का तेल	.. ..	साढ़े ६ टीन
चना ..	.. ..	६२ मन
मक्के का आंटा	.. ..	४ मन
पका हुआ खाना (पराठे)	.. ..	११२ मन
रोटी	.. ..	७२ मन
दियासलाई	.. ..	१०२ डिब्बी
पैलूड्रीन की गोलियां	.. ..	१,३०३

(ह०) जी० एस० डेविड,
जिलाधीश, बदायूं।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० ८३ एल० ए०--१६५७--७६६।